चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 15 सितंबर-28 सितंबर 2014 | संयुक्तांक | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

ज्वाइंट वेंचर के नाम पर एक और कोयला घोटाला

फोटो–प्रभात पाण्डेय

शशि शेखर

मान लीजिए, आप दावत देना चाहते हैं, उसके लिए राशन एवं अन्य आवश्यक सामान खरीद कर लाते हैं, बावर्ची को बुलाते हैं और उससे भोजन तैयार करने को कहते है. इस काम के बदले बावर्ची आपसे एक तयशुदा रकम लेता है. यह तो हुई एक आम कहानी. अब एक खास कहानी. मान लीजिए, बावर्ची आपसे कहे कि वह भोजन तैयार करने का मेहनताना तो लेगा ही, साथ ही तैयार भोजन का पचास फ़ीसद या उससे भी ज़्यादा हिस्सा अपने साथ ले जाएगा, तो जाहिर है कि आप ऐसी शर्त कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी बावर्ची को भोजन तैयार करने का मेहनताना तो दे सकता है, पर उसके साथ 50 फ़ीसद भोजन नहीं बांट सकता. लेकिन, एक लाख छियासी हज़ार करोड़ रुपये के कोयला घोटाले के बाद भी चल रहे एक और कोयला घोटाले में यही शर्तें लागू हैं. नतीजतन, कई राज्य सरकारें हज़ारों करोड़ रुपये का नुक़सान जानबूझ कर उठा रही हैं. वे ज्वाइंट वेंचर बनाकर निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं. यह पूरी कहानी समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ का. समझते हैं कि राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में अडानी और ज्वाइंट वेंचर के जरिये हज़ारों करोड़ रुपये के कोयले की लूट कैसे हो रही है.

सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की. केंद्र सरकार ने कई राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक आवंटित किए थे. उक्त आवंटन इसलिए किए गए थे, ताकि राज्य सरकारें लगभग मुफ़्त में मिले कोयले से सस्ती बिजली का उत्पादन करें और उससे आम आदमी को फ़ायदा मिल सके. लेकिन, इसके बिल्कुल उलट हो रहा है. राज्य सरकार यहां भी निजी कंपनियों के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकीं. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) को 2006 में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा मोरगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए परसा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया. सीएसपीजीसीएल ने अपने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की बैठक, जो जून 2008 में हुई थी, में एक फ़ैसला लिया. यह फ़ैसला था ज्वाइंट वेंचर (जेवी) बनाने का, ताकि आवंटित ब्लॉक से कोयले का खनन किया जा सके. फरवरी 2009 में कंपनी ने जेवी पार्टनर के लिए टेंडर निकाला. टेंडर की शर्तों के मुताबिक, जेवी पार्टनर वही हो सकता था, जो कोल इंडिया लिमिटेड या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोयले की क़ीमत से कम क़ीमत पर कोयला दे. एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड), एमएमटीसी (मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड) और एईएल (अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड) ने जेवी के लिए आवेदन किया. ग़ौरतलब है कि एसईसीएल एवं एमएमटीसी भारत सरकार की कंपनियां हैं और अडानी इंटरप्राइजेज एक निजी कंपनी है, जिसके मालिक गौतम अडानी हैं. अंत में 19 अक्टूबर, 2009 को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईल) को जेवी पार्टनर चुन लिया गया. अडानी ने सीआईएल एवं एसईसीएल के कोयले की क़ीमत से तीन प्रतिशत कम क़ीमत पर कोयला देने की बात कही थी.

अब असल कहानी इसके बाद शुरू होती है. जुलाई 2010 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के बीच एक ज्वाइंट वेंचर बना, जिसका नाम है, सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड. इस जेवी में सीएसपीजीसीएल के पास 51 फ़ीसद शेयर थे और एईएल के पास 40 फ़ीसद. आश्चर्य की बात यह है कि सीएसपीजीसीएल को कोल ब्लॉक मुफ़्त में मिला था, उसे केवल खनन करके कोयला बाहर निकालना था. जाहिर है, यह काम कोई भी खनन कंपनी खनन की क़ीमत लेकर कर सकती थी, लेकिन सीएसपीजीसीएल ने कोयले के बाज़ार भाव पर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड से समझौता करके ज्वाइंट वेंचर बनाया, साथ ही उसे 40 फ़ीसद शेयर भी दे दिए और अपना ही कोयला उसने अडानी से बाज़ार भाव से सिर्फ़ तीन फ़ीसद कम क़ीमत पर खरीदा. यानी अडानी को इस पूरे मामले में बिना कोल

(शेष पृष्ठ 2 पर)

2012 तक 1549.06 करोड़ रुपये का नुक़सान

पारसा कोल ब्लॉक में 172.30 मीट्रिक टन कोयला है. एसईसीएल ने एफ ग्रेड की क़ीमत 570 रुपये/टन, ई ग्रेड की क़ीमत 730 रुपये/टन और डी ग्रेड की क़ीमत 880 रुपये/टन निर्धारित की थी. यानी एफ ग्रेड की क़ीमत आधार बनती, तो डी ग्रेड के कोयले पर 310 रुपये/टन, ई ग्रेड के कोयले पर 160 रुपये/टन की बचत सरकार को होती, लेकिन कोल प्राइसिंग की शर्तें बदलने से सरकार को नुक़सान हुआ. दरअसल, टेंडर के प्राइस खोले जाने से पहले सीएसपीजीसीएल ने टेंडर के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें एईएल ने कहा कि निकाले जाने वाले कोयले की वास्तविक श्रेणी के आधार पर कोयला देने की क़ीमत तय हो. इससे हुआ यह कि एफ ग्रेड वाली शर्त बदल गई. चूंकि इस इलाके में डी और ई ग्रेड का कोयला ज़्यादा है और उसकी क़ीमत एफ ग्रेड से ज़्यादा होती है. अडानी को वास्तविक श्रेणी के कोयले का मूल्य मिला, न कि पहले की शर्त

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका संख्या 120/2012 पर सुनवाई करते हुए बीते 25 अगस्त को अपना फ़ैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच हुए सारे कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए. अपने 163 पेज के फ़ैसले में अदालत ने कहा है कि यह कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट के ख़िलाफ़ है कि केंद्र सरकार राज्य को कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दे. चौथी दुनिया से बात करते हुए एनर्जी एक्सपर्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल ब्लॉक आवंटन अवैध ठहरा दिए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ज्वाइंट वेंचर के नुक़सान

- अगर जेवी की ज़रूरत थी, तो यह कोयला निकालने वाली कंपनी के साथ होना चाहिए.
- समझौता खनन लागत पर होना चाहिए था, न कि बाज़ार भाव पर.
- कोल ब्लॉक मुफ़्त मिला, फिर भी सरकार ने बाज़ार भाव से सिर्फ़ तीन प्रतिशत कम क़ीमत पर अपना ही कोयला अडानी से खरीदा.
- जो मुनाफ़ा सरकार को होना चाहिए था, वह अडानी के खाते में चला गया.
- नतीजतन, सरकार को नुक़सान उठाना पड़ा और जनता को सस्ती बिजली भी नहीं मिली.

कब मिलेगा नक्सलियों को आत्म-समर्पण का लाभ? 05

न्याय की आस में धन्नीपुर 06

जैविक खेती से किसानों को मिली नई ज़िंदगी 07

साईं की महिमा 12

ज्वाइंट वेंचर के नाम पर एक और कोयला घोटाला

पृष्ठ एक का शेष

ब्लॉक मिले, सिर्फ़ खनन करने के काम से वह फ़ायदा मिला, जो राज्य सरकार मुफ्त में मिले कोल ब्लॉक से नहीं उठा सकी. जाहिर है, इस हिसाब से अगर सीएजी नुक़सान का अंदाजा लगाए, तो यह नुक़सान हज़ारों करोड़ का हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के ज्वाइंट वेंचर के पीछे राज्य सरकार की भूमिका क्या थी? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक बार जब टेंडर की शर्त में एफ ग्रेड कोयले की क़ीमत को आधार बना दिया गया, तब अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के कहने पर संशोधन क्यों किया गया? सीएजी ने बताया है कि सीएसपीजीसीएल को यह जानकारी थी कि उसके पास डी और ई ग्रेड कोयले की मात्रा अधिक है. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने जानबूझ कर, टेंडर में पहले बनाए गए एफ ग्रेड कोयले की क़ीमत (जो कम होती है) के आधार को अडानी के कहने पर बदल दिया. जाहिर है, इससे रमन सिंह सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है कि आख़िर किसके दबाव में रमन सिंह सरकार ने टेंडर के नियमों में फेरबदल किया?

अब जरा एक नज़र राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल, राज्य सरकार का एक उपक्रम) पर भी डालते हैं. छत्तीसगढ़ जैसा ही एक ज्वाइंट वेंचर राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड ने भी अडानी इंटरप्राइजेज के साथ किया है. इसकी भी कहानी बहुत हद तक छत्तीसगढ़ जैसी है. सर्वविदित है कि कोयला मंत्रालय राज्यों को सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए कोल ब्लॉक देता है. 2007 में कोयला मंत्रालय ने राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड को भी दो कोल ब्लॉक दिए थे, ये कोल ब्लॉक भी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं. छत्तीसगढ़ के हसदेव में दो कोल ब्लॉक–पारसा ईस्ट और केंटे बेसिन आरवीयूएनएल को आवंटित किए गए थे. आरवीयूएनएल ने भी बजाय सिर्फ़ खनन का काम कराने (खनन की क़ीमत देकर) के अडानी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया. अच्छा तो यह होता कि राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) खुद या किसी सरकारी एजेंसी से कोल माइनिंग का काम

कराता. मान लीजिए, यह भी संभव नहीं था, तो राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड यह काम किसी ऐसी निजी कंपनी से कराता, जिसे केवल खनन क़ीमत यानी माइनिंग चार्ज देना पड़ता.

जानकारी के मुताबिक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसके उलट, आरवीयूएनएल ने 2008 में अडानी इंटरप्राइजेज से समझौता किया और दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, जिसका नाम था, पारसा केंटे बेसिन कोलियरीज लिमिटेड. इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पारसा केंटे बेसिन कोलियरीज लिमिटेड (पीकेसीएल) के साथ माइनिंग के लिए एक समझौता किया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस ज्वाइंट वेंचर में 74 फ़ीसद हिस्सेदारी अडानी को मिली और 26 फ़ीसद हिस्सेदारी आरवीयूएनएल को. आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब कोल ब्लॉक आरवीयूएनएल को सस्ती बिजली बनाने के लिए लगभग मुफ्त मिले थे, तब ऐसे में 74 फ़ीसद शेयर अडानी को क्यों दे दिए गए? इस ज्वाइंट वेंचर के मुताबिक अडानी के हिस्से में भूमि अधिग्रहण, माइनिंग, कोल वाशरी प्लांट की स्थापना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन (सरगुजा रेल कॉरीडोर) बिछाने और कोल वाशरी रिजेक्ट्स का (निम्नस्तरीय कोयला) खुद के पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल करने की बात थी. इन दोनों कोल ब्लॉक की क्षमता 450 मिलियन टन है.

अब आप यह समझिए कि आख़िर कोयले की लूट का यह खेल कैसे खेला गया? जानकारी के मुताबिक, अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खनन का खर्च 250 रुपये प्रति टन आता है. अडानी माइनिंग इसे ज्वाइंट वेंचर पीकेसीएल को बेचती है 675 रुपये प्रति टन के हिसाब से. इसके बाद जेवी यही कोयला आरवीयूएनएल को प्रति टन 736 रुपये के हिसाब से बेचता है. यह बाज़ार मूल्य (कोल इंडिया के रेट) से 64 रुपये यानी 8 फ़ीसद कम है. यही 64 रुपया मुनाफ़ा है इस जेवी का. इस मुनाफ़े में से 74 फ़ीसद अडानी और 26 फ़ीसद आरवीयूएनएल का है. यानी आरवीयूएनएल के हिस्से में मुनाफ़ा आता है प्रति टन 16 रुप. दूसरी तरफ़ अगर आरवीयूएनएल खनन लागत के आधार पर कोयला लेती, तो उसे किसी भी खनन कंपनी को प्रति टन कोयले के लिए सिर्फ़ 250 रुपये प्रति टन देना पड़ता. यानी अभी खरीदे जा रहे कोयले की क़ीमत के मुकाबले 500 रुपये प्रति टन से अधिक का फ़ायदा होता. लेकिन, ज्वाइंट वेंचर की यही महिमा है कि आरवीयूएनएल अपना ही कोयला किसी और से 500 रुपये प्रति टन अधिक देकर खरीद रहा है.

जाहिर है, सरकार या सीएजी इस मसले पर अभी भी गंभीरता से नहीं सोच रही है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के इस खेल को लेकर सवाल तो उठते ही हैं. एक सबसे बड़ा सवाल है कि अडानी को किस आधार पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने क्रमशः 49 एवं 74 फ़ीसद शेयर दे दिए. लगभग मुफ्त में मिले कोल ब्लॉक के खनन के लिए (अगर यह तर्क मान लिया जाए कि राज्य सरकार खनन का काम करने में असमर्थ थी) अगर ज्वाइंट वेंचर की ज़रूरत थी, तो यह खनन लागत के आधार पर क्यों नहीं बनाया गया? जो मुनाफ़ा इन राज्य सरकारों को हो सकता था, वह किसी निजी कंपनी को क्यों दे दिया गया? ऐसे में यह ज़रूरी है कि सीएजी सभी राज्य सरकारों (जहां भी ऐसे ज्वाइंट वेंचर बने हैं) का पूरा ऑडिट करके वास्तविक नुक़सान की गणना करे और यह बताए कि अब तक कोयला लूट के इस नए तरीके से देश को कितने रुपये का नुक़सान हुआ है. सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या केंद्र सरकार लूट के इस नए और अनोखे तरीके की जांच अपनी ओर से पहल करके कराएगी या वह एक और सीएजी रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी? ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

2012 तक 1549.06 करोड़ रुपये का नुक़सान

पृष्ठ 1 का शेष

के मुताबिक सभी श्रेणी के कोयले के लिए एफ ग्रेड का मूल्य. सीएसपीजीसीएल ने अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के कहे अनुसार कोल माइनिंग शुल्क के भुगतान संबंधी शर्त में संशोधन कर दिया. इसके अनुसार जिस श्रेणी का कोयला निकाला जाएगा, उसी श्रेणी के कोयले की एसईसीएल द्वारा तय क़ीमत के आधार पर माइनिंग शुल्क दिया जाएगा. नतीजतन सीएजी के मुताबिक, राज्य सरकार को 1549.06 करोड़ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ा. हालांकि सीएजी की यह रिपोर्ट 2012 की है और जेवी के तहत यह खेल अभी तक चल रहा है. इस हिसाब से यह नुक़सान अब तक करीब पांच हज़ार करोड़ रुपये के आंकड़े को छू चुका होगा. ■

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

पृष्ठ 1 का शेष

हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा किए गए सारे ज्वाइंट वेंचर और एमडीओ कॉंट्रैक्ट भी अपने आप अवैध मान लिए जाएंगे. इस हिसाब से देखें, तो राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य सरकारों द्वारा निजी कंपनियों के साथ बनाए गए ज्वाइंट वेंचर्स को तत्काल प्रभाव से काम बंद कर देना चाहिए. साथ ही सीएजी को यह पूरा मामला इकट्ठा करके बताना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर के नाम पर इन निजी कंपनियों ने कितने हज़ार या कितने लाख करोड़ रुपये का चूना इस देश को लगाया है. यह इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अकेले छत्तीसगढ़ के लिए सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 तक छत्तीसगढ़ सरकार को क़रीब 1550 करोड़ रुपये का नुक़सान हो चुका है. ऐसे में अगर अन्य राज्यों में ज्वाइंट वेंचर के जरिये हुए नुक़सान को, वह भी आज की तारीख़ तक, जोड़ दिया जाए, तो नुक़सान का यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 28–29 (संयुक्तांक)
दिल्ली, 15 सितंबर–28 सितंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
बैंक कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर गुरुवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

अच्छे दिन खत्म

वर्ष 2002 से पंजाब के कई नौकरशाह अध्ययन अवकाश नीति (स्टडी लीव पॉलिसी) का उपयोग करके विदेश गए और वहां जाकर पैसे बनाए. उनमें से कुछ को तो कनाडा जैसे देशों में स्थायी निवासी का दर्जा भी मिल गया है. देर से ही सही पर सरकार को यह एहसास हो गया है कि कुछ लोगों ने अध्ययन अवकाश की आड़ में वहां अपने व्यावसायिक हितों को विकसित किया है. यह सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य के मुख्य सचिव सुरेश कौशल को इस संबंध में जांच करने निर्देश दिया है और जिन नौकरशाहों ने विदेशों में स्थायी निवासी या अप्रवासी दर्जा प्राप्त किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार राज्य के तकरीबन दो हजार बाबुओं ने शैक्षिक अवकाश लिया है. जाहिर तौर पर सरकार तब जागी है जब इन बाबूओं द्वारा हवाला के जरिए पैसे भारत भेजने की बातें विजिलेंस विभाग के सामने आई हैं. पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख सुरेश अरोरा के अनुसार सरकार अब इस घोटाले की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दृढ संकल्पित है. जाहिर है कि अच्छे दिन हमेशा नहीं बने रहते. ■

सुलह की ओर?

केरल के मुख्य सचिव ईके भारत भूषण और राज्य के आईएएस एसोसिएशन के बीच विवाद का जिक्र हमने पिछले महीने इस कॉलम में किया था. यह अब भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जाहिर तौर पर एसोसिएशन को भारत भूषण के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ बदले की भावना और अशिष्ट व्यवहार करने की कई शिकायतें मिली हैं. उनके खिलाफ लोगों की पदोन्नति रोकने की भी शिकायतें मिली हैं, इस वजह से वह अपने आईएएस सहयोगियों के बीच अलोकप्रिय मुख्य सचिव बन गए हैं. दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम के प्रयास विफल रहे हैं. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष के एम चंद्रशेखर के जरिए मध्यस्थता करवाने की कोशिश की लेकिन वह प्रयास असफल रहा. लेकिन इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वी सोमसुंदरन को मध्यस्थता के लिए लाया गया लेकिन उनकी केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव के रुप में नियुक्ति हो गई और उन्हें जाना पड़ा. लेकिन अब लग रहा है कि एसोसिएशन के दबाव का असर हुआ है और भूषण नरम पड़े हैं. वह इस मसले को सुलझाने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन क्या केरल के नौकरशाह इस विवाद का पटाक्षेप करेंगे? ■

नाफरमानी काम आई

यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारियों का एक वर्ग गैर आईएएस अधिकारियों से नाराज है. क्योंकि वो न सिर्फ बार–बार स्थानांतरण के आदेशों को धत्ता बता रहे हैं बल्कि अपने शक्तिशाली संपर्कों का उपयोग कर स्थानांतरण आदेशों को स्थगित भी करा रहे हैं. सवालों के घेरे में आए एक अधिकारी शिवाजी पंधारे का नागपुर के क्षेत्रीय बोर्ड विभाग में स्थानांतरण किया गया था लेकिन उन्होंने वहां पदभार संभालने से इंकार कर दिया और पुणे में बने रहने का फैसला किया. सूत्रों के अनुसार स्कूली शिक्षा के प्रमुख सचिव अश्विनी भिड़े ने पंढारे के नागपुर स्थानांतरण का आदेश दिया था क्योंकि वहां एक साल से ज्यादा वक्त से रिक्त पड़ा है. लेकिन बाबू का अड़ियल रवैया शिक्षा विभाग के ताकतवर अधिकारियों से भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ. साफ तौर पर विभाग ने इस मसले विद्रोही अधिकारी के साथ रस्साकशी नहीं करने का निर्णय लिया. कथित तौर पर अब उन्हें पुणे स्थित स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग(एससीईआरटी) में संयुक्त निदेशक का कार्यभार संभालने को कहा गया है. लेकिन उसने जिन अधिकारियों के आदेश की नाफरमानी की वो अभी भी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं. ■

महाराष्ट्र शासन

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

मिहिर भारत सरकार में शामिल

1993 बैच के आईएएस अधिकारी मिहिर कुमार संयुक्त सचिव के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए.

संजय आईजी विजिलेंस बने

1992 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अग्रवाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के रूप में मुख्यमंत्री-राजस्थान की सुरक्षा में नियुक्त किए गए हैं.

ओ. पी सिंह निदेशक बने

1983 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ओ. पी. सिंह को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

भट्नागर आईटीबीपी से जुड़े

1983 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आर.आर. भट्नागर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

पुष्पेंद्र इस्पात मंत्रालय से जुड़े

1999 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र राजपुत को इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है.

केशव संयुक्त सचिव नियुक्त

1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक को कश्मीर का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. पाठक वर्तमान में गृहमंत्रालय के अर्न्तगत स्वतंत्रता सेनानी विंग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं. ■

बिहार में सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा

ऐसे नटवरलालों ने किया शिक्षा का बंटाधार

नवीन चौहान

कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, वह देश का भविष्य बनाता है, उसे नई दिशा देता है, लेकिन बिहार में कुछ लोग फर्जी मार्कशीटों के बल पर पंचायत शिक्षक की नौकरी पाने में कामयाब हो गए हैं. ऐसा ही एक मामला चौथी दुनिया के सामने आया है, जिसमें हुए फर्जीवाड़े ने साबित कर दिया कि इंसान यदि बेईमानी पर उतर आए, तो व्यवस्था उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के धोकराहा का है, जहां राम लखन तिवारी नामक शख्स ने नौकरी पाने की आयु सीमा निकल जाने के बाद न केवल अपना नाम बदल कर राम जी तिवारी कर लिया, बल्कि अपनी जन्मतिथि भी बदल ली. इसके बाद हासिल किए गए दस्तावेजों की बदौलत वह पंचायत शिक्षक के पद पर आसीन हो गया. राम जी तिवारी ने फर्जी दस्तावेजों की ही बदौलत अपने बेटे, बेटी और बहू को भी पंचायत शिक्षक बनवा दिया. सभी दस्तावेज इतनी सफाई से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर किसी को शक नहीं होता कि वे वाकई नकली हैं.

शिकायतकर्ता निरंजन तिवारी

इस मामले में पहली शिकायत आरोपी राम लखन तिवारी के सगे भाई निरंजन तिवारी ने 2007 में की थी. सात साल से वह विभिन्न सरकारी महकमों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त से लेकर अदालत तक वह इंसाफ पाने की पुरजोर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली. पहले इस बिंदु पर छानबीन हुई कि राम लखन और राम जी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं या दो अलग-अलग व्यक्ति हैं. पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि की कि राम लखन तिवारी उर्फ राम जी तिवारी एक ही व्यक्ति है. इन पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2006 में की गई थी. 20 दिसंबर, 2007 को डीजीपी बिहार के आदेश पर राम जी तिवारी के घर पर पुलिस ने छापा मारा था. छापे के दौरान विभिन्न दस्तावेज जब्त करने के बाद राम जी तिवारी एवं उनके पुत्र रमेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों को 26 दिनों तक पुलिस रिमांड पर रहना पड़ा था. इसके बाद पुलिस ने जो केस डायरी पेश की, उसमें केवल टीचर्स ट्रेनिंग के दस्तावेजों की जांच की बात कही गई, लेकिन मध्यमा के दस्तावेजों की उसने चर्चा तक नहीं की. पुलिस ने कहा कि दस्तावेज सही हैं. बाद में सूचना का अधिकार क़ानून के जरिये हासिल जानकारी से खुलासा हुआ कि पुलिस ने गलत केस डायरी पेश की थी. जो दस्तावेज पुलिस ने सही बताए थे, वे फर्जी निकले. बावजूद इसके प्रशासन मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने में अक्षम सिद्ध हुआ.

राम जी पर अन्य लोगों को भी फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराने का आरोप है. राम लखन तिवारी उर्फ राम जी तिवारी पुत्र वीर तिवारी उर्फ कृष्णा तिवारी फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे प्रखंड चनपटिया के ग्राम खसुआड़ में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. राम लखन तिवारी ने वर्ष 1969-70 में मोतीलाल उच्च विद्यालय मझौली से मैट्रिक की परीक्षा पास की. इसके बाद वर्ष 1978 से 1985 के दौरान उन्होंने मझौली प्रखंड से राम लखन तिवारी के नाम से बेरोज़गारी भत्ता भी हासिल किया. वर्ष 1984 में राम लखन तिवारी ने अपना नाम राम जी तिवारी कर लिया और राज संस्कृत उच्च विद्यालय, बेतिया से मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उम्र काफी कम करके लिखाई गई. राम लखन तिवारी के मैट्रिक प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि 6-10-1951 अंकित है, जबकि राम जी तिवारी की जन्मतिथि 07-09-1962 अंकित है. एक ही व्यक्ति की दो जन्मतिथि कैसे हो सकती है? इसके बाद राम जी ने वाल्मीकि नगर (पश्चिमी चंपारण) से 1984-86 में टीचर्स ट्रेनिंग ली. इस दौरान उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता और टीचर्स ट्रेनिंग का स्टाइपेंड दोनों अलग-अलग नाम से प्राप्त किया. राम लखन तिवारी के पुत्र रमेश तिवारी प्रखंड नौतन, पुत्री रीमा देवी चनपटिया प्रखंड के मरमचा में और बहू कृपा तिवारी बेतिया प्रखंड के विद्यानगर में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और सभी के प्रमाण-पत्र फर्जी हैं. इस बात का खुलासा सूचना अधिकार क़ानून के जरिये प्राप्त दस्तावेज करते हैं. इनके अलावा सतेंद्र नारायण सिंह पुत्र रामाधार सिंह एवं प्रदीप कुमार पांडेय पुत्र जगत नारायण पांडेय नौतन, धर्मेंद्र दुबे पुत्र राजेंद्र दुबे चनपटिया में फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं.

अब उक्त लोगों के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आरटी आई के जरिये जानकारी मांगी गई, तो मालूम हुआ कि रमेश कुमार तिवारी ने 1988-90 में मिल्लत रांची से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की. उनके प्रमाण-पत्र में रोल कोड 1153, क्रमांक 07 दर्ज है, जो वर्ष 1994 के दस्तावेजों में है और

मो. मुर्तजा पिता इसहाक मिर्जा के नाम पर आवंटित है, जो उस वर्ष परीक्षा में अनुपस्थित रहा था. इसी तरह कृपा कुमारी ने भी छोटा नागपुर रांची से 1994 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं की. उनके प्रमाण-पत्र में रोल कोड 1101, क्रमांक 326 दर्ज है, जो फर्जी है, क्योंकि विद्यालय परीक्षा समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों में केवल 324 क्रमांक तक ही रिकॉर्ड उपलब्ध है. प्रदीप कुमार पांडेय पुत्र जगदीश नारायण पांडेय ने भी वर्ष 1994 में मिल्लत रांची से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की. उनके प्रमाण-पत्र में रोल कोड 1153, क्रमांक 21 दर्ज है, जबकि उस वर्ष के उपलब्ध रिकॉर्ड में इस कोड पर केवल क्रमांक 7 तक ही दर्ज है, क्रमांक 21 नहीं है. इसी तरह धर्मेंद्र कुमार दुबे के सत्र 1989-91 शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा प्रमाण- पत्र में रोल कोड 1105, क्रमांक 273 दर्ज है, जबकि समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों में क्रमांक 01 से 266 तक ही दर्ज है. ऐसे में 273 आया कहां से? आरोपी की पुत्री रीमा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से वर्ष 2002 में उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र दिया है, जिसमें अनुक्रमांक 4403 अंकित है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर मध्यमा परीक्षा-2002 में अनुक्रमांक 4403 आवंटित ही नहीं किया गया था.

आश्चर्य का विषय यह है कि सरकार ने इसे दो सगे भाइयों का आपसी विवाद माना. यहां तक कि पटना हाईकोर्ट ने भी इसे दो भाइयों के बीच का विवाद मानते हुए इस मामले की जांच के संबंध में निरंजन तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी थी. बिहार सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी क्रमांक 6382/2010 में हलफनामा दाखिल किया गया कि निरंजन तिवारी राम जी तिवारी को परेशान करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और राम लखन तिवारी एवं राम जी तिवारी एक ही व्यक्ति है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. आम तौर पर किसी भी सरकारी पद पर किसी शख्स की नियुक्ति होने पर उसके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालयों से कराई जाती है, लेकिन इन सभी मामलों में इस तरह की कोई जांच नहीं हुई. आवेदकों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र अधिकारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं. इसी वजह से अधिकारी भी जांच कराने का नियम नज़रअंदाज कर देते हैं. इन सभी मामलों से सीधे तौर पर जाहिर होता है कि सरकारी पदों पर बैठे लोग भी फर्जी मार्कशीटों के इस गोरखधंधे में शामिल हैं. हर कोई एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में है. जब आरटीआई के जरिये मिली जानकारी से प्रमाणित हो गया कि दस्तावेज फर्जी हैं, तो संबंधित अधिकारियों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक ओर कुछ लोग फर्जी मार्कशीट के जरिये सरकारी नौकरी पा रहे हैं, वहीं जो लोग वाकई नौकरी पाने के हक़दार हैं, वे बेरोज़गार बैठे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

> किसानों के शुभचिंतक दिखने वाले जिलाधिकारी विवेक के नेतृत्व में वह सब कुछ हुआ, जिसे करने में कई जिलाधिकारी नाकाम रहे. अब देखना यह है कि इन्हें क्या पुरस्कार मिलता है शासन की ओर से और क्या निर्णय करता है न्यायालय. 440 मेगावाट का यह प्लांट बरसों से टांडा में चल रहा है. इसमें 2 यूनिटें 660 प्लस 660 मेगावाट की और लगनी हैं, जिसके लिए 808 एकड़ ज़मीन की जरूरत है.

एनटीपीसी का विस्तारीकरण

क़ानून को ताख पर रखकर ज़मीनों का अधिग्रहण

राकेश कुमार यादव/लोकपति त्रिपाठी

अंबेडकर नगर में टांडा स्थित एनटीपीसी तापीय विद्युत गृह के विस्तारीकरण के चलते कई किसानों की ज़िंदगी अंधकार में डूब गई है. प्रशासनिक अमले ने सारे नियम-क़ानून ताख पर रखकर, मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और तय कोरम पूरा न हो पाने के बावजूद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंजाम दे दी. एक बड़ा टकराव टालने के लिए जिलाधिकारी विवेक ने साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना कर बरसों से लटका वह कार्य पूरा कराने में सफलता हासिल कर ली, जो वैधानिक व्यवस्था के दायरे में संभव नहीं था. एनटीपीसी प्रशासन बार-बार किसानों की मांगें मानता एवं नकारता रहा. अंतत: ऊपरी दबाव के चलते जिला प्रशासन वह सब कर गया, जिसे करने के लिए उसका जमीर शायद तैयार नहीं था.

किसानों के शुभचिंतक दिखने वाले जिलाधिकारी विवेक के नेतृत्व में वह सब कुछ हुआ, जिसे करने में कई जिलाधिकारी नाकाम रहे. अब देखना यह है कि इन्हें क्या पुरस्कार मिलता है शासन की ओर से और क्या निर्णय करता है न्यायालय. 440 मेगावाट का यह प्लांट बरसों से टांडा में चल रहा है. इसमें 2 यूनिटें 660 प्लस 660 मेगावाट की और लगनी हैं, जिसके लिए 808 एकड़ ज़मीन की जरूरत है. लगभग 7 वर्ष से इस दिशा में कार्य हो रहा है. इसके लिए आठ हज़ार करोड़ रुपये खर्च का लक्ष्य था, जो अब 12 हज़ार करोड़ रुपये हो गया है. उस समय 65 प्रतिशत किसानों की रजामंदी ज़रूरी थी, अब 80 प्रतिशत किसानों की रजामंदी ज़रूरी है. यूनिट विस्तार के लिए 808 एकड़ ज़मीन जुटाना स्थानीय किसानों के प्रबल विरोध के चलते संभव नहीं हो पा रहा था. लाख कोशिशों के बावजूद केवल 40 प्रतिशत किसानों ने अपनी ज़मीनों का बैनामा एनटीपीसी को किया. बाकी 60 प्रतिशत किसान अपने हक़ की पूरी क़ीमत और भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जिसे एनटीपीसी प्रशासन ने मंज़ूर नहीं किया. जिन 9 गांवों की ज़मीनें अधिग्रहीत करनी थीं, वे अति विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित थे, जिन्हें 18 जुलाई, 2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी पिंकी जोवेल ने अति विशिष्ट ग्राम में तब्दील कर दिया.

नतीजा यह हुआ कि आबादी की ज़मीनों की क़ीमत तो यथावत रही, लेकिन रिक्त और कृषि भूमि की क़ीमत सरकारी अभिलेखों में घट गई. काफी ज़मीनें असिंचित क्षेत्र घोषित कर दी गईं. इतना बड़ा और घातक खेल एक जिलाधिकारी ने किसानों के हितों के विपरीत कर दिया. इसके पीछे उक्त जिलाधिकारी का क्या हित रहा, यह भी जांच का विषय है. कृषि भूमि से ज़्यादा आबादी के दाम मिल रहे हैं, लेकिन 808 एकड़ ज़मीन में आबादी का हिस्सा महज 2 प्रतिशत है. इस तरह तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक झटके में करोड़ों का फ़ायदा एक औद्योगिक इकाई को करा दिया. ग़ौरतलब है कि 27 नवंबर, 2008 को धारा 4/17 अर्जेंसी में गजट कराई गई थी, लेकिन क़ीमत ज़्यादा होने के कारण ज़मीन की नवैयत ही जिलाधिकारी पिंकी जोवेल ने बदल दी. किसान अपनी लड़ाई न्यायालय तक ले गए. कई याचिकाएं दाखिल हुईं, जिनमें 99/12, 111/12, 46, 47, 48/13 और 101/2013 उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन हैं. प्रशासन की जबरदस्ती को देखते हुए बीते 3 सितंबर को न्यायालय ने पीड़ित किसानों के पक्ष में यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया, लेकिन प्रशासन ने अपना काम कर दिया. स्थगनादेश मिलने से पहले ही संगीनों के साये में अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई. आख़िर जिलाधिकारी ने किसानों के हितों की अनदेखी क्यों की? इसमें उनका व्यक्तिगत हित क्या था?

यदि एनटीपीसी प्रशासन ने समय पर किसानों की मांगें मान ली होतीं, तो लागत खर्च में चार हज़ार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी न होती और बिजली संकट से जूझ रहा उत्तर प्रदेश राहत की सांस ले रहा होता. किसानों ने विस्तारीकरण का विरोध कभी नहीं किया, बल्कि अपनी ज़मीनों की उचित क़ीमत की मांग की, जिसे एनटीपीसी मानने को तैयार नहीं हुआ. सात वर्ष पहले यदि किसानों को उनकी ज़मीनों की उचित क़ीमत, भविष्य की गारंटी और रहने को छत मिल जाती, तो 1760 मेगावाट बिजली का उत्पादन काफी पहले शुरू हो गया होता और लागत खर्च भी 8 हज़ार करोड़ के आसपास सिमट जाता. लेकिन बलिदान सिर्फ़ किसानों से लिया जाता है, बदले में उन्हें कुछ देने के लिए शासन- प्रशासन तैयार नहीं होता. औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की हरी-भरी फसलें रौंदी जाती हैं, उनके पेट की रोटी छीनी जाती है. चंद रुपये देकर उन्हें बंजारों की तरह जीने के लिए विवश किया जाता है. जब वह अपने हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्हें पीटा जाता है. हवा में गोलियां चलाई जाती हैं, मुकदमे लादे जाते हैं.

दरअसल, खेतों में तैयार फसलें ध्वस्त करके भूमि अधिग्रहण करने के बावत जिलाधिकारी विवेक ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और तीन महीने के लिए अभियान रोक दिया गया. लेकिन, इसी बीच एक सोची-समझी साजिश के तहत बीते 27 अगस्त को पुलिस ने कुछ किसानों को उनके घर से उठा लिया, बाकी किसान आंदोलित हो गए. उन्होंने सड़क जाम कर दी. पुलिस ने मौक़े पर पहुंच कर बल प्रयोग किया, तो जवाब में पत्थर चले. इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग के साथ किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया. अलीगंज थानाध्यक्ष वृजनंदन सिंह का सिर फट गया, नतीजा यह हुआ कि किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए. डर के चलते कई किसान घर छोड़कर भाग गए. मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस, पीएसी, सीमा सुरक्षाबल, रैपिड एक्शन फोर्स की कई बटालियनें गांवों में लगा दी जाती हैं. प्रशासन पुन: भूमि अधिग्रहण कार्रवाई शुरू करता है. यह सब अचानक नहीं घटता, बल्कि जानबूझ कर होता है. ऐसा लगता नहीं कि हम स्वतंत्र भारत में सांसें ले रहे हैं. अपने हक़ की लड़ाई लड़ने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई जाएं, एक औद्योगिक इकाई के लिए पूरा प्रशासन खड़ा दिखे और सरकार में बैठे मंत्री इन सारी घटनाओं से स्वयं को अलग कर लें! आख़िर यह सब क्या है? क़ानून कहता है कि कम से कम 80 प्रतिशत किसानों की रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन केवल 40 प्रतिशत किसानों की रजामंदी को आधार बनाकर सभी किसानों की ज़मीनें जबरन अधिग्रहीत कर ली गईं. इस एकपक्षीय कार्यवाही में शासन-प्रशासन की मंशा और निजी स्वार्थ सहज ही सामने आ जाते हैं.

आने वाले दिनों में यह विद्युत गृह जनपदवासियों एवं किसानों के लिए कितना लाभप्रद साबित होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इलाके की दिक्कतों में बेशुमार वृद्धि होगी. इससे निकलने वाली राख के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगी. पहले से लगभग चार गुना ज़्यादा राख निकलनी तय है. जाफराबाद जंक्शन से अकबरपुर रेलवे स्टेशन तक लगभग 90 किलोमीटर सिंगल रेलवे लाइन होने के कारण माल गाड़ियों का दबाव बढ़ेगा, यात्री गाड़ियां विलंबित होंगी. बताते हैं कि पहले एनटीपीसी परिसर स्थित गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे, तत्कालीन स्थानीय विधायक और पूर्व संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री लालजी वर्मा अपने लाव-लश्कर के साथ रहते थे. सबके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था एनटीपीसी करता था. अब स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री शंखलाल मांझी भी वही सारी सेवाएं लेते हैं, जबकि एनटीपीसी भारत सरकार का उपक्रम है. फिलहाल किसानों की किस्मत रौंदने का काम प्रशासन ने पूरा कर लिया है. अब न्यायालय क्या निर्णय देता है, यह देखना बाकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए दर-दर भटक रहे लोग

राजकुमार शर्मा

केदारनाथ आपदा के दौरान लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए उनके परिवारीजनों को एक वर्ष बाद भी दर-दर भटकना पड़ रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 3173 लापता लोगों में से अब तक केवल 2801 लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी हो सके हैं. मुख्यमंत्री हरीश रावत के तमाम प्रयासों और प्रशासन के होमवर्क के बाद भी एक बार फिर से कुछ मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने में पेंच फंस गया है. उत्तर प्रदेश के दो दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं, जिनके लापता होने की एफआईआर 30 जून, 2013 के बाद दर्ज की गई. इस संबंध में अब नए सिरे से मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. उत्तराखंड के भी क़रीब 41 लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र विभिन्न कारणों से जारी नहीं हो सके हैं. मेघालय एवं चंडीगढ़ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अब तक एक भी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है. राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर एवं असम ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र हासिल कर लिए. ग़ौरतलब है कि 16-17 जून, 2013 को राज्य में आई इस आपदा में सर्वाधिक नुक़सान केदारनाथ में हुआ था. केदारनाथ में ही हज़ारों श्रद्धालुओं-पर्यटकों की मौत हो गई थी.

आज भी मिलने वाले दर्जनों नरकंकाल इस बात की गवाही देते हैं कि इस दैवीय आपदा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए. सैकड़ों लोग, जो किसी तरह आपदा से बचकर जंगली पहाड़ियों पर चले गए थे, समय पर सरकारी मदद न मिलने के कारण दाना-पानी के अभाव में उन्होंने भी दम तोड़ दिया. देश के 22 राज्यों से आए हज़ारों श्रद्धालु-पर्यटक लापता हो गए थे. केंद्र की पहल पर राज्य सरकार द्वारा उक्त लापता लोगों को मृत मानते हुए उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे. इस बावत उत्तराखंड सरकार ने सभी संबंधित राज्यों से अपने लापता लोगों के संबंध में विशेष जांच कराकर भेजने को कहा था, ताकि परिवारीजनों को उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकें. इसके लिए 30 जून, 2013 तक उनके लापता होने की एफआईआर दर्ज कराए जाने के प्रमाण सहित अन्य कई बिंदु रखे गए थे. तय मानकों के अनुसार 22 राज्यों द्वारा भेजी गई जांच आख्या के आधार पर 2801 लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए. बावजूद इसके अब भी 372 परिवार ऐसे हैं, जो अपने परिवारीजनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र की बाट जोह रहे हैं, क्योंकि संबंधित राज्यों द्वारा जांच आख्या नहीं भेजी गई है. उत्तर प्रदेश के 193 परिवार आज भी अपने लापता परिवारीजनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं पा सके हैं. इनमें 29 मामले ऐसे हैं, जिनकी जांच आख्या तय मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी वजह 30 जून, 2013 के बाद एफआईआर दर्ज होना है. उत्तराखंड में भी 41 मामले ऐसे हैं, जिनमें मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने में दिक्कत आ रही है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. संबंधित राज्यों को जिन बिंदुओं पर जांच करके भेजनी है, उनमें लापता शख्स के संबंध में परिवार द्वारा 30 जून, 2013 तक दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति, लापता शख्स के उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में 16 जून से पूर्व यात्रा पर होने के साक्ष्य, अनुरक्षित डाटाबेस के आधार पर की गई जांच की पुष्टि का प्रमाण-पत्र आदि मूल राज्य के जांच अधिकारी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी को सौंपने थे. उत्तर प्रदेश के जिन 29 मामलों में पेंच फंसा है, उनमें बिजनौर के चार, गाजीपुर के पांच, बरेली के तीन, वाराणसी के सात, लालगंज (रायबरेली) के दो और गोरखपुर, सहारनपुर, बाराबंकी, नोएडा, धामपुर, जौनपुर एवं इलाहाबाद के एक-एक मामले शामिल हैं. ■

तीन सितंबर, 2014 तक जारी मृत्यु प्रमाण-पत्रों की स्थिति

राज्य	लापता लोगों की संख्या	जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र
उत्तराखंड	835	794
उत्तर प्रदेश	1150	957
मध्य प्रदेश	542	509
राजस्थान	508	509
दिल्ली	216	148
महाराष्ट्र	163	174
गुजरात	129	126
हरियाणा	112	107
आंध्र प्रदेश	86	63
बिहार	58	43
झारखंड	40	40
प. बंगाल	36	31
पंजाब	33	17
छत्तीसगढ़	29	22
ओडीशा	26	16
तमिलनाडु	14	17
मेघालय	06	00
चंडीगढ़	04	00
जम्मू-कश्मीर	03	04 (एक पूर्व लापता)
केरल	02	01
पुडुचेरी	01	01
असम	01	02 (एक पूर्व लापता)

feedback@chauthiduniya.com

बिहार की अस्मिता जगाने या बिहारवाद का गौरव बोध विकसित करने के नाम पर सूबे में और बाहर ऊंचे–ऊंचे हवाई महल खड़े किए जा रहे हैं. बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों–ग़ैर बिहारियों को यह ख़ूब आकर्षित करता है, लेकिन हकीकत बताने के लिए खेल दिवस समारोह में खेल मंत्री विनय बिहारी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों की स्थिति दयनीय है.

...क्योंकि श्रेयसी बिहार की बेटी है

सुकांत

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बहाने बिहार की सत्ता के नेपथ्य–नायकों, कुछ बड़े राजनेताओं एवं नौकरशाहों को बधाई! उन्हें अंतत: बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह की सुध आई तो!! 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर मांझी ने अफ़सोस जाहिर किया कि श्रेयसी सिंह की उपलब्धि के बारे में अफसरों ने उन्हें समय पर नहीं बताया. इसके लिए खेद जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार की इस बेटी को बधाई दी और उसे 11 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की. बांका के तत्कालीन सांसद एवं समाजवादी नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी ने हाल ही ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग की डबल ट्रैप स्पर्द्धा में रजत पदक जीता. इस उपलब्धि के एक महीने बाद उसे अपने राज्य के मुख्यमंत्री की बधाई मिली. राज्य के खेल मंत्री की बधाई भी कोई पखवाड़े भर बाद मिली थी और वह भी तब, जब श्रेयसी ने अपनी उपलब्धि के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षा का सरेआम उल्लेख किया और कहा कि बिहार सरकार ने बधाई देने तक की ज़रूरत नहीं समझी. खेल मंत्री विनय बिहारी ने इस बावत अपनी और सरकार की गलती स्वीकारी थी. हालांकि बिहार सरकार के जागने से पहले राज्य के कुछ खेल संगठन एवं अन्य लोग उसका सम्मान कर चुके थे.

श्रेयसी के साथ राज्य सरकार और राजनेताओं का यह सुलूक अप्रत्याशित नहीं है. बिहार के अनेक राजनेता एवं नौकरशाह खेल की राजनीति के माहिर हैं और राष्ट्रीय खेल संघों के पदाधिकारी हैं. वे खेल की राजनीति को अपनी तर्जनी से नचाने का दावा भी करते रहते हैं. इनमें कुछ बिहार की राजनीति के बड़े नाम हैं, तो कुछ राज्य की सत्ता में बड़ी ताकत बने बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी श्रेयसी के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं. उसे सम्मानित करना तो दूर, उसकी उपलब्धि को नोटिस तक नहीं किया गया. इनमें वे राजनेता एवं नौकरशाह भी शामिल हैं, जो खुद को कभी दिग्विजय सिंह का खास बताते घूमते थे और आज गिद्धौर, जमुई एवं बांका की धरती का प्रतिनिधित्व पटना से लेकर दिल्ली तक कर रहे हैं. लेकिन, किसी ने भी श्रेयसी को शुभकामना देने की ज़रूरत नहीं समझी.

श्रेयसी यदि झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु की होती, तो इस उपलब्धि के लिए उसे सिर–आंखों पर बैठा लिया जाता. सरकार उसे पूरा सम्मान देती, भविष्य की तैयारी

के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं. उसे केवल मुख्यमंत्री नहीं, समूची सरकार बधाई देती. उन दिनों बिहार विधान मंडल का अधिवेशन चल रहा था, सत्ता और विपक्ष कई मसलों पर मूंछ की लड़ाई लड़ रहे थे. मूंछ की लड़ाई में फंसे राजनेताओं को श्रेयसी की उपलब्धि दिखी ही नहीं. क्या अन्य राज्यों में ऐसा ही होता? विभाजित बिहार के खेल इतिहास का यह पहला मौक़ा है, जब सूबे की किसी संतान ने इसे ऐसी पहचान दी, लेकिन क्या सत्ताधारी, क्या उनके सहयोगी दल, क्या विपक्ष और क्या निर्दल, सभी एक जैसे निकले. नीतीश कुमार पिछले आठ सालों से (जबसे बिहार में उनकी सत्ता है) बिहारी अस्मिता जगा रहे हैं, बिहारीपन की भावना विकसित कर रहे हैं और बिहार गौरव को साकार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते. उनके इस बिहारवाद को राज्य के सार्वजनिक जीवन में सकारात्मकता की शुरुआत के तौर पर लिया गया. मौजूदा मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, खेल, युवा कार्य एवं कला–संस्कृति विभाग के सचिव चंचल कुमार, सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जैसे कई अधिकारी बिहार की नौकरशाही का नेतृत्व कर रहे हैं. ये और ऐसे कई लोग नीतीश कुमार के बिहारवाद के स्क्रिप्ट राइटर रहे. क्या इनमें से किसी

श्रेयसी यदि झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु की होती, तो इस उपलब्धि के लिए उसे सिर–आंखों पर बैठा लिया जाता. सरकार उसे पूरा सम्मान देती, भविष्य की तैयारी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं. उसे केवल मुख्यमंत्री नहीं, समूची सरकार बधाई देती. उन दिनों बिहार विधान मंडल का अधिवेशन चल रहा था, सत्ता और विपक्ष कई मसलों पर मूंछ की लड़ाई लड़ रहे थे.

को श्रेयसी की उपलब्धि नहीं दिखी? यह और भी विस्मयकारी है कि नीतीश कुमार के सत्ताधारी जनता दल (यू) के, संपूर्ण व्यवहारिक अर्थों में, सबसे बड़े नेता रहते ऐसा हुआ. क्या उन्हें भी अपना बिहारवाद याद नहीं रहा?

बिहार की अस्मिता जगाने या बिहारवाद का गौरव बोध विकसित करने के नाम पर सूबे में और बाहर ऊंचे–ऊंचे हवाई महल खड़े किए जा रहे हैं. बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों–गैर बिहारियों को यह खूब आकर्षित करता है, लेकिन हकीकत बताने के लिए खेल दिवस समारोह में खेल मंत्री विनय बिहारी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों की स्थिति दयनीय है. ज़िलों में स्थित स्टेडियम तालाब बन गए हैं और मेडलिस्ट जीविका के लिए रिक्शा चला रहे हैं. गांवों में खेल की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की योजना पायका राज्य में विगत चार सालों से स्थगित है, क्योंकि उसके खर्च का हिसाब भेजने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं. खिलाड़ियों को सरकार ने नौकरी देने का निर्णय किया है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते दिक्कत हो रही है. इस मसले पर बात करने के लिए मंत्री राज्य के प्रधान सचिव से समय मांग रहे हैं, लेकिन प्रधान सचिव के पास समय नहीं है. यह विनय बिहारी के भाषण का अंश है, इसमें कितना सही है, कितनी राजनीति है, यह तो वही बता सकते हैं.

सिर्फ़ खेल नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र में यही हाल है, जिससे वोट की राजनीति को ताकत नहीं मिलती. बिहार में दशकों से हिंदी एवं अहिंदी भाषी हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है. राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान और राजेंद्र माथुर पत्रकारिता सम्मान की बड़ी प्रतिष्ठा रही है, लेकिन अब इन सम्मानों का क्या हाल है, बताना बड़ा कठिन है. सरकार ने कमेटियां बना दी हैं, पर पिछले कई वर्षों से इसकी प्रक्रिया चल रही है. राजभाषा विभाग या बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के प्रतिष्ठित पुरस्कारों की बात कौन करे! सांस्कृतिक धरोहरों या विरासतों के संरक्षण की बात करना तो और भी बेमानी है. विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल के मोतिहारी स्थित जन्मस्थल को विकसित करने का काम आरंभ करने की घोषणा की गई है. जब अभिनव जयदेव, विद्यापति, भिखारी ठाकुर आदि की जन्मस्थली का संरक्षण–संवर्द्धन हमारी सत्ता नहीं कर सकती, तो शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, अनूप लाल मंडल एवं गोपाल सिंह नेपाली के गांवों को विकसित करने के बारे में सोचना बेमानी है. कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का गांव ही नहीं, घर और समाधि स्थल को भी अख़बारों के प्रयास के बावजूद नहीं बचाया गया. एनडीए सरकार ने उसे बागमती में डूब जाने दिया. वस्तुत: बिहार में राज्य की खेल नीति–संस्कृति नीति का अर्थ होता है, सत्ता पर काबिज राजनीति की खेल नीति–संस्कृति नीति. और, इसकी परिभाषा के दायरे में बहुत कुछ नहीं आता है, श्रेयसी सिंह भी शायद नहीं आती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आख़िर कब मिलेगा नक्सलियों को आत्म–समर्पण का लाभ?

वाल्मीकि कुमार

चार साल पूर्व दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सरकार द्वारा घोषित आत्म–समर्पण लाभ पाने के लिए दर–दर भटक रहे हैं. गौरतलब है कि भारत–नेपाल सीमा पर स्थित ज़िलों सीतामढ़ी एवं शिवहर के कई हिस्से नक्सलियों के गढ़ बन चुके हैं. यह अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से इन ज़िलों में नक्सली गतिविधियां थमी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके संगठन नेस्तनाबूद हो गए हैं. सुरक्षाबल की सक्रियता नक्सलियों को कुछ करने का मौक़ा नहीं दे रही है, लेकिन घात लगते ही संगठन से जुड़े लोग वारदातें अंजाम देने से परहेज नहीं कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, युवाओं के समूह में दो तरह के युवा शामिल हैं. पहले वे, जो अपने परिवार के जीवनयापन के लिए राज्य से बाहर नौकरी करते हैं और दूसरे वे, जो अपने गांव–ज़िले में जी–तोड़ मेहनत करके जीवनयापन करना चाहते हैं. जब उन्हें आधुनिक रहन–सहन के लायक कमाई नहीं हो पाती, तो वे समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं. इनमें अधिकांशत: अल्पशिक्षित हैं. बेहतर शिक्षा न मिलने के कारण ऐसे युवा समाज की मुख्य धारा से विमुख होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका लाभ समाज विरोधी ताकतों को सीधे तौर पर मिल जाता है.

समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त नक्सली संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रति सरकारी और प्रशासनिक नज़रिया गौर करने लायक है. बिहार में जब एनडीए–1 की सरकार बनी, तब नक्सल समस्या के निदान की दिशा में पहल की गई. नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में वापस आने की अपील करते हुए सरकार ने आत्म–समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए ज़मीन एवं आवास समेत अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की. ज़िला मुख्यालयों में योजना के बावत बड़े–बड़े पोस्टर लगाए गए. सरकार की घोषणा पर भरोसा करते हुए उत्तर बिहार के कई ज़िलों के नक्सलियों ने हथियार समेत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर स्वयं को समाज विरोधी कार्यों से अलग रखने का संकल्प लिया. इसी कड़ी में 23 मई, 2010 को दरभंगा के तत्कालीन एसपी एम आर नायक के समक्ष सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के तक़रीबन एक दर्जन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. इनमें गणेशी दास, रामबाबू दास, शिवजी दास, शिव नारायण दास, कल्लर दास, इंदल दास, देव नारायण दास, शंकर दास, मो. मुन्ना, मो. रेजाइल एवं राम मूर्ति मंडल आदि शामिल थे. 2012 में मुजफ्फरपुर ज़िला स्कूल मैदान में तत्कालीन एडीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, तिरहुत रेंज के डीआईजी सुशील मान सिंह खोपड़े एवं एसएसपी राजेश कुमार की मौजूदगी में सीतामढ़ी के नानपुर के दिनेश सहनी एवं नसीरुल नदाफ ने 25 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया था. इस कार्यक्रम में हथियार डालने वालों में मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के राम अनेक सहनी, प्रमोद सहनी, बलिराम सहनी, कैलाश राय, शंभू चौधरी, नागेश्वर साह, वीरेंद्र राय, कमलेश साह, नंदलाल महतो, नरेश साह, जगदेव सहनी, हर्षवर्द्धन पाठक एवं राम शिवेश सहनी, औराई थाना क्षेत्र के अरुण पासवान, सतन पासवान, मुकेश पासवान, शंकर पासवान, रंजीत साह, सुलोचन चौधरी, राम बिलास दास एवं सीताराम बैठा, दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सुशील ठाकुर एवं भुटन पासवान, सदर थाना क्षेत्र के होमू साह और पूर्वी चंपारण के शंभू पासवान शामिल थे. नक्सलियों ने 315 बोर की सात राइफलें, नाइन एमएम की एक पिस्टल, एक सिक्सर, 9 देसी कट्टे, दो पाइप कट्टे, 3 सेमी देसी राइफलें एवं 70 कारतूस भी पुलिस को सौंपे थे. उक्त नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराने में एमसीसी के पूर्व एरिया कमांडर अवधेश पासवान, राजकुमार

पितरिया एवं ललन पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी. तब नक्सलियों ने कहा था कि अगर सरकार पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराती है, तो उत्तर बिहार में नक्सलवाद का पतन तय है. कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी हरसंभव सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया था. जब सरकारी लाभ मिलने में विलंब हुआ, तब सीतामढ़ी के नानपुर निवासी समर्पणकारी नक्सली ज़िला प्रशासन के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचने लगे. गणेशी दास, रामबाबू दास, शिवजी दास, शिव नारायण दास, कल्लर दास, इंदल दास, देव नारायण दास, शंकर दास, मो. मुन्ना, मो. रेजाइल एवं राममूर्ति मंडल ने थक–हारकर पिछले साल एक संयुक्त आवेदन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, समाहर्त्ता सीतामढ़ी, अपर पुलिस महानिदेशक मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी, अनुमंडलाधिकारी पुपरी एवं थाना प्रभारी नानपुर को देकर सरकारी लाभ दिलाने की गुहार लगाई. कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों की गणेश परिक्रमा करने के बाद गणेशी दास, शिवजी दास, इंदल, देव नारायण दास एवं सेवक दास को मात्र इंदिरा आवास का लाभ नसीब हो सका. शेष को अब भी सरकारी लाभ पाने के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है. जबकि अन्य ज़िलों में आत्म–समर्पण कर चुके नक्सलियों को बहुत हद तक सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं. सरकार को चाहिए कि वह समय रहते घोषणा के अनुरूप आत्म–समर्पण कर चुके शेष नक्सलियों को भी हरसंभव लाभ दिलाए, जिससे समाज में अमन–चैन कायम रहे. ■

feedbacl@chauthiduniya.com

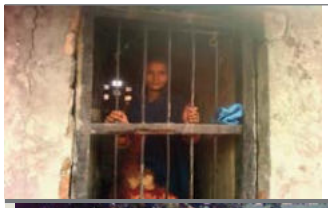

धन्नीपुर के लोगों ने तथाकथित मुख्य धारा के बाज़ार की वस्तुओं का उपभोग तो सीख लिया लेकिन एक नागरिक की हैसियत से अपने घर-गांव की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में आज भी अक्षम हैं. सवाल लाज़मी है कि नई सरकार के गठन के बाद जब बनारस को नई दृष्टि से देश और दुनिया में देखा जा रहा है और यहां के बुनकरों को बाज़ार से जोड़ने के लिए फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ने की मुहिम में ख़ुद प्रधानमंत्री जी जुटे हैं, तो ऐसे में धन्नीपुर और यहां के बुनकरों के चेहरों पर मायूसी क्यों छाई हुई है?

न्याय की आस में धन्नीपुर

धन्नीपुर आधुनिक भारत के उन गांवों में है, जहां शहरीकरण के कुछ प्रतिनिधि तत्व जैसे ईंट की दीवारों का होना और मिट्टी की कच्ची दीवारों का न होना आदि बताते हैं कि ऐसे गांव भी शहरीकरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं रहे हैं. बनारसी पान की लाली में फास्ट फूड, चिप्स/कुरकुरे और पेय पदार्थों का तड़का लगना भी इस बात का संकेतक है कि धन्नीपुर में शहरीकरण की प्रक्रिया अपनी रफ़्तार से जारी है. लेकिन इस प्रक्रिया को आईना दिखाने का काम किया है यहां रह रहे ज़्यातर लोगों के छत और छप्परों की सुराख़ों ने.

डॉ. वसीम अख़्तर

लगभग चार हज़ार आबादी वाला गांव धन्नीपुर आज अपनी किस्मत पर रो रहा है. धन्नीपुर गांव के नाम में नयी बस्ती जुड़ा होना इस बात का संकेतक है कि यह गांव कोई मामूली गांव नहीं है बल्कि गांवों की श्रृंखला में कोई मॉडल गांव है. लेकिन पीढ़ियों की एक बड़ी खेप निकल जाने और विकास के नए आयाम स्थापित होने वाले सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक मानकों के बावजूद धन्नीपुर नयी बस्ती में जिंदगी की गाड़ी अभी भी पुराने पहियों पर ही दौड़ रही है. मानव विकास के हर पैमाने पर इस गांव का सूचकांक ऐसी जगह जाकर ठहरा हुआ है, जहां से इसका स्वत: आगे बढ़ना और विकास की मुख्य धारा में शामिल होना काफी मुश्किल है. बनारस शहर से 11 किमी की दूरी पर स्थित लोहता बाज़ार के ठीक पीछे स्थित इस गांव का अस्तित्व वैसे तो किसी सुनियोजित योजना के तहत नहीं हुआ है. लेकिन पिछले लगभग 40 बरसों से इस गांव के गली-कूचे में आते-जाते लोगों के कदम इस बात के गवाह ज़रूर बने हैं कि धन्नीपुर भारत के उन उपेक्षित गांव-कस्बों में है, जहां से नगरों और महानगरों में होने वाले अरबों-खरबों रूपए के उद्योग और व्यापार के लिए सस्ते मानव श्रम की आपूर्ति होती रही है. लेकिन अथक परिश्रम करने और बनारसी होने की ऐतिहासिक पहचान होने के बाद भी यह गांव और यहां के निवासी शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक आजीविका के अवसरों से वंचित हैं. कम से कम निसार अंसारी, अब्दुल अहद, रुबीना, शहीदा, रिजवाना, अफसाना, तहज़ीब, अशफ़ाक़ और महमूद भाई जैसे धन्नीपुर के बुनकरों के जीवन का संघर्ष ऐसी ही कहानियां कहती हैं.

मौसम चाहे कोई हो, धन्नीपुर में दु:ख और परेशानी कम होती नहीं दिखती है. अगर मानसून की बात करें तो किसानों से लेकर देश के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की निगाह मानसूनी बारिश पर टिकी रहती है. क्योंकि समय से बारिश न सिर्फ फसल और पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है बल्कि इसका असर देश के सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रा स्फीति और महंगाई के सूचकांक पर भी पड़ता है. हमारे देश और समाज की विडंबना यह है कि बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए किसानों की आंखों में तैरते दु:ख का सागर हमारे राजनेताओं को नज़र आ जाता है, लेकिन कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हैंडलूम और पावरलूम किंचित कारणों से हाशिए पर चला जाता है. अफसोस की बात है कि दिन-रात मेहनत करने वाले बुनकरों का पहाड़ सा दु:ख किसी को नज़र नहीं आता है. गौरतलब है कि जिन बुनकरों की मेहनत से खड़ी होने वाली पूंजी देश के जीडीपी यानि सकल घरेलू इत्पाद का हिस्सा बनती है, इस जीडीपी से बनने वाली योजनाओं तक हाशिए के बुनकर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. निश्चित तौर पर धन्नीपुर के मास्टर बुनकर के पास आज की शब्दावली में बी.टेक., एम.टेक. जैसी महंगी डिग्रियां या आई.टी.आई. जैसा डिप्लोमा नहीं है. लेकिन इनका परंपरागत ज्ञान बहुत ही समृद्ध है. बुनकरों के परंपरागत ज्ञान को अगर मौजूदा दौर में प्रचलित तकनीकी शिक्षा के मानकों पर परखा जाए तो यह ज्ञान आज की प्रोफेशनल डिग्रियों से कहीं अधिक बड़ा है. ज़रूरत इस बात की है कि बुनकरों की लाजवाब कर देने वाली कला और परंपरागत ज्ञान का उचित सम्मान किया जाए. ऐसा सम्मान जो लक्षित योजनाओं की भूल-भूलैया से आज़ाद हो.

धन्नीपुर की हालत भारत के उन गांवों जैसी है जिनकी आवाज़ कई दशकों के बाद भी प्रदेश और देश की राजधानी तक नहीं पहुंच पायी है. शायद यही वजह है कि धन्नीपुर जैसे गांवों और बस्तियों में विकास का दीपक आज भी बुझा हुआ नज़र आता है. धन्नीपुर उन गांवों और बस्तियों का प्रतीक जान पड़ता है, जो तमाम वैज्ञानिक प्रगति और शहर के करीब होते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. धन्नीपुर वाराणसी जिला मुख्यालय से महज 11 किमी की दूरी पर स्थित है. समझा जा सकता है कि जिस गांव की आबाज 11 किमी की दूरी पर बैठे जिला और मंडल स्तर के मोहकमों और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी आवाज़ लगभग 318 किमी दूर स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी से लगभग 793 किमी दूर स्थित देश की राजधानी नई दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी. पिछले 40 सालों में निसार भाई जैसे बहुत से कारीगरों को बेवक्त ही मौत का शिकार होना पड़ा है. कल्याणकारी राज्य और विकसित होती अर्थव्यवस्था में ऐसी मौतें जन-धन का नुकसान हुआ करती हैं. निसार भाई जैसे बुनकर अभी ज़िन्दा हैं. कभी दस्तकार पहचान कार्ड तो कभी स्वास्थ्य बीमा कार्ड लेकर इधर-इधर मोहकमों का चक्कर भी लगाते हैं. लेकिन शासन और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती. जूं रेंगेगी भी क्यूं? धन्नीपुर जैसी बस्तियां और गांव या तो लक्षित योजनाओं की प्राथमिकता सूची में शामिल किए जा चुके हैं या फिर योजनाओं से पूरी तरह बेदखल हैं.

धन्नीपुर इन गांवों में शामिल है जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद कीचड़ और जल जमाव को गली-कूचे का आभूषण बनते देखा जा सकता है. ऐसे में गली की तंगी कम होने के बजाय लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में बढ़ जाती है. अगर कोई बीमार पड़ जाए और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत हो तो यह काम किसी कठिन चुनौती से कम नहीं होता. अगर मामला आपात स्वास्थ्य सुविधा जैसे प्रेगनेंसी का हो तब तो इन गलियों के कीचड़ से बाहर निकलते-निकलते महिला की मृत्यु भी मुमकिन है. कुछ ऐसा ही हाल शिक्षा का भी है. यहां आंगनबाड़ी केन्द्र (आई.सी.डी.एस.) तो है लेकिन बस्ती में किसी स्कूल की गैर मौजूदगी धन्नीपुर के बच्चों को बचपने में ही हाशिए तक पहुंचाने में उत्प्रेरक का काम करती है. गांव में समुदाय द्वारा संचालित मदरसा अवश्य है लेकिन जल-जमाव और कीचड़ वाली गलियों से मदरसों तक का रास्ता तय करना नन्हे-मुन्नों के लिए किसी बड़ी परेशानी को दावत देने से कम नहीं है. कहना पड़ रहा है कि धन्नीपुर के जो हालात हैं, उसमें यहां के बच्चों की ज़ुबान से नन्हा-मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं. जैसा गीत निकल ही नहीं सकता है. इसकी एक बड़ी वजह इन बच्चों का ताना-बाना की कारीगरी में मददगार के तौर पर काम करना है. कहना होगा कि अगर बच्चों को काम से अलग कर दिया जाए तो बहुत से घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो सकता है.

धन्नीपुर इन गांवों में शामिल है जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद कीचड़ और जल जमाव को गली-कूचे का आभूषण बनते देखा जा सकता है. ऐसे में गली की तंगी कम होने के बजाय लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में बढ़ जाती है. अगर कोई बीमार पड़ जाए और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत हो तो यह काम किसी कठिन चुनौती से कम नहीं होता.

धन्नीपुर आधुनिक भारत के उन गांवों में है, जहां शहरीकरण के कुछ प्रतिनिधि तत्व जैसे ईंट की दीवारों का होना और मिट्टी की कच्ची दीवारों का न होना आदि बताते हैं कि ऐसे गांव भी शहरीकरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं रहे हैं. बनारसी पान की लाली में फास्ट फूड, चिप्स/कुरकुरे और पेय पदार्थों का तड़का लगना भी इस बात का संकेतक है कि धन्नीपुर में शहरीकरण की प्रक्रिया अपनी रफ़्तार से जारी है. लेकिन इस प्रक्रिया को आईना दिखाने का काम किया है यहां रह रहे ज़्यातर लोगों के छत और छप्परों की सुराखों ने. निसार भाई के घर में इस बार पक्की ईंटों की चिनाई नज़र आई लेकिन टीन का शेड और शेड के नीचे पावरलूम मशीनों के साथ जिंदगी की जंग लड़ती बीवी, दो बेटियों और एक बेटे व बहू का संघर्ष भी नज़र आया. बारिश धन्नीपुर में सिर्फ गलियों को ही कीचड़मय नहीं बनाती है बल्कि टीन शेड और खपरैल के छप्परों से रिस-रिस कर नीचे गिरने वाली बारिश की बूंदे बुनकर मज़दूरों के हथकरघे की गति को भी स्थिर कर देती हैं. क्योंकि बुनकरों के समक्ष ताना-बाना और जकाट को बचाने की चुनौती होती है. काम रुकने से उत्पादन प्रभावित होता है. यह स्थिति किसानों की उस स्थिति से साम्य रखती है, जब अचानक से ओला पड़ जाए या सूखा पड़ जाए और मेहनत के दम पर खड़ी पूंजी बरबाद हो जाए. धन्नीपुर के बुनकरों की हालत कुछ ऐसी ही है. देखने पर ऐसा लगता है कि समय काटना ही एक काम रह गया है. यह विचार का विषय है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित हालिया फ्लिपकार्ट जैसी बाजार की युक्ति किस तरह इन बुनकरों की जिंदगी में उजाला लाएगी, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा तो बाज़ार में बेचने के लिए उत्पाद कहां से लाया जाएगा. माध्यम चाहे वाराणसी का चौक हो या फिर फ्लिपकार्ट सदृश ऑन लाइन मार्केटिंग की सुविधा हो.

उत्पादन को प्रभावित करने वाली एक वजह यह भी है कि थोड़ी देर की बारिश में धन्नीपुर की गलियां पानी से सराबोर हो जाती हैं. बहुत से घरों में पानी भर जाना आम बात है. इस आम बात में यह भी शामिल है कि इससे देर तक हथकरघों के ताने-बाने बुरी तरह प्रभावित होते हैं. काबिले जिक्र है कि हथकरघों को चलाने के लिए एक व्यक्ति को गड्ढे में पैर करके घंटों बैठना पड़ता है. कहने को धन्नीपुर की गलियों में सीवर भी बिछाया गया है, लेकिन महमूद भाई के शब्दों में यह काम कुछ गलियों में ही हुआ है. धन्नीपुर की अधिकतर गलियां आज भी जल-जमाव से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही हैं. कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि यहां लोग किसी तरह पेट पालते हुए किसी मसीहा की प्रतिक्षा में हैं जो फिल्म के एंग्रीयंग मैन नायक की तरह आए और उन्हें उनकी समस्या से निजात दिलाए. ऐसी बात सुनने में अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन ऐसी बातें राज्य और संविधान की असफलता की कहानियां भी उजागर करती हैं. क्योंकि हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां नागरिक के अधिकार और कर्तव्य लिखित तौर पर सुनिश्चित किए गए हैं.

धन्नीपुर के लोगों ने तथाकथित मुख्य धारा के बाज़ार की वस्तुओं का उपभोग तो सीख लिया लेकिन एक नागरिक की हैसियत से अपने घर-गांव की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में आज भी अक्षम हैं. सवाल लाज़मी है कि नई सरकार के गठन के बाद जब बनारस को नई दृष्टि से देश और दुनिया में देखा जा रहा है और यहां के बुनकरों को बाज़ार से जोड़ने के लिए फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ने की मुहिम में ख़ुद प्रधानमंत्री जी जुटे हैं, तो ऐसे में धन्नीपुर और यहां के बुनकरों के चेहरों पर मायूसी क्यों छाई हुई है? सवाल यह भी है कि दस्तकार पहचान कार्ड और स्वास्थ्य बीमा वाले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाले कार्ड कब इनके काम आएंगे? मुमकिन है ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ने की मुहिम में इनके पास फ्लिपकार्ट कम्पनी भी कार्ड मुहैया कराने की कोई योजना पर अमल करे और बुनकरों के पास कार्डों की संख्या एक अदद और बढ़ जाए. लेकिन सच्चाई यही है कि महज कार्डों की उपलब्धता से उनके जीवन में नया सवेरा नहीं होने वाला जब तक कि उनकी समस्याओं पर प्राथमिकता के अनुसार पुनर्विचार न किया जाए. ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी आधार पर नागरिकता के बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से वंचना भारतीय संविधान में समाहित कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ़ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोरारका फाउंडेशन ने जैविक खेती की शुरुआत राजस्थान के शेख़ावटी क्षेत्र से की. राजस्थान के लोग देश के दूसरे हिस्सों के मुक़ाबले पानी के अभाव से ज़्यादा दो-चार हैं. किसानों को अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो वे भला खेती कैसे करेंगे? इसीलिए मोराराका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक राजस्थान के किसानों को इस बात का प्रशिक्षण देने में जुटे हैं कि पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल कैसे उगाई जाए. वे वैज्ञानिक हाइड्रोपॉनिक तकनीक, ट्रे कल्टीवेशन एवं ड्रिप सिस्टम द्वारा किसानों को खेती करना सिखा रहे हैं, जिनमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है. मोराराका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती करने का तरीक़ा बताकर उन्हें नया जीवन दिया है.

जैविक खेती से किसानों को मिली नई ज़िंदगी

ऐसे दौर में जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान तरह-तरह की समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं, राजस्थान के शेख़ावटी क्षेत्र में मोराराका फाउंडेशन ने जैविक खेती के रूप में किसानों को नया जीवन और नई दिशा दी है. जैविक खेती के कारण यहां के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. अब देश के दूसरे क्षेत्रों के किसान भी मोराराका फाउंडेशन के संपर्क में आकर अपने यहां जैविक खेती करना चाहते हैं. मोराराका फाउंडेशन के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं सिक्किम जैसे राज्यों में भी जैविक खेती का आग़ाज़ हो चुका है. यही नहीं, बहुत से शिक्षित युवा भी अब जैविक खेती में अपना भविष्य तलाश करने लगे हैं.

डॉ. क़मर तबरेज़

किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वे अनाज, सब्ज़ियां एवं फल पैदा करके दुनिया की एक बड़ी आबादी का पेट भरते हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारें जिस तरह किसानों की अनदेखी कर रही हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में उन सभी इंसानों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, जो किसानों द्वारा पैदा किए गए अनाज पर निर्भर हैं. सरकार जिस तरह कृषि भूमि को बर्बाद करने पर तुली है, जबरन उसे औने-पौने दामों में खरीद कर उद्योगपतियों को दे रही है, उससे आने वाले दिनों में कृषि भूमि का अकाल पड़ सकता है. बाज़ार में प्रतिदिन नई-नई केमिकल खादें आ रही हैं और किसान उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे भोजन में ज़हरीले तत्वों की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम विभिन्न बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है. इन केमिकलों के बड़ी मात्रा में प्रयोग से ज़मीन की उर्वरता भी कम होने लगी है. ज़ाहिर है, एक किसान जिसका जीवनयापन उसके खेतों पर ही निर्भर होता है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सोना उगलने वाली ज़मीन एक दिन बंजर हो जाए. ऐसे में मोराराका फाउंडेशन ने जब देश के किसानों के सामने जैविक खेती का विकल्प पेश किया, तो उनके निराश चेहरे पर मुस्कान बिखर गई.

मोराराका फाउंडेशन ने जैविक खेती की शुरुआत राजस्थान के शेख़ावटी क्षेत्र से की. राजस्थान के लोग देश के दूसरे हिस्सों के मुक़ाबले पानी के अभाव से ज़्यादा दो-चार हैं. किसानों को अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो वे भला खेती कैसे करेंगे? इसीलिए मोराराका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक राजस्थान के किसानों को इस बात का प्रशिक्षण देने में जुटे हैं कि पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल कैसे उगाई जाए. वे वैज्ञानिक हाइड्रोपॉनिक तकनीक, ट्रे कल्टीवेशन एवं ड्रिप सिस्टम द्वारा किसानों को खेती करना सिखा रहे हैं, जिनमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है. मोराराका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती करने का तरीक़ा बताकर उन्हें नया जीवन दिया है. वास्तव में किसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनके खेत में अधिक से अधिक अनाज पैदा हो और ज़मीन की उर्वरता पर भी उसका कोई असर न पड़े. रासायनिक खेती का सबसे बड़ा नुक़सान यही था कि कुछ समय तक पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन ज़मीन की उर्वरता तेज़ी से घटने लगती थी, लेकिन अब जैविक खेती के ज़रिये किसानों को इस परेशानी से छुटकारा मिल चुका है. मोराराका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक किसानों को सबसे पहले यही बताते हैं कि वे अपने खेतों पर देसी तरीकों से खाद कैसे तैयार करें. इसमें वर्मी कंपोस्ट, हर्बल खाद, हर्बल स्प्रे, गड्ढा खाद और जीव अमृत की बहुत बड़ी भूमिका होती है. 30 वर्षीय संजय कुमार का संबंध राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की नवलगढ़ तहसील के बलवंतपुरा गांव से है. घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए संजय को 1998 में दसवीं कक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उनके पास 3 बीघा ज़मीन है, लिहाज़ा वह रोज़गार की तलाश करने के साथ-साथ काम भी करने लगे. इसी दौरान उनकी दोस्ती प्रेम शर्मा से हुई, जिन्होंने संजय को जैविक खेती के बारे में बताया. प्रेम शर्मा ने 2012 में जयपुर स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जेट की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली और दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल गया. प्रेम शर्मा ने 2013 में 82 प्रतिशत अंकों के साथ आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्हें एचसीएल में नौकरी भी मिली, लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने घर रहकर कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा रखते थे. प्रेम शर्मा ने संजय कुमार के साथ मिलकर 2008 में मोराराका फाउंडेशन से संपर्क किया और उससे जुड़े वैज्ञानिकों के सुझाव पर अमल करते हुए अपने खेतों में पेड़-पौधों, सब्ज़ियों एवं फूलों की एक नर्सरी बनाई. वर्ष 2011 में दोनों ने कड़ी मेहनत से चार क्यारियों में टमाटर, मिर्च, बैंगन एवं फूलों के हज़ारों पौधे तैयार किए. इन सब्ज़ियों एवं फूलों के बीज तैयार करने में 5,000 रुपये की लागत आई. शुरू में उन्हें अपने पौधे और बीज बेचने में काफ़ी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने जैसे-तैसे करके 25 किसानों को उक्त पौधे 21,000 रुपये में बेच दिए. दोनों में साहस एवं विश्वास पैदा हुआ और उन्होंने यह काम आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया. 2012 में मोराराका फाउंडेशन द्वारा दोनों को एक नई तकनीक का ज्ञान हुआ, जिसके तहत उन्होंने हर्बल स्प्रे, वर्मी कंपोस्ट, एनएसडीएल कंपोस्ट और जीव अमृत बनाने के बारे में सीखा, ताकि पौधों में लगने वाले कीड़ों से छुटकारा मिल सके. इस तकनीक पर अमल करते हुए उन्होंने अगली बार 10 क्यारियों में पौधे तैयार किए, जिसमें 10,000 रुपये की लागत आई और कुल आमदनी हुई 55,000 रुपये. इतना अधिक फ़ायदा होता देख उनका साहस और बढ़ गया. 2013 में उन्होंने क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी, जिसमें 30,000 रुपये की लागत आई और आमदनी हुई 1,20,000 रुपये. आज आलम यह है कि क्षेत्र के अधिकतर किसान प्रेम एवं संजय की नर्सरी से पौधे ख़रीदते हैं और उन्हें अपने खेतों में लगाकर अधिक से अधिक लाभ हासिल करते हैं. जैविक खेती करने वाले दूसरे किसान हैं मदन सिंह, जो झांझड़ियों की धानी, नवलगढ़ के रहने वाले हैं. छोटी उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की वजह से उन्हें पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई रोकनी पड़ी. उन्होंने खेती करने का हुनर शुरू में अपनी मां से सीखा. फिर मोराराका फाउंडेशन के संपर्क में आने के बाद जैविक पद्धति से खेती करने लगे. मोराराका फाउंडेशन से उन्होंने मूल रूप से गड्ढा खाद, केंचुआ खाद, हर्बल स्प्रे एवं जीव अमृत बनाना सीखा. इस समय मदन सिंह अपने क्षेत्र में बाजरे की खेती करने वाले सबसे कामयाब किसान हैं. उन्होंने जैविक खेती के ज़रिये एक नई तलाश की. दरअसल, मदन सिंह के पास जानवरों को खिलाने के लिए चारे की ज़बरदस्त कमी थी. इस सिलसिले में जब उन्होंने अपने दोस्त प्रभु दयाल से बात की, तो पता चला कि गुजरात के वड़ोदरा में हरे चारे के लिए बाजरे की एक नई किस्म उगाई जाती है. अब सवाल उठा कि उसे अपने खेतों में कैसे लगाया जाए? इसका जवाब तलाशने के लिए जब उन्होंने मोराराका फाउंडेशन से संपर्क किया, तो उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया. अब वह अपने एक बीघा खेत पर एक साल में 350 क्विंटल बाजरे के रूप में हरा चारा पैदा कर लेते हैं, जिससे उनके 5-6 जानवरों के चारे की व्यवस्था आसानी से हो जाती है.

तीसरे किसान हैं बारवा, नवलगढ़ के शिवनाथ जांगेड़. शिवनाथ जब बीए प्रथम वर्ष में थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी. अपने और परिवार के पालन-पोषण के लिए उन्होंने 2011 से नियमित रूप से खेती शुरू की और अपनी 20 बीघा ज़मीन पर पेड़-पौधे लगाने लगे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पौधों को पानी देने के लिए खेत में न तो कुआं था और न बिजली का कनेक्शन. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मोराराका फाउंडेशन के वैज्ञानिकों से संपर्क किया और फिर उनके सुझाव पर अपने खेतों में सरफल (जिसे स्थानीय भाषा में बेल कहते हैं) के 600 पौधे लगाए. शुरू में वह अपने परिवार के सदस्यों की मदद से पौधों में मटकों यानी घड़ों से पानी डालते थे, लेकिन एक साल बाद उन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन से घर के नए कुएं में 3 एचपी की मोटर लगवाई और फिर मोराराका फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन के तहत ड्रिप सिस्टम लगवाया. अगस्त 2014 में उन्होंने सोलर ऊर्जा पंप भी लगवाया है, जिससे बेल के पौधों को पानी देने में काफी आसानी होती है. शिवनाथ जांगेड़ को उम्मीद है कि बेल के 600 पौधों से उन्हें 1000 क्विंटल की पैदावार मिल जाएगी. इस प्रकार वह जैविक खेती की मदद से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

चौथे किसान हैं प्रहलाद सिंह शेख़ावत, जो शेख़ावतों की धानी, नवलगढ़ के रहने वाले हैं. उनके पास 60 बीघा ज़मीन है. प्रहलाद सिंह के पिता राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनका ख्वाब था कि उनके खेतों में कभी भी रासायनिक खादों एवं दवाओं का प्रयोग न हो. लिहाज़ा प्रहलाद सिंह ने अपने पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए ठान लिया कि पैदावार चाहे कितनी कम हो जाए, वह प्राकृतिक रूप से ही खेती करेंगे. शुरू में समस्या हुई, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से खेती करना नहीं जानते थे. इस बावत उन्होंने 2007 में मोराराका फाउंडेशन से संपर्क किया और फिर जैविक पद्धति से खेती करने का प्रशिक्षण लिया. मोराराका फाउंडेशन द्वारा बताई गई तकनीक पर भरोसा होने के बाद प्रहलाद सिंह ने फाउंडेशन और राज्य के कृषि विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद 2010 में उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन पर मिनि स्प्रिंकर लगवाए, जिससे कृषि कार्य में लगने वाली मज़दूरी और समय की बचत हुई. प्रहलाद सिंह अधिकतर प्याज़ की खेती करते थे, लेकिन फौरन बाज़ार में ले जाकर बेचने से उन्हें उसकी उचित क़ीमत नहीं मिल पाती थी. मोराराका फाउंडेशन ने उन्हें बताया कि वह अपने यहां एक गोदाम बनाएं, जहां प्याज़ का भंडारण करें और फिर बाद में सही क़ीमत मिलने पर उसे बाज़ार में बेचें. प्रहलाद सिंह ने ऐसा ही किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब उन्हें प्याज़ बेचने से 8-10 गुना अधिक मुनाफ़ा होने लगा. प्रहलाद सिंह प्याज़ के अलावा गेहूं और मूंगफली की खेती को भी महत्व देते हैं. वह अपनी गेहूं की फसल मोराराका फाउंडेशन को ही बेच देते हैं, जहां उन्हें बाज़ार से अधिक क़ीमत मिल जाती है और उनका अनाज आसानी से बिक भी जाता है.

इस प्रकार मोराराका फाउंडेशन ने एक-दो नहीं, बल्कि हज़ारों किसानों का जीवन ख़ुशहाल बनाया, जो जैविक खेती करके न केवल अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, बल्कि अपने गांव, समाज एवं देश के दूसरे लोगों को भी साफ़-सुथरा अनाज उपलब्ध करा रहे हैं. उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से पैदा किए गए अनाज को लोकप्रियता इसलिए मिल रही है, क्योंकि उनसे लोग बीमार नहीं होते, बल्कि स्वस्थ होते हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश के अन्य किसान भी मोराराका फाउंडेशन से जुड़कर जैविक खेती की यह नई तकनीक अपनाकर अपने खेतों को बंजर होने से बचाएंगे और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे. ■

tabrez@chauthiduniya.com

सभी फोटो- प्रभात पाण्डेय

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

संपादकीय

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारत : एक बाज़ार या एक राष्ट्र?

पिछली सरकार ने कॉरपोरेट को बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था में कार्य करने की अनुमति दे दी और सोचा कि ग़रीबों की मदद के लिए मनरेगा और खाद्य सुरक्षा क़ानून बना देने से काम चल जाएगा. मानो, वे समाज के समाजवादी पैटर्न पर वापस जा रहे हैं, जहां अमीर सामान्य तरीके से अपना कारोबार चलाता है और ग़रीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है. अब नई सरकार और प्रधानमंत्री की उपलब्धियां क्या हैं, हमें नहीं मालूम. क्या वह मनरेगा को चलाएंगे या बंद करेंगे, नहीं मालूम. खाद्य सुरक्षा क़ानून का क्या होगा, नहीं मालूम.

नई सरकार ने सौ से अधिक दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन आम नागरिक अभी भी वास्तव में नहीं जानता है कि आख़िर हो क्या रहा है. कुछ संकेत ज़रूर आए हैं कि प्रधानमंत्री ने एक छोटा-सा कैबिनेट (क्लस्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज) बनाया है, जो तीव्र गति से मंजूरी देने का काम कर रहा है, पर्यावरण मंजूरी आदि को आसान बनाया जा रहा है. लेकिन, हम यह नहीं जानते कि ज़मीन पर यह काम कैसे होगा? पूरी कार्य प्रणाली काफी गोपनीय बनी हुई है. पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं हुआ. यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री से मिला, कौन नहीं मिला. समाचार-पत्रों में कोई ख़बर ही नहीं आ रही है. हालांकि यह भी सच है कि देश के बहुत सारे उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, लेकिन पिछली सरकारों के विपरीत ये मुलाकातें काफी गोपनीय हैं. पहले की तरह अख़बारों में कोई तस्वीर नहीं है. न तो उद्योगपति और न ही पीएमओ किसी को यह बता रहे हैं कि कौन किससे मिला.

यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकतंत्र में लोगों को यह पता लगता रहे कि क्या हो रहा है, तो सहजता बनी रहती है. उन्हें अच्छा लगता है. संघ परिवार के सदस्य भी यहां-वहां लोगों से मिल रहे हैं और वे खुश हैं कि देश में उनकी सरकार है. वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. उनका दावा है कि कश्मीर समस्या भी सुलझने ही वाली है, क्योंकि भाजपा कश्मीर में चुनाव जीतने जा रही है. इस तरह की जुबानी बातें चारों ओर फैल रही हैं, बिना यह सोचे कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? कॉरपोरेट सेक्टर उत्साहित है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ भी होता या उतरता नहीं दिख रहा है, जिससे यह लगे कि यूपीए-2 स्थिति के मुकाबले कोई बदलाव आया है. अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है. जापान ने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, लेकिन ऐसा वादा यूपीए-2 के शासन में भी किया गया था. केवल बातों से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पैसे आ रहे हैं. सवाल है कि पैसा किन शर्तों पर आ रहा है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है?

इस बीच कुछ अन्य चीजें थोड़ा परेशान कर रही हैं. राज्यपाल के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसा ही मसला है. सरकार के लिए एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किसी तरह का ईनाम देना साफ़ तौर पर गलत है. यह उसके लिए एक अपमान है, लेकिन यह भी अधिक आश्चर्य की बात है कि संबंधित सज्जन ने इसे स्वीकार कर लिया है. मैं नहीं समझता कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय इस तरह के आचरण से अधिक पवित्र या सम्मानजनक हो जाता है. वास्तव में एक मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके लिए अमेरिकी तर्ज पर एक मुख्य न्यायाधीश को उसके पूरे जीवनकाल तक वेतन दिया जा सकता है.

अब बात प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर. वर्तमान में उनके लिए व्यक्तिगत स्तर पर यह एक बड़ा समय है, क्योंकि एक देश, जिसने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था, आज रेड कार्पेट के साथ उनका स्वागत करने जा रहा है. लेकिन, अब वह अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से. प्रधानमंत्रियों का हमेशा अमेरिका में स्वागत होता रहा है. उनके लिए खास यह होगा कि उन्हें वहां अनिवासी भारतीयों की बड़ी सभा को भी संबोधित करना है. मैं समझता हूं कि 20,000 लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होने जा रही है, जो विदेशी अतिथि के लिए निश्चित रूप से अमेरिका में सबसे बड़ी भीड़ होगी. अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा. यह वहां के लिए एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी. लेकिन, वहां एक बड़ी संख्या गुजराती प्रवासियों एवं अन्य अनिवासी भारतीयों की है और वे उत्साहित हैं. वे नरेंद्र मोदी को एक गर्मजोशी भरा ऐसा स्वागत देंगे, जिससे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में एक छोटी-सी हलचल पैदा होगी.

ओबामा के साथ उनकी चर्चा का मुद्दा क्या होगा, हम नहीं जानते. वह अमेरिका से क्या चाहते हैं, क्या तलाश रहे हैं, हम नहीं जानते. मनमोहन सिंह एवं जॉर्ज बुश ने पुराने परमाणु बिल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद कुछ हुआ नहीं. क्या हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमने भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास किया, जो अपनी अवधारणा में पूरी तरह से गलत था, लेकिन वह यूपीए सरकार द्वारा शुरू कर किया गया था और चल रहा है. यूपीए-2 का अमेरिका के साथ दोस्ताना एवं मजबूत रिश्ता था. हम पहले से ही एक उदारवादी व्यवस्था में हैं. ऐसा नहीं है कि अब जाकर भारत समाजवादी व्यवस्था से बाज़ार आधारित व्यवस्था की ओर जाने वाला है. शासन का चरित्र वही पुराना है. नए प्रधानमंत्री अमेरिका के रवैये के बारे में निश्चित नहीं हैं. इसलिए वह जापान और चीन पर अधिक भरोसा करना चाहते हैं. लेकिन, अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है. अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार है और हमारे लिए भारत एक राष्ट्र है. प्रधानमंत्री को यह भेद ध्यान में रखना चाहिए. भारत को बाज़ार के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से हो सकता है कि कॉरपोरेट जगत खुश हो जाए और मॉल, फ्लाईओवर, सड़कों एवं राजमार्गों की शानदार सीरीज तैयार हो जाए, लेकिन यह सब भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा. ग़रीब आदमी खुद को ग़रीब ही महसूस करेगा और उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा.

यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकतंत्र में लोगों को यह पता लगता रहे कि क्या हो रहा है, तो सहजता बनी रहती है. उन्हें अच्छा लगता है. संघ परिवार के सदस्य भी यहां-वहां लोगों से मिल रहे हैं और वे खुश हैं कि देश में उनकी सरकार है. वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. उनका दावा है कि कश्मीर समस्या भी सुलझने ही वाली है, क्योंकि भाजपा कश्मीर में चुनाव जीतने जा रही है. इस तरह की ज़ुबानी बातें चारों ओर फैल रही हैं, बिना यह सोचे कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? कॉरपोरेट सेक्टर उत्साहित है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ भी होता या उतरता नहीं दिख रहा है, जिससे यह लगे कि यूपीए-2 स्थिति के मुकाबले कोई बदलाव आया है. अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है.

पिछली सरकार ने कॉरपोरेट को बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था में कार्य करने की अनुमति दे दी और सोचा कि ग़रीबों की मदद के लिए मनरेगा और खाद्य सुरक्षा क़ानून बना देने से काम चल जाएगा. मानो, वे समाज के समाजवादी पैटर्न पर वापस जा रहे हैं, जहां अमीर सामान्य तरीके से अपना कारोबार चलाता है और ग़रीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है. अब नई सरकार और प्रधानमंत्री की उपलब्धियां क्या हैं, हमें नहीं मालूम. क्या वह मनरेगा को चलाएंगे या बंद करेंगे, नहीं मालूम. खाद्य सुरक्षा क़ानून का क्या होगा, नहीं मालूम. लेकिन, हम यह ज़रूर जानते हैं कि कॉरपोरेट क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधाएं दी जाएंगी. अब यह सब कैसे आम आदमी या पूरे राष्ट्र के लिए समृद्धि लाने का काम करेगा, मुझे नहीं मालूम. बेहतर होगा, सारी स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट होकर सामने आए. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए

भारतीय समाज में बहुत सारी कहानियां और कहावतें हैं, जो सैकड़ों-हज़ारों सालों के अनुभवों के बाद सूत्र रूप में बनी हैं. एक कहानी आपको सुनाते हैं. दो पड़ोसी थे. एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बहुत जलता था और उसकी जलन का हाल यह था कि वह अपने पड़ोसी का अहित करने के लिए किसी से भी मदद ले सकता था. उसने अचानक सोचा कि मैं अपने पड़ोसी का रोज सुबह अपशकुन करूं. भारतीय समाज में अपशकुन के कई तरीके हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, तो अपशकुन मान लेते हैं. उसी तरह एक आंख का व्यक्ति दिखाई दे जाए, तो देखने वाला उसे अपना अपशकुन मान लेता है. तो जलने वाले पड़ोसी ने सोचा कि बिल्ली मैं तो उसके रास्ते में नहीं छोड़ सकता, पर उसे मैं एक आंख का व्यक्ति, जिसे काना कहते हैं, उसका चेहरा रोज दिखा सकता हूं. उसने काने की तलाश की, लेकिन उसे कोई काना मिला नहीं. तब उसने अपनी ही एक आंख फोड़ ली और अपना चेहरा रोज सबेरे पड़ोसी को दिखाने का निर्णय लिया, ताकि उसका रोज अपशकुन हो.

यह कहानी भारतीय राजनीति में कांग्रेस के ऊपर सटीक बैठती है. इस समय कांग्रेस जलन की जगह निष्क्रिय शब्द के दायरे में अपनी आंख फोड़कर पड़ोसी का अपशकुन करने की योजना बनाती दिखाई दे रही है. कांग्रेस को जहां जनता को साथ लेकर, जनता के सवालों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ते दिखना चाहिए, वहां वह आपस में लड़ने में पूरा समय खर्च कर रही है. किसे हटाया जाए, किसे घर बैठाया जाए, किसे बर्फ में लगाया जाए, बस जनता के बीच न जाया जाए. यह चार लफ्जों की कहानी कांग्रेस की बन गई है. न कांग्रेस से किसी की शत्रुता है, न कांग्रेस की किसी से मित्रता है. पर लगता ज़रूर है कि लोकतंत्र का महत्व कांग्रेस ने भुला दिया है. अगर लोकतंत्र में कांग्रेस को विपक्ष का स्थान मिला है, तो इसका मतलब उसे पांच साल तक जनता के सवालों को लेकर जनता को खड़ा करने, उसे उत्साहित करने और निराशा से लड़ने का वक्त मिला है. पर कांग्रेस तो शायद विपक्ष का मतलब ही नहीं समझती, इसलिए उसने लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को भी न्यायालय में लाने की चीज बना दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो एक तरह से विपक्ष के नेता का पद भीख में मांगने जैसा माहौल बना लिया. क्या लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मिलने से ही विपक्ष का रोल पूरा होता है? शायद नहीं.

कांग्रेस अपने पिछले दस सालों के शासनकाल की एक सीख भूल गई. पिछले दस सालों में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी और विपक्ष के नेता पद पर सुषमा स्वराज थीं, उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी थे. इतने भारी-भरकम नेताओं के होने के बावजूद देश में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का कोई सार्थक रोल नहीं निभाया और इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पहली बार विपक्ष की गरिमा के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया. लेकिन, इसके बावजूद सरकार की गलत नीतियों, सरकार के गलत फ़ैसलों और सरकार द्वारा उत्पन्न की हुई समस्याओं से उपजे गुस्से ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता पद पर काबिज होने की संख्या भी नहीं मिलने दी और जिस दल ने विपक्ष का सक्षम रोल नहीं निभाया या सार्थक रोल नहीं निभाया, उसे ही सत्ता सौंप दी.

शायद कांग्रेस उसी रास्ते पर चलना चाहती है. कांग्रेस में अब राजनीतिक रूप से सोचने-समझने वाले नेताओं का या तो अभाव दिखने लगा है या जो राजनीतिक रूप से सोच-समझ सकते हैं, वे अपनी बात कहना व्यर्थ मानते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने वहां पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताकत उन्होंने ऐसे संगठन को लेकर लगाई, जिसे उन्होंने या उनके साथियों ने कभी बनने ही नहीं दिया. नतीजे के तौर पर बिहार में कांग्रेस के सिर्फ़ चार विधायक चुने गए. इसके डेढ़ साल के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, लेकिन कांग्रेस ने कोई सीख नहीं ली और उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया. न पार्टी के सांसदों को उत्तर प्रदेश में लगाया गया, न विधायकों को और न उन नेताओं को, जो न सांसद थे, न विधायक, लेकिन जिनकी समाज में पैठ थी. एक निष्क्रिय-निर्जीव संगठन उत्तर प्रदेश में बना रहा और दिल्ली से बैठकर उसी लुंजपुंज संगठन को हिलाने-डुलाने की कवायद होती रही.

यह सब राहुल गांधी की आंख के नीचे हो रहा था. उस पार्टी में, जिसकी अध्यक्ष खुद उनकी मां सोनिया गांधी हैं. नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में पार्टी बुरी तरह हारी. लोकसभा के चुनाव इसके दो साल बाद होने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भी सारे देश में न संगठन को सक्षम बनाया गया, न पार्टी के सांसदों- विधायकों को ज़िम्मेदारी दी गई और न उन्हें बताया गया कि किस दिशा में पार्टी संगठन को खड़ा करना है. दूसरी तरफ़ सरकार मनमाने तरीके से फ़ैसले लेती रही और राहुल गांधी उन पीआर कंपनियों के इशारे पर अपना रुख तय करते रहे, जो हिंदुस्तानी समाज को समझती ही नहीं हैं. पार्टी के भीतर राजनीतिक सलाहों और राजनीतिक क़दमों का इतना अभाव पैदा हो गया, जिसे केवल एक शब्द से व्याख्यायित किया जा सकता है और वह शब्द है शून्यता.

आम तौर पर यह माना जा रहा है कि सरकार के फ़ैसले सरकार नहीं लेती थी, वे दस जनपथ से होते थे. दस जनपथ ने भी आज तक यह खंडन नहीं किया है कि फ़ैसले उनके यहां से नहीं होते थे. पर अगर सत्ता का एक ही केंद्र था, तो उसके जो सकारात्मक परिणाम निकलने चाहिए थे, वे नहीं निकले. घोटाले पर घोटाले सामने आते गए और पार्टी उनमें लगातार घिरती चली गई. इसके बावजूद लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई भी योजना कांग्रेस पार्टी में बनती नहीं दिखाई दी. और, यह सब राहुल गांधी की निष्क्रियता और सोनिया गांधी के अराजनीतिक ज्ञान का परिणाम माना जा सकता है. नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी कभी दे नहीं पाई और वह नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए अखाड़े में लड़ती दिखाई दी. कांग्रेस यह भूल गई कि अपने अखाड़े में जीतना आसान है, जबकि प्रतिद्वंद्वी के अखाड़े में लड़ने में हारने की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं.

लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर आ गई. इसके बावजूद ग़ैर राजनीतिक सवाल उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, मसलन नेता विपक्ष का पद. होना यह चाहिए था कि राहुल गांधी या कांग्रेस की औपचारिक अध्यक्ष उनकी मां सोनिया गांधी पार्टी के सभी गुटों को, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग बुलातीं और इतने बड़े देश में पार्टी को कैसे खड़ा करना है, इसके बारे में सबकी राय लेतीं. पर इसकी जगह स्वयं को बचाने के लिए ज़िम्मेदारियां तय की जाने लगीं और हमेशा की तरह हार का विश्लेषण करने के लिए एंटोनी कमेटी बनी. पार्टी को लेकर अब तक जितनी भी कमेटियां बनी हैं, उनमें ज़्यादातर में एंटोनी साहब रहे हैं. एंटोनी ने राहुल गांधी को पाक-साफ़ करार दे दिया और कहा कि पार्टी मनमोहन सिंह की वजह से हारी. पार्टी में इसे लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि पार्टी में ही लोगों ने इसका मखौल उड़ाया, क्योंकि मनमोहन सिंह को दिशा देने वाला भी तो दस जनपथ ही था और जब-जब राहुल गांधी ने मांग की, तब-तब मनमोहन सिंह ने उस मांग को पूरा किया. भले ही उसे थूककर चाटने की संज्ञा विपक्ष ने दी हो.

राहुल गांधी बजाय इसके कि पार्टी की नई तरह से विवेचना करते, राज्यों के संगठनों को नए तरीके से संगठित करते, क्योंकि हर साल लगभग एक या दो विधानसभाओं के चुनाव लगातार आने वाले हैं अगले लोकसभा चुनाव तक. और, राज्यों में कांग्रेस का जीतना बहुत ज़रूरी है. किसी तरह बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ उसने समझौता किया, लेकिन बाकी राज्यों में पार्टी संगठन क्या करेगा और किसके सहारे अपनी एक या दो या पांच सीटें जीतने की संभावनाएं तलाशेगा, यह अभी तक साफ़ नहीं है. अब कांग्रेस के सचिव, जिनका कांग्रेस के विधान में कोई रोल नहीं है, वे कांग्रेस के सभी नेताओं के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं. इनमें से ज़्यादातर सचिव ऐसे हैं, जो नए उभरे धनाढ्य वर्ग से आते हैं. इन्हें न राजनीति की समझ है, न विपक्षी पैतरों की समझ है. इनमें से ज़्यादातर जी- हुजूरी और चापलूसी में डिग्री लिए हुए हैं. इनके पास बेपनाह पैसा है और ये राहुल गांधी के साथ खड़े होकर देश में एक नई राजनीति करना चाहते हैं. स्वागत किया जाना चाहिए इस नई राजनीति का भी, क्योंकि इसका जवाब कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलेगा, बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा. उसके पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में मिलेगा और यह जवाब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, बल्कि जनता देगी. वह जनता, जिसने कांग्रेस को लंबे समय तक देश में सत्ता पर काबिज रखा. इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण होगा, लोगों का कांग्रेस से संपूर्ण मोहभंग.

राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं, यह बात उनके पक्ष में जाती है, पर इससे भी ज़्यादा उनके पक्ष में कोई तर्क भविष्य में जा सकता है, तो वह है उनकी समझ. अगर वह भारतीय समस्याओं को समझें, भारत के लोगों की तकलीफों के प्रवक्ता बनें, तो शायद लोग उनकी तरफ़ दोबारा देखें. पर अभी तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का अपशकुन हो, इसके लिए अपनी ही आंख फोड़ने में लगे हुए हैं. मुझे लगता है, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत सशक्त स्थान है. उस रोल को कांग्रेस पार्टी को किसी और के पास नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि स्वयं उसे निभाने का ज़िम्मा पूरा करना चाहिए, अन्यथा विपक्ष के उस रोल को निभाने के लिए नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, देवेगौड़ा और ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता तैयार बैठे हैं. मुझे लगता है, अगले पांच सालों में विपक्ष के अध्याय में एक नई इबारत लिखी जी सकती है. ■

editor@chauthiduniya.com

जुनून और उन्माद से लबरेज़ पत्रकारिता

यह बदलाव का युग था. पुराने संपादकों और नए संपादकों के बीच तीखे मतभेद भी इसी दौर में उभरे. पटना के एक होटल में दिनमान के पहले संपादक एवं वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय और एसपी के बीच काफी लंबी और तीखी बहस हुई. बहस का विषय था कि रविवार जैसी पत्रकारिता कर रहा है, वह सचमुच पत्रकारिता है या नहीं तथा वह जिन नए लड़कों को रिपोर्ट लिखने की ज़िम्मेदारी दे रहा है, वे उसे निभा रहे हैं या नहीं. बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, पर अज्ञेय जी को लगा कि पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है तथा सुरेंद्र जी को लगा कि वह बिल्कुल सही दिशा में हैं. शायद यह पीढ़ियों के दृष्टिकोण का फर्क था. कभी परशु-राम ने भी राम के ऊपर संदेह व्यक्त किया था, पर यहां तो पीढ़ियों के साथ काल का भी फर्क था. तब परशुराम समझ गए थे कि उनका वक्त समाप्त हो गया है और राम का प्रारंभ हो गया है, पर इस काल में इसे अज्ञेय जी अंत तक नहीं समझ पाए. उन दिनों के कई वरिष्ठ पत्रकार अज्ञेय जी की राय के थे, लेकिन समय ने सुरेंद्र जी को सही साबित किया. यदि यह न होता, तो आज हिंदी पत्रकारिता में हम जिसे स्वर्णिम अध्याय कहते हैं, वह रचा ही नहीं जाता. न युवकों को बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती और न उन्हें संपादक बनने के योग्य माना जाता.

पहली पीढ़ी के इन संपादकों के साथ एक खासियत और भी थी. ये पत्रकार होने के साथ-साथ साहित्यकार भी थे. ये रिपोर्ट को साहित्य की कसौटी पर भी कसते थे. रिपोर्ट लिखवाने के इनके पैमाने भी अलग थे. सुरेंद्र प्रताप सिंह से पत्रकारों के संपादक बनने का सिलसिला शुरू हुआ. पत्रकारिता में गुणात्मक परिवर्तन का यह भी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि अब संपादक विशुद्ध पत्रकारीय दृष्टिकोण से न केवल रिपोर्ट चुनता था, बल्कि लिखवाता भी था. एसपी के बाद ज़्यादातर दैनिक अख़बारों व पत्रिकाओं के संपादक पत्रकार हुए. इसीलिए हिंदी की ज़्यादातर रिपोर्ट इसी दौर में चर्चित हुईं. संपादक का अपने संवाददाता के साथ आत्मीय व संरक्षक का रिश्ता भी इसी काल में स्थापित हुआ. पत्रकारों का यह नया वर्ग अपने संपादक का केवल धन्यवाद या बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी सुनने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता था. हम में से बहुतों की ज़िंदगी में ऐसे किस्सों की भरमार है. एसपी या एमजे जब हमें फोन कर कहते कि अच्छी रिपोर्ट है, तो लगता था कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया. लेकिन इस मानसिक स्थिति ने कई लोगों की आदतों को बिगाड़ भी दिया. कई पत्रकार ऐसे अहम् के शिकार हो गए कि वे न उन दिनों सत्ता प्रतिष्ठान को कुछ समझते थे और न आज समझते हैं. उनके लिए उन दिनों भी पत्रकारिता जुनून और उन्माद थी और आज भी जुनून और उन्माद है. मेरा अपना मानना है कि जिसमें जुनून और उन्माद नहीं होगा, वह अच्छा पत्रकार बन ही नहीं सकता. वह भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा. यदि किसी को प्रथम पांच सौ अथवा प्रथम सौ में स्वयं को शामिल कराना है, तो उसे अपने अंदर जुनून और उन्माद के साथ वे सारे तत्व शामिल करने पड़ेंगे, जो उस दौर के पत्रकारों में थे.

एक खास बात और थी. जो पत्रकार इस दौर में बड़े हुए, वे न तो उन दिनों प्रेस क्लब या अन्य क्लबों में जाते थे और न ही शाम जनसंपर्क अधिकारियों के साथ बिताने की कोशिश करते थे. वे न तो मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों का आतिथ्य स्वीकार करते थे और न ही बड़े घरानों से आई भेंट लेते थे. ऐसा नहीं है कि आज सभी ऐसे हो गए हैं, लेकिन तालाब में ऐसी मछलियों की संख्या बढ़ रही है. उन दिनों केवल एक ही नशा रहता था, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट के लिए विषय तलाश करने का. इस दौर में पत्रकारों की एक ऐसी जमात खड़ी हुई, तो सर्च करने वाली थी, रिसर्च करने वाली नहीं. हमेशा सर्च करने वाले कम होते हैं, पर उनकी सर्च पर रिसर्च करने वाले बहुत ज़्यादा. उन दिनों के संपादक हमेशा सर्च करने की प्रेरणा देते थे. विनम्रता से कहूं कि जो जोखिम उठा सके, वे सर्च करने वाली टीम का हिस्सा बन गए तथा बाकी रिसर्च करने वाली टीम के शानदार सदस्य बनकर रह गए. संपादक का यही सबसे बड़ा गुण है कि यदि वह अपनी टीम को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, पर यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि कितनों की इच्छा इतिहास का हिस्सा बनने की होती है.

एक ख़ास बात और थी. जो पत्रकार इस दौर में बड़े हुए, वे न तो उन दिनों प्रेस क्लब या अन्य क्लबों में जाते थे और न ही शाम जनसंपर्क अधिकारियों के साथ बिताने की कोशिश करते थे. वे न तो मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों का आतिथ्य स्वीकार करते थे और न ही बड़े घरानों से आई भेंट लेते थे. ऐसा नहीं है कि आज सभी ऐसे हो गए हैं, लेकिन तालाब में ऐसी मछलियों की संख्या बढ़ रही है. उन दिनों केवल एक ही नशा रहता था, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट के लिए विषय तलाश करने का. इस दौर में पत्रकारों की एक ऐसी जमात खड़ी हुई, तो सर्च करने वाली थी, रिसर्च करने वाली नहीं.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

सुरेंद्र प्रताप सिंह में यह इच्छा थी. उन्होंने एक पूरी पीढ़ी पर प्रभाव डाला और उसे नई शैली की पत्रकारिता के लिए तैयार कर दिया. एसपी के साथ एमजे अकबर को भी श्रेय जाता है, बल्कि एमजे को ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एसपी को न केवल तैयार किया, बल्कि उन्हें पूरी आज़ादी और स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल दिया. एसपी और अकबर को इसलिए भी पत्रकारिता का इतिहास याद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों गुरु संपादकों के साथ काम करने के दौरान वह सब अपने मन में संजो लिया, जिसे वे भविष्य में करना चाहते होंगे. दोनों के गुरु बड़े और महान हैं, ये उस पत्रकारिता के लिए कभी जाने नहीं गए, जिसके लिए ये सराहे गए या याद किए जाएंगे. दोनों ने महान संपादकों, श्री खुशवंत सिंह और डॉ. धर्मवीर भारती से वे सभी गुण सीखे, जिनसे एक अच्छा पत्रकार और संपादक बना जा सकता है, पर पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखने की कला तो उन्हें उसी जिजीविषा से मिली, जिसे उन्होंने स्वयं अपने अंदर पैदा किया.

आशा करनी चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता में जल्दी ही खोजी रिपोर्ट, घटनास्थल से आई सीधी रिपोर्ट, बेबाक सीधी भाषा में जनता के पक्ष की रिपोर्ट, जोखिम उठाकर उजागर करने वाली रिपोर्ट जल्दी ही पढ़ने या देखने को मिलेगी. फिर कोई इतिहास बनाने वाला संपादक आएगा और हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध करने वाले संवाददाताओं की फौज खड़ी कर जाएगा. बीते वक्त का गुणगान कभी अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन यदि वक्त बदल जाए और गुणवत्ता न बढ़े, तो बीता वक्त हमेशा याद आता है. गुणवत्ता बढ़ रही है, इसका एक पैमाना है कि याद करने पर कितनी रिपोर्ट याद आती हैं और कितने संवाददाता याद आते हैं. यदि लीक से हटकर रिपोर्ट होगी, तो याद आएगी और यदि सामान्य होगी, तो याद नहीं रह पाएगी. संपादकों और पत्रकारों की यह ज़िम्मेदारी है कि यदि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले से अच्छा काम करना है, तो उन्हें अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना होगा. शायद तभी उन्हें इतिहास याद रख पाएगा और अपने पन्नों में उनके लिए जगह सुरक्षित रखेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

इतिहास पर माथापच्ची

संघ और विश्व हिंदू परिषद के सहायक संगठनों द्वारा एक अलग तरह का फ्रंट खोल दिया गया है, जो सांप्रदायिक एजेंडे से तो अलग है, लेकिन अक्सर इसे लेकर लोग भ्रमित हो जाते हैं. यह संघ परिवार की सांस्कृतिक पहचान का एजेंडा है. यहां पर भी दो धड़े हैं. एक धड़ा वीर सावरकर के उस तर्क की पुनरावृत्ति कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र का निर्धारण उसकी सामुदायिक शर्तों पर ही होता है.

सरकार गठन के सौ दिनों के भीतर प्रदर्शन मापने का फैशन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डीलानो रूजवेल्ट ने शुरू किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका आर्थिक महामंदी की चपेट में था और मार्च 1933 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तेज क़दम उठाने थे. अगर भारत की बात जाए, तो नरेंद्र मोदी को किसी महामंदी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उनके सामने एक हताश देश था, जो बदलाव के लिए छटपटा रहा था. मोदी से आशाएं काफी ऊंची थीं, जबकि उन्होंने किसी 100 दिनी एजेंडे का वादा नहीं किया था. अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है. साधारण राजनीति के फ्रंट पर नई सरकार ने काम किया है, जिसमें आर्थिक एवं विदेश नीति और ऊर्जा एवं पर्यावरण के मामले शामिल हैं. हालांकि इस दौरान सरकार सहमति बनाकर ही चली है, न कि आमने-सामने आने के नज़रिये से. स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है और यह आशा व्यक्त की जा रही है कि आगामी तिमाही में विकास दर शुरुआती तिमाही में तय की गई विकास दर से ज़्यादा रहेगी. आगामी सौ दिन शायद पिछले सौ दिनों से और बेहतर साबित हो सकते हैं.

सरकार में उच्चस्तरीय स्तर पर काम ठीक रहा है. हालांकि अभी आम आदमी के सवाल वहीं बने हुए हैं और कुछ मामले संस्कृति एवं पहचान को भी लेकर बने हुए हैं. हालांकि मोदी बीते दिनों में सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी यह संभव नहीं लगता कि भाजपा में ग्रास रूट लेवल पर भी विचारधारा में कोई परिवर्तन होने वाला है. चुनाव के पहले डराने वाली ऐसी ख़बरें चल रही थीं कि मोदी सत्ता में आते ही सांप्रदायिक एजेंडा लागू करेंगे. जबकि वह जबसे आए हैं, सभी के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में निचले स्तर पर कुछ ऐसा मूड नहीं है. बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अनुसार यह ऐसा क्षण है, जिसकी वे काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे. उनके अनुसार यह हिसाब बराबर करने का समय है. हिंदू-मुस्लिम विवाद के कई छोटे मामले अभी प्रकाश में आए हैंङ्क. बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोदी को तुरंत ऐसी बातों के लिए क़दम उठाने चाहिए, लेकिन वह सिवाय बड़े अवसरों के इस पर कुछ भी नहीं बोलते, जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर बोला था.

यहां तक कि बहुत संगठित राजनीतिक पार्टियां भी इतने छोटे स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं कर सकतीं. देखिए, डेविड कैमरन किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. भारतीय राजनीतिक पार्टियां पुरानी राजशाही सेनाओं की तरह हो गई हैं, जिनमें छोटे सरदारों के पास अपनी सेनाएं होती थीं और वे भी ताकतवर होते थे. उत्तर प्रदेश में मायावती के सत्ता से जाने के बाद से ही एक तरह का सांप्रदायिक युद्ध जारी है. समाजवादी पार्टी ने अपने कमजोर होते मुस्लिम-यादव वोट बैंक को महसूस किया और अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल के जाटों को अपनी तरफ़ लुभाना शुरू कर दिया. भाजपा ने भी उसी जगह काम करना शुरू कर दिया और जिसके नतीजे के रूप में मुजफ्फरनगर एवं कई अन्य जगहों जैसे परिणाम सामने आए. वर्तमान में उत्तर प्रदेश क़ानून विहीन राज्य बन गया है और वहां की महिलाएं इसके बारे में बेहतर बता सकती हैं.

संघ और विश्व हिंदू परिषद के सहायक संगठनों द्वारा एक अलग तरह का फ्रंट खोल दिया गया है, जो सांप्रदायिक एजेंडे से तो अलग है, लेकिन अक्सर इसे लेकर लोग भ्रमित हो जाते हैं. यह संघ परिवार की सांस्कृतिक पहचान का एजेंडा है. यहां पर भी दो धड़े हैं. एक धड़ा वीर सावरकर के उस तर्क की पुनरावृत्ति कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र का निर्धारण उसकी सामुदायिक शर्तों पर ही होता है. उन्होंने यह तर्क यूरोप के हिसाब से उठाया था, जिसमें एक राष्ट्र बहु-सामुदायिक नहीं हो सकता. इसलिए उनके लिए हिंदुत्व एक धार्मिक पहचान न होकर एक क्षेत्रीय पहचान थी. 1871 में हुई जनगणना के दौरान हिंदुत्ववाद शब्द का

इस्तेमाल सनातन धर्म मानने वालों के लिए किया गया था. हिंदुत्व पर लिखे गए अपने लेख में सावरकर ने काफी लंबी व्याख्या देकर समझाया है कि हिंदू शब्द फारसी नहीं है. ऐसा संभव है, सिंधु के जरिये यह फारसी से ही निकला हो. मुस्लिम इतिहासकार इसे अल-हिंद कहते हैं. सत्रहवीं शताब्दी में पुर्तगाली उपमहाद्वीप को जेंटू कहते थे, जिसमें ज का उच्चारण ह होता था.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तब उसी भाषा में बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है. इस दौरान सभी ने, यहां तक कि वामपंथियों ने भी, कहा कि यह भारत था, हिंदुस्तान नहीं. मुझे याद है कि पचास के दशक में किस तरह वामपंथी नेता कहते थे कि इंडिया के साथ भारत का नाम एक रियायत के तौर पर जोड़ा गया था, जिसके लिए कांग्रेस के दक्षिणपंथी मिजाज के नेताओं का विशेष आग्रह था, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे. वामपंथी नेताओं ने हिंदुस्तान शब्द को ही तरजीह दी थी. इसलिए नहीं कि अल्लामा इकबाल इसे प्रयोग में लाए थे, बल्कि इसलिए कि वे राष्ट्र भाषा के तौर पर हिंदुस्तानी को ज़्यादा तरजीह देते थे हिंदी पर.

अब फिर से उस बहस में जाने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षवादियों के लिए ज़रूरी हो गया है कि वे इतिहास पर चल रहे रण को गंभीरता से लें. वैसे भी उनके आइडिया ऑफ इंडिया बनाने के लिए सारे स्रोतों पर उनका एकाधिकार ही रहा है. संघ के विद्वानों को चाहिए कि वे एक अध्ययनशील इतिहास लिखें, जो धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों से मेल खा सके. यह सिर्फ़ दीनानाथ बत्रा की किताबों से संभव नहीं हो सकेगा. गंभीर इतिहास लेखन में सालों का कठिन परिश्रम लगता है. अब संघ परिवार से जुड़े इतिहासकारों के लिए क़ीमती समय आ गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैल्शियम युक्त भोजन

बोन कैंसर के खतरे को कम करता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

कैंसर की शुरुआत शरीर की आधारभूत इकाई यानि कोशिकाओं में बदलाव के कारण होती है. शरीर में पुरानी कोशिकाओं का टूटना और नई कोशिकाओं का बनाना एक सतत प्रक्रिया है. लेकिन जब कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया असामान्य हो जाती है ऐसे में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती. इसी तरह का एक कैंसर है हड्डियों का कैंसर. हालांकि अभी तक हड्डियों के कैंसर के कारणों का पता नहीं लग सका है, लेकिन इसे फिर भी अनुवांशिक (जेनेटिक) कारणों और कारकों से जोड़कर देखा जाता है. हड्डियों का कैंसर आम तौर पर शरीर के एक हिस्से से शुरू हो कर शरीर के दुसरे भागों तक पहुंच जाता है.

बोन कैंसर के लक्षण

हड्डियों का कैंसर किसी भी उम्र के लोगों मसलन बच्चों बूढ़ों या नौजवान किसी को भी हो सकता है. हालांकि हड्डियों के कैंसर के मामले आम तौर पर कम ही देखने को मिलते हैं. इस प्रकार के कैंसर की शुरुआत शरीर की किसी भी हड्डी से हो सकती है. समय रहते इसका इलाज कराने के लिए इसके लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचानना जरुरी है. जैसे-जैसे कैंसर कोशिकाएं शरीर में विकसित होती हैं उसी तरह शरीर में इसके लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं. हड्डियों के कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण हड्डियों में तोज दर्द होना है. दर्द के साथ उस हिस्से में सूजन भी आनी शुरू होती है. दर्द में वक्त के साथ इज़ाफा होता है. कैंसर के स्थान के उपरी हिस्से में त्वचा लाल रंग की होती है, वह हिस्सा शरीर के अन्य हिस्से की तुलना में ज्यादा गर्म होता है, उस हिस्से में थोडा सुन्नपन और सूजन होती है. बोन ट्यूमर की वजह से अचानक बुखार आ जाता है व बुखार के दौरान पसीना भी आ सकता है. चक्कर आना, भूख कम लगना, वजन में गिरावट आना इसके अन्य लक्षण हैं. वयस्कों में हड्डियों के कैंसर का पता तब चलता है जब मरीज को बार-बार हड्डियों के फ्रेक्चर होने की शिकायत होने लगती है. हड्डियों का कमजोर होना बोन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है. यदि आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो जरुरी नहीं है कि आपको बोन कैंसर हो. ऐसा शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है. इसे ऑस्ट्रियोपोरोसिस कहते हैं. बोन डेंसिटी टेस्ट करवारकर इस तरह के वहम से बचा जा सकता है. हड्डी में किसी एक ही जगह पर बार-बार चोट लगने से हड्डी में धाव बन जाता है, उस पर ध्यान न देने पर भी उस स्थान पर कैंसर होने की संभावना होती है.

बोन कैंसर के प्रकार

प्राइमरी बोन कैंसर हड्डियों शुरू होकर होकर धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है. यह कैंसर एक वयस्क के शरीर में पाई जाने वाली 206 हड्डियों में से किसी भी हड्डी में हो सकता है. लेकिन यह आम तौर पर हाथ और पैर की लम्बी हड्डियों अथवा जोडों से शुरू होता है. हालंकि हड्डियों का कैंसर किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है लेकिन आम तौर पर यह बच्चों और नवजवानों को अपना शिकार ज्यादा बनाता है.क्योंकि उनके शरीर में चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है. शरीर के नाजुक होने की वजह से अंदरूनी गंभीर चोटें कैंसर का रुप ले लेती हैं, हालांकि बच्चों के शरीर में कोशिकाओं के बनने की दर युवाओं और वृद्धों से ज्यादा होती है ऐसे में अधिकांश मामलों में बच्चे चोटों से उबर जाते हैं लेकिन कुछ के शरीर में कैंसर घर कर जाता है.

प्राथमिक बोन कैंसर तीन प्रकार का होता है: ऑस्टियोसर्कोमा, कॉन्ड्रोसर्कोमा, इविंगसर्कोमा.

ऑस्टियो सर्कोमा- यह बोन कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है. यह कैंसर आमतौर पर कूल्हे और कंधे व साथ ही घुटने के आसपास के हिस्सों में पाया जाता है. इस प्रकार के कैंसर से हर साल दस लाख लोगों में से 3-4 नए लोग इस तरह के कैंसर का शिकार होते हैं. हालांकि यह बच्चों को भी हो सकता है लेकिन बोन कैंसर का यह रूप आमतौर पर युवाओं में देखने को मिलता है. यह कैंसर महिलाओं के मुकाबले पुरूषों में अधिक पाया जाता है.

कॉन्ड्रोसर्कोंमा - बोन कैंसर के प्रकारों में कॉन्ड्रो सार्कोंमा 40 से 70 वर्ष की उम्र के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है. यह कैंसर भी कूल्हे और कंधे के आसपास अधिक होता है. बोन कैंसर का यह सामान्य प्रकार है. यह कैंसर हड्डियों से शुरू होकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है. इस कैंसर में सबसे अधिक दर्द जोड़ों में होता है.

इविंगसरकॉमा - यह कैंसर कम उम्र के लोगों को होता है. यह 5 से 20 साल तक के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. यह आमतौर पर हाथों, पैर, बाजू, पसलियों इत्यादि जगहों से आरंभ होता है.

सेकेंडरी बोन कैंसर में प्रभावित कोशिकाएं धीरे-धीरे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती हैं और शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगती है. यह कैंसर शरीर के किसी एक हिस्से में फैलना शुरू होता है और आम तौर पर लंग कैंसर(फेफड़ों का कैंसर), स्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) या फिर प्रोटेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों के शरीर में बोन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. सेकेंड्री बोन कैंसर के परिणाम स्वरूप हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है और बार-बार हड्डियां टूटने लगती हैं. उपरोक्त कैंसरों के मरीजों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए. जिससे कि कैंसर की दोहरी मार से बचा जा सके. इस अवस्था में मरीज को बहुत अधिक दर्द होता है और विशेष तौर पर कमर में दर्द की शिकायत रहती हैं.

असामान्य बोन कैंसर

असमान्य बोन कैंसर आम तौर पर वयस्कों में पाए जाते हैं इसके निम्न प्रकार हैं. आईब्रोसरकोमा अधिकांशतः घुटनों और कूल्हों में पाया जाता है. ये वृद्ध लोगों को कैंसर के इलाज के क्रम में रेडियेशन थैरेपी की वजह से होता है. एडमिंटोनोमा आमौतौर पर पिंडली की हड्डी में होता है. कोर्डोमास अधिकांशतः रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में टेल बोन के पास पाया जाता है.

बोन कैंसर के कारण

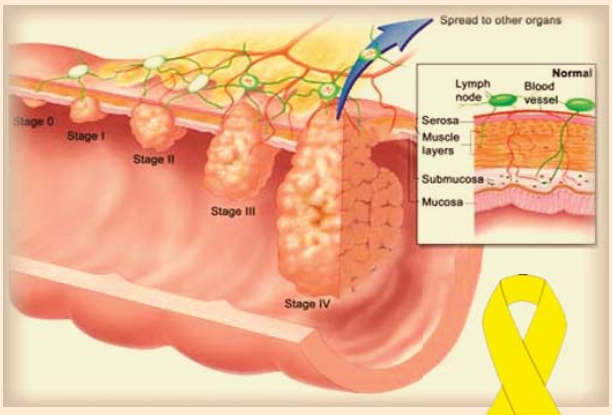

बोन कैंसर कई कारणों से हो सकता है, इनमें से मुख्य है आनुवांशिक रूप से कोई गड़बड़ी होना. इसके अलावा पेगेट रोग का प्रभाव भी हड्डियों पर पड़ता है. इसके साथ ही यदि व्यक्ति बहुत अधिक रेडिएशन के प्रभाव में है या फिर बहुत अधिक रेडिएशन ट्रीटमेंट होने से भी बोन कैंसर हो सकता है. बोन कैंसर से संबंधित एक और कैंसर है बोन मेरो कैंसर. हालांकि यह ब्लड कैंसर का एक रूप है. बोन मेरो कैंसर से पीड़ित मरीज को बोन कैंसर हो सकता है. दरअसल, बोन मेरो कैंसर में रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती है जो कि हड्डियों का आधार होती है, ऐसे में बोन मेरो कैंसर की स्थिति बोन कैंसर को बढ़ाने में सहायक है. कोशिकाओं का आसामन्य रूप से बढ़ने और उनका प्रभाव बोन कैंसर का कारक है. हालांकि बोन कैंसर बोन मेरो कैंसर से बहुत अलग है लेकिन बोन मेरो कैंसर और बोन कैंसर के इलाज पर भी निर्भर करता है कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह से और किस रूप में ले रहे हैं. यदि बोन कैंसर का शुरूआती अवस्था में पता लग जाता है तो आप आसानी से इसका सही इलाज करवा सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के बोन कैंसर से निजात पा सकते हैं.

बोन कैंसर का निदान

बोन कैंसर के दौरान हड्डियों में ट्यूमर हो जाता है, इससे हड्डियों के टिश्यू को बहुत नुकसान पहुंचता है. लेकिन सभी बोन ट्यूमर घातक नहीं होते हैं. दरअसल बोन ट्यूमर दो तरह के होते हैं पहला बेनाइन और दूसरा है मेलिगनेन्ट. बेनाइन ट्यूमर का होना सामान्य है. इससे रोगी को कोई खतरा नहीं होता है. जबकि मेलिगनेन्ट ट्यूमर काफी खतरनाक होता है. यह दोनों ही ट्यूमर रोगी की हड्डियों में होते हैं लेकिन बेनाइन ट्यूमर फैलता नहीं और ना ही बोन टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है, इससे खतरा बहुत कम होता है. मेलिगनेन्ट ट्यूमर जब हड्डियों में होता है तब उसे प्राइमरी बोन कैंसर कहते हैं. जब कैंसर हड्डियों से शरीर के अन्य भागों जैसे ब्रेस्ट, फेफड़े, प्रोस्टेट में पहुंच जाता है तो उसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं.

बोन कैंसर का उपचार

सर्जरी: सर्जरी करने से पहले ट्यूमर का आकार देखना जरूरी है. सर्जरी के दौरान ट्यूमर के सभी भाग व उसके आसपास के टिश्यू को निकाल दिया जाता है. कभी कभी जिस जगह पर कैंसर हुआ है उस अवयव को हटाना पड़ता है. सर्जरी के दौरान अगर संभव हो तो क्षतिग्रस्त हड्डियों को निकालकर उसकी जगह आर्टीफिशियल हड्डी लगना पड़ती है. यह बोन कैंसर का बहुत ही आम इलाज है.

कीमो थैरेपी चिकित्सा: कीमोथेरेपी में कैंसर निवारक दवाओं के जरिए ट्यूमर को खत्म किया जाता है. दवाएं कैंसर सेल्स को बढ़ने व फैलने से रोकती है लेकिन यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करती है लेकिन समय के साथ यह कोशिकाएं ठीक हो जाती हैं. कीमोथेरेपी की वजह से भूख न लगना, मितली आना, वजन कम होना, चक्कर आना जैसी समस्या हो सकती हैं. आमतौर पर सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी चिकित्सा की जाती है लेकिन कई बार सर्जरी के बाद भी यह चिकित्सा ट्यूमर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दी जाती है.

रेडियेशन थैरेपी उपचार: रेडियेशन थैरेपी में एक बड़ी मशीन के जरिए कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है. इससे निकलने वाले विकिरण का उपयोग ट्यूमर के आकार या रक्त संचार को कम करने के लिये किया जाता है क्योंकि ट्यूमर प्रभावित अंग में रक्त की आपूर्ति की मात्रा बहुत होती है. इसके परिणाम स्वरूप कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इस विधि का प्रयोग प्रभावित अंग में ऑपरेशन से पहले या सर्जरी के दौरान रक्त की आपूर्ति को कम करने के लिए किया जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नए अध्याय की शुरुआत

चौथी दुनिया ब्यूरो

जिस समय देश में सांप्रदायिक सद्भाव कम हो रहा है. लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं. ऐसे समय में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धरती ने हिंदी साहित्य जगत को विमर्श के लिए एक नया मंच प्रदान किया है. 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित तीन दिवसीय अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ नये साहित्य सृजन का संकल्प लिया गया. साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए देश भर के विख्यात साहित्यकार और कलाविद एक मंच पर आए. सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को लोगों के बीच प्रगाढ़ करने के लिए इस तरह के मंच की आवश्यकता थी. अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल ने इसकी कमी को पूरा कर दिया है. सम्मेलन का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए देश और दुनिया के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाविद और पत्रकार सहित विभिन्न वर्गों की बौद्धिक सहभागिता से सकारात्मक विमर्श करना था. जिससे समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभ्य, सुसंस्कृत और संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सके. अब अजमेर भी देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां लोगों के पास देश को संबोधित करने, देश-विदेश के घटना क्रम पर विमर्श और टिप्पणी करने के लिए एक मंच उपलब्ध है. इस मंच के जरिए अजमेर के लोग अपनी आवाज देश के कोने-कोने में पहुंचा सकते हैं. इस मंच ने अजमेर के लोगों को सवाल पूछने आजादी दी है. अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल के लोगो और संकेतों में भी सद्भावना के प्रतीक नज़र आ रहे थे. फेस्टिवल के लोगो में ख्वाजा की दरगाह, पुष्कर का मंदिर और पृथ्वी राज चौहान के तारागढ़ किले को जगह दी गई थी. जो कि अजमेर के इतिहास, सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए था. इस साहित्य उत्सव में समाज के उन सभी विषयों को जगह दी गई थी. जिनका आम और खास सभी लोगों से ताल्लुक होता है. साहित्य, कला,राजनीति, शिक्षा, लोक संस्कृति, पत्रकारिता और सोशल मीडिया जैसे कई क्षेत्रों के विषयों को इस उत्सव में जगह दी गई थी.

अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल

फेस्टिवल का आगाज मुख्य अतिथि प्रख्यात फिल्मकार मुज़फ्फर अली और उनकी पत्नी मीरा अली ने किया. इस दौरान मुज़फ्फर अली ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. साहित्य हमें आत्मीय बनाता है. इससे समाज को दिशा मिलती है. इस तरह के आयोजनों से समाज में अच्छा वातावरण बनता है. सार्थक विचार के मंच बाजार के युग में नज़र नहीं आते हैं, इसलिए इस तरह के मंच की आवश्यकता है. अजमेर की अपनी परंपरा है बावजूद इसके वह वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहा था. साहित्य जड़ों से पनपता है इसलिए लोगों को इस तरह के सम्मेलनों से जोड़ना जरूरी है, अजमेर साहित्य सम्मेलन का आयोजन इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है. आज देश का युवा इंटरनेट से जुड़ा है. उसे सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए साहित्य की ओर लाना होगा. इस तरह के आयोजनों से युवाओं को साहित्य की ओर वापस लाया जा सकता है. लोगों का किताबों से रोमांस कम हुआ है. लिटरेचर फेस्टिवल उस रोमांस को एक नई जान दे सकते हैं. जो शुरूआत हुई है उसमें सबसे बड़ी चुनौती उस विरासत को आगे लेकर जाने की है, साहित्य समाज की आत्मा होता है, जिस समाज में साहित्य नहीं होता है वह कंगाल होता है. अजमेर की धरती मानवता से प्रेम से जुड़ी हुई है, यहां जिस साहित्य का श्रृजन होगा वह मानवता से जुड़ा होगा. यही मानवता वाला साहित्य इस साहित्य उस्सव का रंग ढंग बनेगा. यहां वो लोग आएंगे जिनकी सांप्रदायिक सद्भाव में यकीन होगा. ये मुहब्बत की जमीन है यहां जो आएगा वह कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा. पुष्कर का भी अपना अलग रंग है, यह अगर साहित्य से जुड़ता है तो साहित्य को अलग-अलग रंग मिलेंगे. इस तरह के आयोजन से शहर को एक नई पहचान मिलेगी.

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की आवाज भी यहां से उठी. साहित्यकार पद्मश्री सी पी देवल ने कहा कि राजस्थानी भाषा संस्कृति का मूल है. लेकिन ग्यारह सौ साल पुरानी भाषा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है. देश के दूसरों राज्यों में भी अन्य भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा दौड़ में सबसे आगे है सरकार को महापात्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए. देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने, अच्छे दिनों की राजनीति राजनीति के अच्छे दिन जैसे मसलों पर विमर्श हुआ. राजनीति के अच्छे दिनों पर विमर्श करते हुए चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति अच्छे दिन कभी ला ही नहीं सकती. उन्होंने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ से लेकर वी पी सिंह के भ्रष्टाचार हटाओ के नारों का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ही नारे झूठे साबित हुए. और अब अच्छे दिनों की बात भी बेमानी साबित हो रही है.

कुल मिलाकर अजमेर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, आयोजक रास विहारी गौड़ और उनकी टीम इस आयोजन को विवादास्पद होने से बचते रहे लेकिन अंतिम दिन पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने अपने बयान से इस साहित्य उत्सव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया. वैदिक ने कहा कि यदि सरकार उन्हें जेल भेजना चाहती है तो वह तिहाड़ में अपने बगल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ से बात की थी, जो कारगिल में सैकड़ों जवानों की हत्या के दोषी माने जाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ब्रिटिश नेताओं के पास स्कॉटिश जनता को जोड़े रखने के लिए बहुत ज्योदा तर्क नहीं है. इसका मुख्य कारण यह है कि वहां की जनता काफी हद तक इस बात के पक्ष में है कि उन्हें एक अलग राष्ट्रत चाहिए. जब तकक ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में स्था पति रहा, ब्रिटेन के साथ जुड़े किसी भी क्षेत्र के लिए यह मांग कर पाना बहुत मुश्किल था. इस तरह की किसी भी मांग को बुरी तरह कुचल दिया गया लेकिन शायद अब ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं है. दुनिया अब एक नई सुबह देख चुकी है, जिसे लोकतंत्र कहते है.

साल्ट रिपोर्ट

अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों पर हमले

शफीक आलम

अब अमेरिका के राजनितिक हलकों में भी दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, खासकर मुसलमानों, हिन्दुओं, सिखों और अरब देशों के लोगों के प्रति घृणा की भावना की चाप सुनाई देने लगी है. हाल ही में साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग ट्गेदर (साल्ट) संस्था ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक इस समुदाय के लोग नफरत भरे माहौल में जीने पर मजबूर हैं. अंडर सस्पिशन, अंडर अटैक के नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में साल्ट ने जनवरी 2011 से मार्च 2014 तक अमेरिका की राजनितिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा नफरत भरी बयानबाज़ी और शाब्दिक आलोचना और अन्य घृणा अपराध की वारदातों को संकलित किया है. वैसे तो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में न्यूयॉर्क ट्रेड टावर पर 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद से ही दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ घृणा अपराध की वारदातें शुरू हो गईं थीं. लेकिन समय-समय पर इस में कमी-बेशी होती रहती. साल्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में ऐसी वारदातों में वृद्धि हुई है. इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने हालिया संबोधन में भी की है.

बहरहाल, साल्ट ने यह रिपोर्ट 2011 से 2014 के दरम्यान अखबारों में छपी उन ख़बरों के आधार पर तैयार की है जो नफरत के माहौल और राजनीतिक बयानबाज़ी पर आधारित थीं. साल्ट की 2010 की रिपोर्ट के मुकाबले में घृणा भरी राजनीतिक टिप्पणियों में सालाना 40 फीसदी की वृद्धि देखी गई. इस दौरान पूरे अमेरिका में ऐसी 157 घटनएं समाचार की सुर्ख़ियों में आईं. इनमें 78 मामले राजनीतिक बयानबाज़ी से संबंधित थे जबकि 76 मामले हिंसात्मक थे. इनमें से 90 फीसद राजनीतिक मामलों और 80 फीसद अपराधिक मामलों का संबंध मुस्लिम विरोध से था. ज़ाहिर है ऐसी वारदातों की वजह से इस समुदाय के लोगों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. साल्ट की रिपोर्ट में शामिल वह घटनाएं न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, शिकागो और इसके आसपास के क्षेत्र तथा दक्षिणी और उत्तरी कैलिफोर्निया से संबंधित हैं.

साल्ट की यह रिपोर्ट उस सच्चाई से पर्दा उठाती है कि हालिया कुछ वर्षों में अमेरिका और यूरोपीय देशों में मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर और दूसरे दक्षिण एशिया के समुदायों के खिलाफ आम तौर पर हिंसा की वारदातों में इजाफा हुआ है (देखें चौथी दुनिया का पिछला अंक). मिसाल के तौर पर पिछले दो महीने में न्यूयॉर्क शहर में नस्ली नफरत के तीन बड़े मामले सामने आये. न्यूयॉर्क वो शहर है जहां अलग-अलग जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. दी गार्जियन अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुकलिन में एक मुस्लिम महिला का पीछा कर उसका सिर कलम कर देने की धमकी दी गई, इसी महीने एक अमेरिकी सिख पर कुछ शरारती लोगों ने हमला किया और उसे ओसामा आतंकवादी कह कर फब्तियां कसीं. एक दूसरी घटना में एक सिख व्यक्ति को ट्रक से कुचल दिया गया.

अब सवाल यह उठता है कि क्या ये घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रहीं हैं कि दक्षिण एशिया के लोग एक जैसे दिखते हैं? या इसकी कोई और वजह है क्योंकि अमेरिका में बसे सिख समुदाय के लोगों ने पहले भी इस बात को साफ़ किया था कि सिख मज़हब एक अलग मज़हब है. इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं. कम से कम एक पढ़ा लिखा अमेरिकी एक मुसलमान और सिख के दरम्यान के फर्क को ज़रूर समझता है. अलबत्ता न्यूयॉर्क की मुस्लिम महिला के सिर कलम कर देने की धमकी की बात को आईएसआईएस की हालिया खुनी खेल से जोड़ कर देखा जा सकता है. साथ में यह सवाल भी उठता है कि अमेरिका जो अभिव्यक्ति कि आज़ादी, लोकतंत्र, मल्टी-कल्चरलिज़्म का सब से बड़ा पक्षधर है (और अमेरिकी संविधान भी अपने नागरिकों को ये अधिकार देता है) क्या अपने देश के अल्पसंख्यकों की हितों की अनदेखी करता रहेगा? यह बात और भी गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब तक इन मामलों की प्रकृति अपराधिक होती थी लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा है कि इससे शीघ्र ही चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है.

अमेरिका में अगर जातीय हिंसा के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो अक्सर यह देखा गया है की किसी बड़ी आतंकवादी घटना के बाद ऐसी जातीय हिंसा की वारदातें बढ़ जाती हैं. मुस्लिम विरोध के मामलों में 9/11 की घटना के बाद ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी. इस साल एफबीआई ने मुस्लिम विरोधी जातीय हिंसा के 481 मामले दर्ज किए थे, जो एक साल पहले के मुकाबले 1600 फीसद ज्यादा थे. साल्ट की 2014 की रिपोर्ट में इस तरह की हिंसा में हुई वृद्धि की एक बड़ी वजह आईएसआईएस की हालिया गतिविधियां थीं. लेकिन ऐसी हिंसा की वजह सिर्फ आतंकवादी घटनाएं हों ऐसा नहीं है क्योंकि अमेरिकी पादरी टेरी जोंस द्वारा 2010 कुरान जलाने की धमकी के बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा के मामलों में 50 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई थी. अमेरिका में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक सोच में वृद्धि की बात को अरब-अमेरिकन इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट भी तस्लीम करती है. हालांकि यह भी सच्चाई है कि अमेरिका में मुसलमानों के प्रति हिंसा का रवैया नया नहीं है 30 साल पहले जब ईरान में अमेरिकियों को बंधक बनाया गया था उस समय भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसात्मक प्रतिक्रिया हुई थी.

दक्षिण एशिया के लोगों के प्रति बढ़ती हुई नकारात्मक सोच और हिंसा के पीछे एक और हकीकत है जिसका ज़िक्र साल्ट की हालिया रिपोर्ट में किया गया है. इस रिपोर्ट में नेड रेस्निकोफ के हवाले से कहा गया है कि एशियन समुदाय अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रुप है. साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर आबादी में वृद्धि का यही रुझान रहा तो अगले 30 साल में सफ़ेद फाम लोगों की संख्या बाकी के लोगों से कम रह जाएगी. कहनी न कहीं यह हकीक़त भी दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ होने वाली जातीय प्रकृति के हमलों के पीछे है. मीडिया रिपोर्टिंग भी ऐसे हमलों में आग में घी का काम करती हैं.

बहरहाल, ऐसी वारदातें न तो अमेरिका जैसे बहुसांस्कृतिक देश, जहां का सविधान अपने नागरिकों को सामान अधिकार देता है वहीं अभिव्यक्ति की भी आज़ादी देता है, के लिए ठीक हैं और न ही एशियाई मूल के लोगों के लिए. अगर अमेरिका में इस तरह के जातीय हमले जारी रहे तो ज़ाहिर है यह उसके बुनियादी वसूलों के विपरीत होगा. वहीं एशियाई मूल के लोगों को भी कुछ पहल करनी चाहिए और दूसरी संस्कृतियों से बेहतर ताल मेल बनाने के लिए डायलाग शुरू करना चाहिए. ऐसे में राष्ट्रपति बराक ओबामा का यह बयान सराहनीय है कि एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीपवासी समुदाय की विविधताओं और विशिष्ट संस्कृतियों से भी अमेरिकी राष्ट्रीय जीवन का निर्माण होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अरुण तिवारी

ग्रेट ब्रिटेन से इंग्लैंड की ओर

ब्रिटेन को समझ आ जाना चाहिए कि अब औपनिवेशिक समय का दुनिया से अंत हो चुका है. उससे जुड़े देश ही अब अलग होने की मांग कर रहे हैं. बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में यूनाइटेड किंगडम के अपने महल में ब्रिटेन सिर्फ अकेला बचेगा क्योंकि जिन्हें जनता मानकर उसने अपने साथ मिलाया था अब वे ही सीना ठोंककर ये दावा करने लगे हैं कि तुम हमारे राजा नहीं. स्कॉटिश नेता एलेक्सच सेलमंड तो इस हद तक कहते हैं कि अगर ब्रिटेन अलग होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी. इसलिए यह वक्त है जब ब्रिटेन अपनी संसद में कश्मीर पर चर्चा कराने की बजाए अपने देश को बचाने की कवायद करे क्योंकि स्कॉटलैंड तो सिर्फ शुरुआतभर है...

सन 1690 के आस-पास स्कॉटलैंड आर्थिक कंगाली की अवस्था में आ गया था. उसकी ऐसी अवस्था इस वजह से हुई थी कि उसने पनामा के एक हिस्से-को उपनिवेश बनाने की कोशिश की थी. उसी दौरान वहां ऐसी स्थितियां भी बनी थीं कि जिसमें वे चाहते थे कि वे भी अपना अगला राजा चुनें और यह बात ब्रिटेन नहीं चाहता था. इन्हीं हालातों में दोनों देशों के साथ-साथ आने की तैयारियां शुरू हो गईं जिसने 01 मई 1707 को मूर्त रूप ले लिया. एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ और उसी दिन ग्रेटब्रिटेन की संसद का गठन भी हो गया. ब्रिटेन इसके बाद भी नहीं रुका. ब्रिटेन, ग्रेटब्रिटेन बना और फिर युनाइटेड किंगडम बनाने की तैयारियां शुरू हो गईं. इसी के तहत 1801 में ग्रेटब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाकर एक नया शक्तिशाली ध्रुव यूनाइटेड किंगडम यानी यूके तैयार हुआ.

अब सवाल यह उठता है कि साल 2012 में जब स्कॉक्टलैंड की आजादी के समर्थक नेता एलेक्स सेलमंड और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने साल 2014 में ही यह जनमत संग्रह के लिए कागजातों पर हस्तादक्षर क्यों किए थे? दरअसल इस साल स्कॉटलैंड के लोग बानोकबर्न युद्ध की 700 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. यह युद्ध 1314 में हुआ था. तब रोबर्ट द ब्रूस ने अंग्रेजी सेना पर शानदार जीत दर्ज की थी. यह बात जरूर एलेक्स सेलमंड के दिमाग में रही होगी जिससे वे लोगों में इस बात की भावना पैदा कर सकें कि हम एक बार फिर आजाद हो सकते हैं और इंग्लैंड को हरा सकते हैं जहां इंग्लैंड के नेता और मीडिया इस विभाजन का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं वहीं स्कॉटलैंड के अखबार पूरी तरह से स्वतंत्र स्कॉटलैंड के पक्षधर नजर आ रहे हैं.

असल में ब्रिटेन टूट सकता है यह तो बहुत पहले से लगने लगा था. पिछली सदी के चालीस, पचास और साठ के दशक में जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनियाभर के अलग-अलग देशों से उखड़ना शुरू हो गया था तो उसके बाद से दबी जुबान में ब्रिटेन के भीतर अलगाव की चिंगारी सुलगने लगी थी. ब्रिटेन के कई हिस्से सालों से अलग होने की मांग कर रहे है. वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को अंग्रेज लोग दबाए हुए है. सिर्फ इतना ही नहीं इन जगहों पर अंग्रेजी भाषा के दबदबे ने यहां के रहने वालों को शिक्षा, राजनीति, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में पछाड़ दिया है. ब्रिटेन भले ही दुनिया से तो सत्ताच्युत हो गया लेकिन सत्ता का चस्का उसे अपने ही लोगों के साथ ज्यादती करने से नहीं रोक सका. इन्हीं सब कारणों की वजह से साल 2011 में स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग करनेवाली राजनीतिक पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड में सत्तारूढ़ हो गई.

इस पार्टी के सत्ता में आते ही स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग ने ऐसा जोर पकड़ा कि नौबत यहां तक आ पहुंची. पार्टी का कहना है कि पचास लाख की आबादी वाले स्कॉटलैंड के पास तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है कि वह यूरोप का सबसे अमीर देश बन सकने की कूवत रखता है लेकिन ब्रिटेन की वजह से ऐसा हो पाने में दिक्कत आ रही है. अभी उसकी प्रति व्यक्ति आय ब्रिटिश नागरिक से 20 प्रतिशत ज्यादा है. यूनाइटेड किंगडम टूट के कगार पर आ गया है. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और उपप्रधानमंत्री निक क्लेग ने स्कॉटिश जनता को समझाने की भरसक कोशिश की.

स्कॉटलैंड के लोगों में ब्रिटिश महारानी के विशेष सम्मान है.

ब्रिटिश नेताओं के लिए और दिक्कत की बात यह हो गई कि महारानी ने इस मसले पर किसी भी तरह की कोई भी अपील करने से मना कर दिया. इससे पहले एकबार महारानी की मार्मिक अपील पर ही बंटवारे को टाला जा सका था लेकिन इस बार महारानी भी इस दिशा में शायद ही कुछ करने के मूड में है. इस पूरे आंदोलन में दोनों ही तरफ कई नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की है. जहां स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग को हॉलीवुड अभिनेता शीन कॉनरे और जेराड बटलर का समर्थन प्राप्त है तो वहीं एकीकृत यूके के लिए हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जे के राउलिंग ने 01 मिलियन पाउंड का डोनेशन दिया है. वहीं 200 नामी हस्तियों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, इसमें जूडी डेंच भी शामिल है.

ब्रिटिश नेताओं के पास स्कॉटिश जनता को जोड़े रखने के लिए बहुत ज्यादा तर्क नहीं है. इसका मुख्य कारण यह है कि वहां की जनता काफी हद तक इस बात के पक्ष में है कि उन्हें एक अलग राष्ट्र चाहिए. जब तक ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में स्थापित रहा, ब्रिटेन के साथ जुड़े किसी भी क्षेत्र के लिए यह मांग कर पाना बहुत मुश्किल था. इस तरह की किसी भी मांग को बुरी तरह कुचल दिया गया लेकिन शायद अब ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं है. दुनिया अब एक नई सुबह देख चुकी है, जिसे लोकतंत्र कहते है. पूरी दुनिया को औपनिवेशिक संस्कृति देने वाला ब्रिटेन भी अब उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल है जिसमें उसके साम्राज्य से जुड़ा हिस्सा ही उससे अलग होने की मांग कर रहा है. ब्रिटेन के लिए चिंता की बात तो यह है कि यह है स्कॉटलैंड के अलग होने ही उत्तरी आयरलैंड और वेल्श भी अलग होने की मांग कर सकते हैं.

उत्तरी आयरलैंड में तो इसकी चिंगारी सुलग भी चुकी है. स्कॉटलैंड के अलगाव से ब्रिटेन के सामने सब से बड़ा सवाल ईंधन का पैदा होगा. क्योंकि आज तो ब्रिटेन को 90 प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति स्कॉटलैंड ही करता है. आज जो स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अधीन है वही आने वाले समय में स्कॉटलैंड के अधीन हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. जिस ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी एकता और दृढ़ता के लिये अनेक देशों को तोड़ा वह अब अपने ही एक प्रदेश की अंगड़ाई से स्वयं टूट जाए तो यह नई अर्थ व्यवस्था का चमत्कार होगा.

ब्रिटेन को अपनी उस मानसिकता में बाहर निकलना होगा जिसमें वह पूरी दुनिया का शासन करता था. हाल में उसने कश्मीर पर अपनी संसद में डीबेट कराई जिसमें उसने चिंता जाहिर की कि विश्व की शांति के लिए कश्मीर में भी शांति होना आवश्यक है. हालांकि उसने इस मसले पर मध्यस्थता करने से मना कर दिया लेकिन उसे पहले अपने देश को संभालने पर ज्यादा देना चाहिए न कि दूसरों के मसले पर संसद में बहस करानी चाहिए. ब्रिटेन को यह समझना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही संप्रभु राष्ट्र हैं और अपनी समस्यायें हल करने में पूरी तरह सक्षम भी है. ब्रिटेन की इस हरकत का भारत ने विरोध भी किया था. क्योंकि यह एक गलत परिपाटी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

गुरु जी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले. उसने ऐसा ही किया नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया. कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं.

साई बाबा के सत्य वचन

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा के दिए गए वचनों पर भक्त चलें, उनका सदा ही कल्याण होगा. जब तक किसी का किसी से कोई संबंध न हो, तो कोई किसी के समीप नहीं जाता है. बाबा कहते हैं कि कोई तुम्हारे पास आए तो उसके साथ असभ्यता नही करनी चाहिए. उसका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए. यदि भूखे को खाना, प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र और आगन्तुक को सहारा दोगे, तो भगवान श्री हरि तुमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और तुम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखेंगे. बाबा का कहना है कि कोई कितनी भी निंदा करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो. इसी प्रकार ऐसे प्रसंगगों से सदैव बचते रहे, तो सदैव सुखी रहोगे. एक को दूसरे से अलग रखने वाली प्रवृत्ति को नष्ट करनी देनी चाहिए, जिससे सभी प्रमे पूर्वक एक साथ रह सकें. अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षणकर्ता नहीं है.

ईश्वर की कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है. उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं. वे ही मार्ग-प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं. मनुष्य को परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए. जिन लोगों ने अपने जीवन का ध्येय (ईश्वर दर्शन) पा लिया है, वही धन्य और सुखी है.

यह ध्यान देने योग्य बात है कि साई बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे. इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक उनके शरण जाएं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक संकटों में हमारी किस प्रकार मदद करते हैं.

यदि प्रात:काल हमारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि हम उसकी पुष्टि दिनभर करें तो वह हमारा विवेक अत्यन्त विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा. साई बाबा उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा नहीं करते थे, वह स्वतंत्रतापूर्वक उपदेश दिया करते थे. एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे. गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के खिलाफ कटुशब्दों का प्रयोग करने लगा.

निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साई बाबा का तरीक अलग था. वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए.

बाबा की दोपहर में जब लेण्डी के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है. तुम भी जी भर कर अपने भाइयों को सदाअपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है. अनेक शुभ कर्मों के परिणामस्वरुप ही तुम्हें मानव-तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो मैं तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकूंगा. कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया. इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे. यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए, तो आध्यात्म की प्राप्ति अधिक दूर नहीं रह जाएगी. एक कहावत है कि यदि मेरा श्री हरि होगा, तो वह मुझे चारपाई पर बैठे-बैठे ही भोजन पहुंचाएगा. यह कहावत भोजन और वस्त्र के लिए सच हो सकती है, लेकिन यदि कोई इस प्रकार आलस्यपूर्वक बैठा रहा, तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर उलट पतन के घोर अंधकार में चला जाएगा. इसलिए आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए सभी को सर्वथा परिश्रम करना चाहिए. जितना प्रयत्न करोगे, उतना ही लाभप्रद होगा.

बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. इसलिये जो भक्त अनन्य भाव से साई शरण आए और जिन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, वे सदा ही प्रसन्न रहे.

जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें. दुख देने वाले कटु शब्दों का प्रयोग से किसी को दुख न पहुंचाकर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनन्य भाव से भयरहित होकर उनकी शरण जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास के साथ उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व केसमस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. इसलिये जो भक्त अनन्य भाव से साई शरण आए और जिन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, वे सदा ही प्रसन्न रहे. जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें.

साई के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाटकों की दुनिया

सीमेंट का काला गोरखधंधा बंद हो

सभी जानते हैं कि 2लाख76 हजार करोड़ के कोयले घोटाले का पर्दाफाश चौथी दुनिया ने किया था और कांग्रेस को अपने घोटालों के कारण लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस केवल लोकसभा चुनाव 44 सीटें ही जीत पाई. चौथी दुनिया ने अपने 28 जुलाई-03 अगस्त 2014 के अंक में एक बार फिर बड़ा विषय उठाया है, जिसका सीधा जुड़ाव आम आदमी के जान-माल से है. सीमेंट ही नहीं बहुत सारी नकली चीजें देश खुलेवाम बेचीं जा रही हैं. ब्रांड के नाम पर नकली सामान शहर के बाहर गांव, कस्बे, तहसीलों के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे है. नकली सीमेंट देश में बन रहे पुल, गगन चुंबी इमारतों के लिए खतरनाक है और उसमें रह रहे करोड़ों लोगो के जान-माल को भी खतरा है. प्रभात रंजन दीन का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सीमेंट के काले कारोबार व उनसे जुड़ी नामी कंपनियों, नौकरशाहो व राजनेताओं के सिंडीकेट की सांठगाठ का मुद्दा उठाया. इस गिरोह में बिना बड़े लोगों के शामिल हुए इतने बड़े काला बाजारी का धंधा नहीं हो सकता. सरकार को नकली सीमेंट का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

- राजेन्द्र शुक्ल, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

हमारा बिहार

अब दो विपरीत ध्रुव नीतीश-लालू को एक मंच पर देखकर पूरे बिहार की जनता चिंतन के लिए बिहार लिए बाध्य हो गई है. आज हमारा बिहार जहां है, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान है, तो निश्चित रूप से वह नीतीश हैं. जनतंत्र और गठबंधन की राजनीति की तमाम कमियों, सीमाओं एवं खामियों के बावजूद नीतीश ने बिहार को पिछड़ेपन के अंधेरी गली से बाहर निकाला,लेकिन अचानक विरोधी खेमें में खड़े हो गए. फिर भी सुशासन-कुशासन का मेल निश्चित रूप से बिहार के लिए कोई शुभ संकते नहीं दे रहा है. कुछ लोग इस मेल को मंडल की राजनीति में वापसी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता जैसा देख रहे हैं, तो यकीनन वे लोग खुद को धोखा दे रहे हैं. 21 वीं सदी का बिहार व देश मंडल-कमंडल की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है. बहरहाल मेरा मानना है कि इस गठबंधन से सबसे अधिक नुकसान नीतीश को ही होगा. अचम्भा होता है कि जिस लालू के जंगल राज के खिलाफ नीतीश ने सत्ता को हासिल किया और फिर अपनी खुली आंखों से सब देखते हुए उसी तुफान के भंवर में चले गए. इस गठबंधन से लालू प्रसाद यादव फायदे में हैं. नीतीश के द्वारा ही बानए गए मुख्यमंत्री मांझी के घूस देने के बयान ने पूरे बिहार का एक नंगा सच पूरे देश के समक्ष लाकर रख दिया. नरेंद्र मोदी ने संस्कृतिनिष्ठ राजनीति की जन अकांक्षा को परवान चढ़ाया और 2014 के जनादेश ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया. अब बिहार के लोग निश्चित रूप से सोचेंगे कि वे किधर जाएं.बिहार के लोग मानते हैं और जानते हैं कि सस्कृति बिहीन राजनीति केवल कोरी सत्ता पिपासा है.

-अशोक निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

साइबर क्राइम

भारत में इंटरनेट यूजरों का इजाफा दिन-प्रतिदिन होता ही जा रहा है और इसके साइबर क्राइम में भी बृद्धि हो रही है. लोगों में डाटा की गोपनीयता और इस संबंध में बने काननों को लेकर जागरूकता का अभाव है. जिसके कारण लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं. वित्तीय क्षेत्र की खुफिया जानकारी देने वाली फर्म अल्ट्रास्कैन में हाल ही में एक अनुमानत: रिपोर्ट आई है कि सन् 2013 में भरतीयों ने लगभग 85 करोड़ डॉलर की राशि उन धोखाधड़ी करने वालों को दे दी, जो लोगों के खाते में भारी भरकम रकम स्थानातरित करने के बहाने उसके पूर्व कुछ एडवांस शुल्क मांगते हैं. लॉटरी देने आदि के नाम पर भी लोगों से पते, बैंक खाता नंबर, पैन नंबर समेत व्यक्तिगत जानकारी लेकर एक निश्चित रकम किसी ऐसे खाते में जमा करने को कहा जाता है, जो उन साइबर क्राइमर का होता है. ऐसी रिपोर्ट है कि जब ऑनलाइन डाटा दूसरों को देने की बात सामने आती है, तो भारतीय सबसे आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं. हाल में एक सर्वे किया गया जिसमें भारतीय अपनी जानकारी आसानी से देने में नंबर एक पर रहे. कानून को प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाना होगा.

- अशोक निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

असंवेदनशील जनसेवक

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं और इसमें प्रकाशित आलेख दिल को छू लेने वाले एवं कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले होते हैं. समाचार पत्र के 25 अगस्त-31 अगस्त 2014 के अंक में पेज3 पर प्रकाशित आलेख लोग मरते रहे महामहिम व्यस्त हैं और पेज पांच पर प्रकाशित आलेख रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भारतीय नौसेना की हालत खस्ता पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है, लेकिन आलेख पढ़कर काफी कष्ट हुआ. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस देश में महामिहम द्वारा ऐसे संगीन मामलों की अनदेखी कर जनाधिकार का उपहास करना अत्यंत दुखद एवं गभीरता का विषय है. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाओं से वंचित लोगों की आवाज राष्ट्रपति भवन से कब तक टकराती रहेंगी. जहां नागरिक का एक वोट देश के भविष्य के लिए निर्णायक हो वहां जनता की अनदेखी करना लोकतंत्र का अपमान है. नौ सेना का खस्ता हाल का समाचार काफी संवेदनशील है. यह रक्षामंत्रियों द्वारा उसकी अवहेलना को दिखाता है कि किस प्रकार नवसेना की उपेक्षा की गई है. नौ सेना की अगर खस्ता हाल है, तो यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. देश की सुरक्षात्मक/आर्थिक व्यस्था में कोताही बरतने वालों को सारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए. जिससे बाद के रक्षा मंत्री बनने वाले लोग इससे प्रेरणा ले सकें.■

- श्याम बिहारी प्रसाद, *मुंगेर, बिहार.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कहानी

गुरु और शिष्य

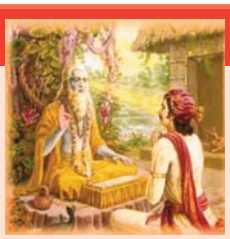

एक बार की बात है एक समृद्ध व्यापारी, जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला-गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूं, लेकिन हर समय मुझे लगता है कि वहां पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देवपूजन के साथ-साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, बेसहारा को सहारा मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें. सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले-केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ. व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने ने दो मंदिर, एक अपने गांव और दूसरा अपने नगर में, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दिए. दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए. लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है. उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भारी मन से वह गुरु जी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया. गुरु जी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले. उसने ऐसा ही किया नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया. कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं. अब तो उसे हैरानी के साथ-साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी. बिना एक क्षण की देरी के वह गुरुजी के पास जा कर हाथ जोड़ कर, कहने लगा आपकी आज्ञानुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गम्भीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन, कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके, नगर के देवालय में आने लगे हैं. मुझसे यह नहीं देखा जाता. व्यापारी की बात सुनते ही गुरु जी सारी बात समझ गए और बोले-हैरानी और परेशानी छोड़ो. दरअसल, जो गांव वाले पुजारी हैं, उनका अच्छा स्वभाव ही है जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं, जहां वे होते हैं. उनका लोगों से नि:स्वार्थ प्रेम, उनके दु:ख से दुखी होना , उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी और आकर्षित करता है और लोग स्वत: ही उनकी और खिंचे चले आते हैं. अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी. ■

शिक्षा-हमें सदा के सभी साथ प्रेम और आदर करना चाहिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

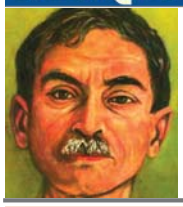

> जब किसी तरह न रहा गया, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया. कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था. जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी. अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता.

कॉकस के कब्जे में अकादमी

अनंत विजय

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनाने के बाद इस बात की आशंका तेज हो गई थी कि सांस्कृतिक संगठनों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति होगी. वामपंथी बुद्धिजीवी लगातार आशंका जता रहे हैं कि सांस्कृतिक संगठनों की स्वायत्तता ख़त्म करके सरकार उन पर कब्जा कर लेगी. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर संघ की पृष्ठभूमि के वाई सुदर्शन राव की नियुक्ति से इन आशंकाओं को बल भी मिला. दरअसल, इन सांस्कृतिक संगठनों पर लंबे समय से वामपंथी बुद्धिजीवियों का कब्जा रहा है. यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वामपंथी बुद्धिजीवियों ने उसका समर्थन किया था. दिल्ली में भीष्म साहनी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक में आपातकाल के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया था. उसके बाद इंदिरा गांधी ने पुरस्कार स्वरूप सांस्कृतिक संस्थाओं की कमान प्रगतिशीलों के हाथों में सौंप दी. प्रगतिशील जब बंटे, तो इन संस्थाओं का भी बंटवारा हुआ और कुछ लेखक जनवाद के फेरे में जा पहुंचे, लेकिन मूल विचारधारा वही रही. ईनाम में मिली मिल्कियत का जो हश्र होता है, वही इन साहित्यिक-सांस्कृतिक संगठनों का हुआ. यानी अंधा बांटे रेवड़ी, जमकर अपने-अपनों को दे.

1954 में जब साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी, तो कौशल विकास और शोध इसके प्रमुख उद्देश्य थे. तक़रीबन छह दशकों के बाद भी साहित्य अकादमी देश की सभी भाषाओं में शोध और कौशल विकास को अपेक्षित स्तर पर नहीं ले जा पाई. साहित्य और अन्य कला अकादमियां एक तरह से पुरस्कार, विदेश यात्रा, देश भर में गोष्ठियों के नाम पर अपने पसंदीदा लेखक-लेखिकाओं को घुमाने वाली ट्रैवल एजेंसी या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मात्र बनकर रह गई हैं. साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव पर यात्रा भत्ता में घपले के आरोप समेत कई संगीन इल्जाम लगे थे. उन्हें मुअत्तल किया गया. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी गई थी. जांच के दौरान ही सचिव रिटायर हो गए और तिवारी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बन गए. जांच कहां तक पहुंची या फिर क्या कार्रवाई की गई, यह सार्वजनिक नहीं हुआ. इसके पहले भी गोपीचंद नारंग के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहते उन पर अपने कार्यालय की साज-सज्जा पर फिजूलखर्ची के आरोप लगे थे. यह हाल सिर्फ़ साहित्य अकादमी का नहीं है. ललित कला अकादमी ने अपने पूर्व अध्यक्ष के आर सुब्बन्ना समेत 21 कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन सभी पर अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं. संगीत नाटक अकादमी के एक सचिव का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिशासी बोर्ड ने फ़ैसला ले लिया था. बाद में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपनी राय दी कि यह नियुक्ति ग़ैर क़ानूनी तरीके से की गई थी.

इन स्थितियों से इस बात के पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि हमारे देश के सांस्कृतिक संगठनों में स्वायत्तता की आड़ में कुछ गड़बड़ चल रहा है. 17 दिसंबर, 2013 को संसद के दोनों सदनों में सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी के अलावा इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कामकाज पर टिप्पणियां की गई थीं. येचुरी समिति ने साफ़ तौर पर कहा कि देश की ये अकादमियां निहित स्वार्थों को साधने का अड्डा बन गई हैं. अपने प्रतिवेदन मे संसदीय समिति ने लिखा, समिति यह अनुभव करती है कि कला एवं संस्कृति अभिन्न रूप से हमारी परंपराओं से जुड़ी हैं और इन्हें एक विकास और आवयविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए. साथ ही ये केवल अतीत की वस्तु नहीं हैं, इनका वर्तमान और भविष्य के साथ निकट सह-संबंध है. अत: समिति यह सिफारिश करती है कि संस्कृति को उसके समग्र रूप में समझने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है, जब हमारे उत्कृष्ट सांस्कृतिक संगठनों, जैसे विभिन्न अकादमियों के बीच समुचित समन्वय और सह-क्रिया हो. समिति ने यह भी माना था कि अनुवाद के काम स्तरीय नहीं हो रहे हैं. समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, साहित्य अकादमी के पुरस्कारों में पारदर्शिता का अभाव है. अब अगर हम वर्तमान में साहित्य अकादमी में हिंदी की बात करें, तो इसके जो संयोजक हैं, उनका साहित्य को योगदान अभी तक ज्ञात नहीं है, पर वह हिंदी की दशा-दिशा तय करते हैं, रिमोट चाहे जिनके भी हाथ में हो. यह बात भी सामने आई कि साहित्य अकादमी में वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है. इस तरह की अनियमितताओं के आरोप साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी पर भी लगते रहे हैं और लग रहे हैं. साहित्य अकादमी के संविधान के मुताबिक उसके अध्यक्ष को असीमित अधिकार हैं. कई बार इन अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं. साहित्य अकादमी में तो अनुवाद का इतना बुरा हाल है कि पारिश्रमिक का भुगतान होने के बाद भी अनुवादकों को किताब छपने के लिए दस-दस साल तक इंतजार करना पड़ता है. संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि साहित्य अकादमी साल भर में तक़रीबन चार सौ सेमिनार आयोजित करती है. बेहतर होता कि संसदीय समिति के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विस्तार से प्रकाश डालते कि कितने कार्यक्रम दिल्ली में अकादमी के सेमिनार हॉल में हुए और कितने बाहर. इसी तरह ललित कला अकादमी में भी कलाकारों के साथ भेदभाव किया जाता है. ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब ललित कला अकादमी पर कला दीर्घा की बुकिंग के आवेदन भी धारा और विचारधारा के आधार पर खारिज करने का आरोप लगा था. सवाल यह है कि क्या देश की सांस्कृतिक संस्थाएं किसी खास विचारधारा की पोषक और किसी खास विचारधारा की राह में बाधा बन सकती हैं?

अकादमियों की इन बदइंतजामियों के बारे में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 56 में लिखा, समिति यह दृढ़ता से महसूस करती है कि ऐसी स्थिति बनाए नहीं रखी जा सकती है और इन अकादमियों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ करने का यह सही समय है. समिति यह महसूस करती है कि इन निकायों को भारत की समेकित निधि से धनराशि प्राप्त होती है और इस संसदीय समिति की सिफारिशों पर इनकी ममनदान मांगों को संसद द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुमोदित किया जाता है. अत: यह समिति पूरी ज़िम्मेदारी से कहती है कि इन संस्थाओं को आवंटित निधियों और इनके कार्य निष्पादन का लेखा परीक्षण करके प्रत्येक वर्ष गहन एवं नियमित अनुवीक्षण किए जाने की आवश्यकता है. सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए. ये समीक्षाएं बाहरी व्यक्तियों एवं समितियों द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल किया जाना चाहिए. बाद में उन्हें संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए. इस तरह की कठोर टिप्पणियों से यह संदेश जा सकता है कि संसदीय समिति इन अकादमियों की स्वायत्तता को ख़त्म करना चाहती है. संसदीय समिति की इस रिपोर्ट के बाद जनवरी 2014 में यूपीए सरकार के दौरान अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया. अकादमियों के कामकाज की समीक्षा के बारे में 1988 में हक्सर कमेटी बनी थी और तक़रीबन 25 साल बाद अब सेन कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें नामवर सिंह, रतन थियम, सुषमा यादव, ओ पी जैन आदि सदस्य थे. इस कमेटी को इन अकादमियों के संविधान और कामकाज में बदलाव को लेकर सुझाव देने थे. इसने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की. लगभग सवा सौ पृष्ठों की रिपोर्ट में इस कमेटी ने भी माना कि इन अकादमियों में जमकर गड़बड़झाले को अंजाम दिया जा रहा है. इस हाई पावर कमेटी ने माना कि साहित्य अकादमी की आम सभा में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने के बावजूद स्तरीय शोध नहीं होते हैं. इस कमेटी ने अकादमी के अध्यक्ष का चुनाव विशेषज्ञों की एक समिति से कराने की सिफारिश की है. इसके अलावा अकादमी के अध्यक्ष और अन्य कमेटियों के अध्यक्षों की उम्र सीमा भी 70 साल करने, उपाध्यक्ष का पद बेकार मानते हुए उसे ख़त्म करने और सचिव का कार्यकाल तीन साल करने की सिफारिश की गई है. एक टैलेंट पूल की वकालत की गई है. तीनों अकादमियों की लाइब्रेरी को मिलाकर एक करने का सुझाव भी दिया गया है. यहां याद दिलाते चलें कि यह सब कुछ यूपीए सरकार के दौरान हुआ है.

सेन कमेटी की इन सिफारिशों को लेकर साहित्य अकादमी के अंदर खलबली मची हुई है. इसे अकादमी की स्वायत्तता पर हमले के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है. संभव है कि एनडीए सरकार की मंशा भी ऐसी हो. साहित्य अकादमी की गंभीरता समझने के लिए पिछले दिनों गुवाहाटी में हुई सामान्य सभा की बैठक पर गौर फरमाना होगा. सेन कमेटी समेत अन्य मुद्दों पर 22 अगस्त को सामान्य सभा की बैठक होनी थी. पूर्वान्ह साढ़े ग्यारह बजे का वक्त तय था. बैठक सवा बारह बजे शुरू हुई. बैठक में एक-दो वक्ताओं ने सेन कमेटी की सिफारिशों पर ज्ञान दिया और फिर हाथ उठाकर पहले से तैयार किए गए एजेंडे को स्वीकृति. दरअसल, अगर हम साहित्य अकादमी के क्रियाकलापों पर नज़र डालें, तो यह देखकर तकलीफ होती है कि वहां किस तरह से स्वायत्तता के नाम पर प्रतिभाहीनता को बढ़ावा दिया जा रहा है. साहित्य अकादमी अपनी स्थापना की मूल अवधारणा से भटक गई प्रतीत होती है. साहित्य अकादमी समेत अन्य केंद्रीय अकादमियों की स्वायत्तता का मोदी सरकार अगर अतिक्रमण करती है, तो इसके लिए हाल के वर्षों में वहां काबिज रहे रहनुमाओं की भी थोड़ी-बहुत ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह सवाल तो खड़ा होगा ही कि जिन संस्थाओं पर देश भर के साहित्य-संस्कृति को वैश्विक फलक पर ले जाने की ज़िम्मेदारी थी, वे आख़िर कहां तक सफल रही हैं. अशोक वाजपेयी एवं नमिता गोखले की संयुक्त पहल और संकल्पना-इंडियन लिटरेचर अब्रॉड का क्या हुआ, इस बारे में भी जानकारी बाहर आनी शेष है. स्वायत्तता के नाम पर इस अराजकता पर कहीं न कहीं तो पूर्ण विराम लगाना ही होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

ग़ज़ल

-आदिल सरफरोश

बसंत याद है वो बरसात याद है,
हमें इस शहर की हर बात याद है.
नहीं भूल सकता मैं तस्वीर जिसकी,
वो पहली-पहली मुलाकात याद है.
दिन भूल गए तुम मेरे साथ गुज़रे,
हमें हर शाम और हर रात याद है.
नहीं देखते हैं कभी पीछे मुड़कर,
मगर आज भी अपनी औकात याद है.
उसे याद करके फिर छलकते हैं आंसू,
मुफलिसी के अपने हालात याद है.
लूटते थे सिक्के फिर देकर दुआएं,
गली से निकलती बारात याद है.
मेहनत से मुश्किल कुछ भी नहीं है,
दिल में उठता वो जज्बात याद है.

कहानी

पूस की रात

प्रख्यात कथाकार-उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी कई घटनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया, जो किसी भी संवेदनशील शख्स को अंदर तक हिला देने में सक्षम हैं. कहानी पूस की रात इस बात का प्रमाण है. वह यह बताती है कि मौसम भी ग़रीबों-वंचितों की किस कदर परीक्षा लेता है.

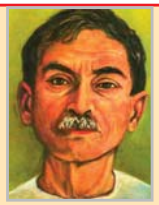

हल्कू ने आकर पत्नी से कहा, सहना (साहूकार) आया है. लाओ जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूं, किसी तरह गला छूटे. मुन्नी झाड़ू लगा रही थी. बोली, तीन ही तो रुपये हैं. दे दोगे, तो कम्मल (कंबल) कहां से आएगा? माघ-पूस की रात हार (खेत) में कैसे कटेगी? कह दो, फसल पर दे देंगे. हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा. पूस सिर पर आ गया, कम्मल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता. मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा. बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी. यह सोचता हुआ वह अपना भारी-भरकम डील लिए हुए (जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था) पत्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे. कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा.

मुन्नी आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय! जरा सुनूं तो कौन-सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई. बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जनम हुआ है. पेट के लिए मजूरी करो. ऐसी खेती से बाज आए. मैं रुपये न दूंगी, न दूंगी. हल्कू उदास होकर बोला, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं. हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था. उसने आले (ताख) से रुपये निकाले और लाकर हल्कू को दे दिए. फिर बोली, तुम छोड़ दो अबकी से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी. अच्छी खेती है! मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस. हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो. उसने मजूरी से एक-एक पैसा काट-कपट कर तीन रुपये कम्मल के लिए जमा किए थे. वह आज निकले जा रहे थे. एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था.

पूस की अंधेरी रात! आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे. हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पतों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था. खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था. दो में से एक को भी नींद न आती थी. हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रह, तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे, मैं यहां हलुवा-पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े-दौड़े आगे-आगे चले आए. अब रोओ नानी के नाम को. जबरा ने पड़े-पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं-कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया. उसकी श्वान-बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं-कूं से नींद नहीं आ रही है. हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे. यह रांड पछुआ न जाने कहां से बरफ लिए आ रही है. उठूं, फिर एक चिलम भरूं. किसी तरह रात तो कटे! आठ चिलम तो पी चुका. यह खेती का मजा है! और एक-एक भगवान ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाए, तो गरमी से घबरा कर भागे. मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ-कम्मल. मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए. तकदीर की खूबी! मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!

हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा-सी आग निकाल कर चिलम भरी. जबरा भी उठ बैठा. हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है. जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा. हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा. उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा. जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया. हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी. चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अबकी सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा. कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था.

जब किसी तरह न रहा गया, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया. कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था. जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी. अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता. वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया. इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था. सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई. इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोकों को तुच्छ समझती थी. वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा. हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया. हार में चारों तरफ़ दौड़-दौड़कर भूंकता रहा. एक क्षण के लिए आ भी जाता, तो तुरंत ही फिर दौड़ता. कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था. ***क्रमशः***

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

सैमसंग का दमदार फैबलेट गैलेक्सी नोट 4

सैमसंग ने अपने प्रीमियम फैबलेट सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 की बिक्री शुरू कर दी है. यह प्रीमियम फैबलेट अपनी श्रेणी में कंपनी का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट है. इसकी कीमत लगभग 56,000 रुपये है. सैमसंग नोट4 में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 3.7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फ्रंट कैमरे में 120 डिग्री वाइड ऐंगल शॉट है. इसकी बैटरी भी पिछले मॉडल की तुलना में 7.5 फीसद अधिक चलती है. इसमें 3220 एमएएच की बैटरी लगी हुई है. इसकी बैटरी केवल 30 मिनट में 50फीसद चार्ज हो जाती है. इसकी स्क्रीन 5.7 इंच की है. इसकी मेमोरी 32 जीबी की है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड जरिए 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 3जीबी का रैम है.■

सैमसंग गैलेक्सी एस5 मिनी भारत में लॉन्च

इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. 2.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. 16 जीबी इंटरनल मेमोरी है और 64 जीबी तक माइक्रो-एसडी कार्ड लगाया जा सकता है.

सैमसंग गैलेक्सी 5 मिनी भारत में उतारा गया है और इसकी कीमत 26499 रुपए है. यह ऐंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर चलता है. इसमें 720 गुणा1280 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 4.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है. 1.4 गीगाहर्ज क्वॉड-कोर प्रोसेसर और 1.5 जीबी रैम है. इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. 2.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. 16 जीबी इंटरनल मेमोरी है और 64 जीबी तक माइक्रो-एसडी कार्ड लगाया जा सकता है. बैटरी 2100एमएएच की है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाई-फाई, ब्लूटुथ 4.0, माइक्रो-यूएसबी, ए-जीपीएस, 3जी और आईआर रिमोट शामिल हैं. यह फिलहाल काले, सफेद, नीले और सुनहरे रंग में उपलब्ध है.■

बुलेट के लुक में नई स्पलेंडर प्रो क्लासिक

टूव्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई सबसे अनोखी और स्टाइलिश बाइक स्पलेंडर प्रो क्लासिक को लॉन्च किया है. नई हीरो स्पलेंडर प्रो क्लासिक की कीमत लगभग 53,900 रुपए है. इस रेंज में स्पलेंडर प्रो क्लासिक 100सीसी में हीरो मोटोकॉर्प का टॉप मॉडल है. हीरो स्पलेंडर प्रो क्लासिक क्रूजर और कम्प्यूटर बाइक्स का मिलजुला रूप है.

इसकी सीट रॉयल एनफील्ड कॉन्टीनेंटल जीटी535 से मिलती-जुलती है. हीरो मोटोकॉर्प प्रो स्लासिक में सिंगल पीस सीट, राउंड हेडलाइट और रियर व्यू मिरर, स्पॉक व्हील्स, राउंड शेप्ड डेशबॉर्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी इस स्टाइलिश बाइक में 92.2 सीसी, सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है जो 7.7 बीएचपी का पावर और 8.4 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये बाइक 4 स्पीड गियरबॉक्स पर है.■

एप्पल आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस और एप्पल वॉच

यह स्मार्टवॉच आईफोन के साथी डिवाइस के रूप में काम करेगा. यह नए आईफोन 6 और 6 प्लस केअलावा आईफोन 5सी, 5एस और 5 के साथ भी काम करेगा. यह अगले साल बाजार में आएगा. इसे दो साइज में लॉन्च किया गया है. साथ ही इसमें कई अलग तरह के वॉच फेसेज और बदलने लायक स्ट्रैप होंगे. एप्पल वॉच, एप्पल वॉच स्पोर्ट्स और एप्पल वॉच एडिशन में लॉन्च किया गया है.

एप्पल ने अपने दो नए स्मार्टफोन आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस लॉन्च किए हैं. इसके साथ ही कंपनी ने अपना पहला स्मार्टवॉच भी पेश किया है. दोनों ही नए आईफोन अब तक के आईफोन्स से आकार में बड़ हैं, लेकिन पतले हैं. जहां आईफोन 6 का स्क्रीन साइज़ 4.7 इंच है, वहीं आईफोन 6+ की स्क्रीन 5.5 इंच की है. आईफोन 6 का डिस्प्ले 1136 गुणा 640 पिक्सल का रेजोल्यूशन और आईफोन 6+ का डिस्प्ले 1920 गुणा 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. आईफोन6 लैंडस्कोप मोड को सपोर्ट करता है. दोनों फोन्स में हाई-स्क्रीन रेजोल्यूशन केलिए रेटिना एचडी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. एप्पल ने आईफोन 6 के साथ अपने 32 जीबी वेरिएंट को खत्म कर दिया है. यह फोन 16, 64 और 128 जीबी ऑप्शंस के साथ आएगा. आईफोन 6 और 6 प्लस अब तक एप्पल केसबसे पतले स्मार्टफोन हैं. इन दोनों आईफोन्स में बैटरी में और सुधार किया गया है और आईफोन 6 14 घंटे का 3जी टॉइटाइम और 10 घंटे का इंटरनेट ब्राउजिंग टाइम देने का दावा करता है. वहीं आईउोन6+ में 24 घंटे का 3जी टॉकटाइम और 12 घंटे की वेब ब्राउजिंग कर सकेंगे.इन दोनों नए फोन में 8एमपी आईसाइट कैमरा है और फेज डिटेक्शन फीचर है. कंपनी ने अपना स्मार्टवॉच एप्पल वॉच भी लॉन्च किया है. एप्पल ने आखिरकार इस डिवाइस के साथ वेअरेबल गैजेट्स के क्षेत्र में कदम रखा है.

यह स्मार्टवॉच आईफोन केसाथी डिवाइस के रूप में काम करेगा. यह नए आईफोन 6 और 6 प्लस केअलावा आईफोन 5सी, 5एस और 5 के साथ भी काम करेगा. यह अगले साल बाजार में आएगा. इसे दो साइज में लॉन्च किया गया है. साथ ही इसमें कई अलग तरह के वॉच फेसेज और बदलने लायक स्ट्रैप होंगे. एप्पल वॉच, एप्पल वॉच स्पोर्ट्स और एप्पल वॉच एडिशन में लॉन्च किया गया है. एडिशन 18 कैरट सोने का बना हुआ है. एप्पल वॉच 18 मॉडल्स में आएगा जिसमें लेदर, मेटल और स्पोर्ट्स बैंड ऑप्शन होंगे. स्पोर्ट्स और एडिशन वेरिएंट्स में 10-10 ऑप्शंस होंगे.

एप्पल वॉच फिटनेस और हेल्थ डिवाइस केतौर पर भी काम करेगा. इसमें लगे सेंसर्स इसे पहनने वाले केहेल्थ और फिटनेस से जुड़े डेटा जुटाने में मदद करेंगे. यह हार्टबीट भी माप सकेगा.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

टाटा मोटर्स ने उतारी नई एसयूवी

लैंड रोवर फ्रीलैंडर2 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 डीजल इंजन पर दौड़ती है. इसकी ताकत की बात करें तो ये 150पीएस पावर और 420एनएम टॉर्क जनरेट करती है.

टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी कॉम्पेक्ट कार लैंड रोवर फ्रीलैंडर2 का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. नई प्रीमियम एसयूवी की कीमत लगभग 44.41 लाख रुपए तय की गई है. कंपनी ने नए एडिशन केकुछ ही मॉडल बाजार में लॉन्च किए हैं.

लैंड रोवर फ्रीलैंडर2 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 डीजल इंजन पर दौड़ती है. इसकी ताकत की बात करें तो ये 150पीएस पावर और 420एनएम टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी इस कार के बाद लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट लॉन्च करने वाली है. इसमें सात (5+2) लोगों केबैठने की जगह है. लैंड रोवर की नई एसयूवी 9 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन केसाथ दौड़ती है. ये ऑल व्हील ड्राइव कार है. इस कार को यूके स्थिति लैंड रोवर डेवलपमेंट सेंटर में डिजाइन किया गया है.

कंपनी ने इसकेइंटीरियर में हाई क्वालिटी का मैटेरियल इस्तेमाल किया है. इस साथ शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है. कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है.■

लेनोवो ने लॉन्च किया नया पीसी लैपटॉप व टैबलेट

लेनोवो थिंकपैड हेलिक्स

लेनोवो थिंकपैड हेलिक्स एक टू-इन-वन प्रोडक्ट है जिसे खासतौर पर कंपनी जरूरतों केलिए बनाया गया है. इस पैड का वजन 1.35 किलो ग्राम है एवं यह 9.65 एमएम मोटा है. लेनोवो के थिंकपैड हेलिक्स में इंटेल कोर एम प्रोसेसर डाला गया है. इस थिंकपैड को आप पांच तरीकों से रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं- टैबलैट, स्टैंड, टेंट, लैपटॉप व डेस्कटॉप. थिंकपैड में 11.6 इंच का डिस्प्ले लगा है जिसे की-बोर्ड से अलग किया जा सकता है.

नए पीसी

लेनोवो की ओर से टेक शो के दौरान दो नए डेस्कटॉप पीसी-हॉरिजन 2एस व हॉरिजन 2ई टेबलटॉप पीसी लांच किए गए हैं. दोनों पीसी मॉडल में चौथी जेनेरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर मौजूद है व इसके साथ ही इसमें ब्लूटुथ, एनएफसी, डॉल्बी होम थिएटर साउंड व अच्छा बैटरी बैकअप जैसी विशेषताएं भी प्रदान की गई हैं.

पीसी के साथ लेनोवो द्वारा कुछ खास ऑफर्स भी मिलेंगे जैसे कि दोनों पीसी में लेनोवो ऑरा मल्टी-यूजर इंटरफेस, 40 से ज्यादा गेम्स व एजुकेशन एप्स, आदि. कंपनी अनुसार हॉरिजन 2ई कीमत 45,225 रुपये हो सकती है.

लेनोवो एज15

यह अब तक के लेनोवो द्वारा लांच किए गए सबसे पतले लैपटॉप में से एक है. ऐज15 केवल एक इंच मोटा है व इसका वजन 2.3 कि. ग्राम है. यह लैपटॉप 360 डिग्री की दिशा में घूम जाता है व इसकेकी-बोर्ड पर बैकलिट लाइट लगी है. लैपटॉप में 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले, चौथी जेनेरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर, बेहतरीन ग्राफिक्स, 8 घंटे चलने वाली बैटरी व 1 टेराबाइट तक मिलने वाला हार्ड ड्राइव स्टोरेज मिल सकता है.

लेनोवो एस5000 टैबलेट

लेनेवो ने एक और टैबलेट लांच किया गया है. लेनोवो एस5000 नाम का टैबलेट 7 इंच डिस्प्ले, 1280 गुणा 800 पिक्सल रेजोल्यूशन, 246 ग्राम वजन, 1जीबी रैम व 16जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ आया है.

इसके अलावा टैबलेट में 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 1.6 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन व 3450 एमएएच की बैटरी मौजूद है.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सानिया के लिए साल-2014 अच्छा रहा है वह इस साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में रोमानिया के होरिया तेकाउ के साथ पहुंची थीं. लेकिन ख़िताबी जीत हासिल नहीं कर सकीं थीं. अमेरिकी ओपन के महिला युगल में भी सानिया जिम्बाब्वे की कार्ला ब्लैक के साथ सेमीफाइनल पहुंची थीं. सानिया का यूएस ओपन में डबल धमाका करने का सपना टूट गया. लेकिन उन्होंने मिक्स डबल्स का ख़िताब जीतकर इतिहास रच दिया.

शाबाश सानिया!

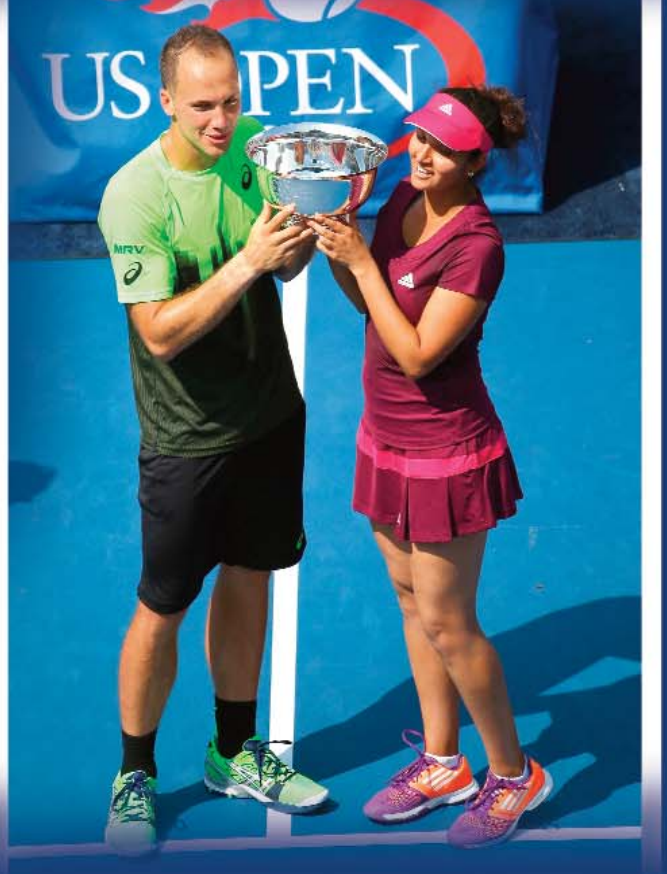

चौथी दुनिया ब्यूरो

हाल ही में संपन्न हुई साल की आख़िरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में सानिया मिर्जा ने इतिहास रच दिया है. देश की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के साथ मिक्स डबल्स का ख़िताब जीता है, सानिया का यह तीसरा मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम ख़िताब है. वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने से महज एक कदम की दूरी पर हैं. इससे पहले सानिया ने हम वतन महेश भूपति के साथ साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन का ख़िताब जीत चुकी हैं. फाइनल मुक़बले में मिर्ज़ा और सोरेस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अमेरिका की एबिलेक स्पीयर्स और मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेस की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 2-6 और 11-9 से मात दी. जीत के बाद सानिया ने कहा कि वह एक दिन विंबलडन जीतने में जरूर कामयाब होंगी और करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करेंगी. सानिया सोरेस के साथ पहली बार खेल रही थीं, जीत के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें सोरेस के साथ खेलने में मजा आ रहा है और वह अगले साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भी सोरेस के साथ खेलती दिखाई देंगी.

सानिया के लिए साल-2014 अच्छा रहा है. वह इस साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में रोमानिया के होरिया तेकाउ के साथ पहुंची थीं. लेकिन ख़िताबी जीत हासिल नहीं कर सकीं थीं. अमेरिकी ओपन के महिला युगल में भी सानिया जिम्बाब्वे की कार्ला ब्लैक के साथ सेमीफाइनल पहुंची थीं. सानिया का यूएस ओपन में डबल धमाका करने का सपना टूट गया. लेकिन उन्होंने मिक्स डबल्स का ख़िताब जीतकर इतिहास रच दिया. वह यूएस ओपन ख़िताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं. सानिया ने इस बार यूएस ओपन में जबरदस्त प्रदर्शन किया. इस वजह से वह ख़िताब जीतने में कामयाब हुईं. सानिया और ब्लैक की जोड़ी को महिला युगल के सेमीफाइनल में मार्टीना हिंगिस और पेनेटा की जोड़ी ने सीधे सेटों में 6-2,6-4 से मात दी. पहले सेट में हार के बाद सानिया और ब्लैक ने वापसी को कोशिश की लेकिन उनकी मेहनत परवान नहीं चढ़ सकी. मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में सानिया और ब्रूनो की जोड़ी ने ताईवान और ब्रिटेन के खिलाड़ियों की जोड़ी को 7-8, 4-6 और 10-7 से मात दी.

सानिया कोरिया के इंचियोन शहर में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए असमंजस में हैं. पहले ही दो पुरुष खिलाड़ी सोमदेव बर्मन और रोहन बोपन्ना एशियाई खेलों से अपना नाम वापस ले चुके हैं, ऐसे में सानिया भी दुविधा में हैं कि वह इसमें भाग लें या नहीं. उन्होंने फैसला अखिल भारतीय टेनिस संघ पर छोड़ दिया है. 19 सितंबर से शुरु हो रहे एशियाई खेलों की तारीखें बीजिंग और टोकयो में होने वाले दो एटीपी टूनामेंटों से मिल रही हैं. इन दोनों टूनामेंट में सानिया को कई एटीपी प्वाइंट्स का बचाव करना होगा इसलिए यह स्थिति काफी मुश्किल है. सानिया का कहना है कि सर्किट को छोड़कर एशियाई खेलों को तरजीह देने से उनके लिए डब्ल्यूटीए के सेशन चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा. सानिया को लगता है कि साल के आखिर में सिंगापुर में होने वाली चैंपियनशिप में जगह बनाने का मौका है यदि वह इन टूनामेंट में नहीं खेलती हैं तो उनके लिए चैंपियनशिप में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा. सानिया का कहना है कि यदि देश को जरूरत है तो वह एशियन गेम्स में खेलेंगी. बड़े खिलाड़ियों के पहले ही एशियाई खेलों से नाम वापस लेने के कारण उन्हें भारत के मेडल जीतने पर आशंका है, ऐसे में वह अकेले मेडल जिता पाएंगी यह मुश्किल दिख रहा है. वर्ष 2010 में ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों के युगल में सानिया ने विष्णु वर्धन के साथ मिश्रित युगल स्पर्धा का रजत और एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था. इस बार भी उनसे देश को पदक दिलाने की उम्मीद है. ऐसे भी वह अच्छे फॉर्म में चल रही हैं. यूएस ओपन से पहले जारी हुई एटीपी रैंकिंग में सानिया मिर्जा को युगल रैंकिंग में पांचवां स्थान मिला था. यूएस ओपन जीतने के बाद वह पांचवें पायदान पर बनी हुई हैं.

सानिया ने छह साल की उम्र में टेनिस रैकेट हाथ में थामा था, आज वही रैकेट उन्हें दुनिया भर में सम्मान दिला रहा है. टेनिस रैकेट हाथ में थामने वाले हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड स्लैम ख़िताबों पर कब्जा कर सके. सानिया पिछले एक दशक में अपने सपनों में रंग भरती आ रही हैं. उनकी जीत अकेले की जीत नहीं यह देश की 60 करोड़ महिलाओं की जीत है. सानिया ने अपनी हालिया जीत से यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. यह पहला मौका है जब सानिया ने किसी भारतीय खिलाड़ी के सहयोग से ग्रैंड स्लैम ख़िताब हासिल किया है. सानिया ने अपने खेल से सालों से देश का नाम ऊंचा करने वाले लिएंडर पेस और महेश भूपति की विरासत को संभाल लिया है.सानिया ने केवल भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है बल्कि भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया है. उसने सभी बंधनों और दायरों से बाहर निकल कर देश की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं. सानिया के टेनिस में पदार्पण के बाद देश में प्रोफेशनल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढी और सफलता के नए अध्याय लिखे जाने लगे. महिला खिलाड़ियों ने दूसरे खेलों में भी उनसे प्रेरणा लेकर एक नई शुरूआत की. परिणाम यह है कि देश में हर खेल में महिला खिलाड़ियों की नई खेप तैयार हो गई है. स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल और स्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल की सफलता को भी सायना की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है.

2003 में सानिया ने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद सानिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. लिएंडर पेस और महेश भूपति ने पुरुष वर्ग में टेनिस को लोकप्रिय किया और देश को गौरव के कई मौके दिए लेकिन भारत की महिला वर्ग में झोली खाली रहती थी, सानिया ने इस कमी को पूरा किया और अपने प्रदर्शन से दुनिया को यह बता दिया कि भारतीय महिलाएं भी टेनिस कोर्ट में कमाल कर सकती हैं, वर्ष 2006 में आस्ट्रेलियाई ओपन में वरीयता पाकर वह किसी भी ग्रैंड स्लैम में वरीयता पाने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं. 2005 में सानिया एटीपी ख़िताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं. वर्ष 2005 में यूएस ओपन के महिला ओपन में वह प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुईं थी. जहां उन्हें मारिया शारापोवा के हाथों मात मिली. 2005 में उन्हें डब्ल्यूटीए का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी घोषित किया गया. 2006 में सानिया ने अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका किया, कोरिया ओपन में मार्टीना हिंगिस को मात दी थी. इसके बाद सानिया ने दोहा एशियाई खेलों में तीन स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया. वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उन्होंने 31 वीं रैंक खिलाड़ी के रूप में भाग लिया. तीसरे राउंड में आठवीं रैंक की वीनस विलियम्स ने मात दी. उसी टूनामेंट में वह मिक्स डबल्स में महेश भूपति के साथ फाइनल में पहुंची लेकिन भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा.

2008 में उनके करियर का सबसे कठिन दौर आया उनकी कलाई की चोट ने उन्हें बहुत परेशान किया. लेकिन सायना ने हार नहीं मानी. चोट से उपरकर सायना ने ऐसी वापसी की कि सब ने दांतों तले उंगली दबा ली. पिछले पांच सालों में सानिया युगल और मिश्रित युगल के पांच ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची जिनमें से तीन बार उन्हें जीत मिली. महिला युगल में वह चार बार सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन एक भी युगल ग्रैंड स्लैम ख़िताब वह नहीं जीत सकीं. आज सानिया अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही हैं. सानिया ने एकल में जो मुकाम हासिल किया वह उनके समकालीन पुरुष खिलाड़ी भी नहीं कर सके हैं. सानिया एकल में विश्व रैंकिंग में 26 वें पायदान पर पहुंचीं थीं. सानिया करियर में 20 डब्ल्यूटीए और 4 आईटीएफ ख़िताब जीत चुकी हैं. भले ही एकल में उन्हें आपेक्षित सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उन्हें हमेशा एक संपूर्ण टेनिस खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा. आगे भी वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहेंगी और देश उन्हें शाबाशी देता रहेगा. शाबाश सानिया! ■

सानिया मिर्जा एक ऐसा नाम है जिसने न केवल भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया बल्कि भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया. उसने सभी बंधनों और दायरों से बाहर निकल कर देश की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं. सानिया के टेनिस में पदार्पण के बाद देश में प्रोफेशनल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और सफलता के नए अध्याय लिखे जाने लगे. महिला खिलाड़ियों ने दूसरे खेलों में भी उनसे प्रेरणा लेकर एक नई शुरूआत की. परिणाम यह है कि देश में हर खेल में महिला खिलाड़ियों की नई खेप तैयार हो गई है. स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल और स्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल की सफलता को भी सायना की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है. करियर शुरु करने के एक दशक बाद भी सानिया नित नई सफलता की कहानियां लिख रही हैं. चोटों से उबरकर सायना ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है. देश को उन पर गर्व है.

feedback@chauthiduniya.com

कहानी शुरू होती है अनुष्का के किरदार से जो जर्मनी के ब्रुग्स में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं. सुशांत सिंह राजपूत उनके बॉयफ्रेंड के किरदार में हैं. दोनों प्यार करते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते में कई अड़चनें हैं. असामान्य खबरों की तलाश अनुष्का को भारत ले आती है, जहां उसकी मुलाकात आमिर के किरदार यानी पीके से होती है.

नाराज हो गईं परिणीति

आदित्य और 60 लोगों के टीम के साथ कई शहरों की फुडजर्नी पर परिणीति जा रही हैं. हर शहर में वे अलग-अलग तरह का खाना चखेंगी. चूंकि वे कह चुकी हैं कि वजन कम करना पतला होना है, इस बात को उनसे यहां पूछा गया कि इस ट्रिप पर अपने वजन को कैसे संतुलित रखेंगे. इतना पूछने पर वे भड़क गईं. परिणीति गुस्से में बोलीं, ज्यादा खाऊंगी तो जिम में वर्कआउट भी करूंगी. फिल्म की थीम ही खाने से जुड़ी है, तो इस पर किसी को मेरे वजन की क्यों चिंता हो? शॉर्ट ऑरेंज ड्रेस में पहुंचीं परिणीति ने मंच पर आते ही कहा कि छोटी ड्रेस पहनने का उनका फैसला गलत रहा. ऊंची कुर्सी पर बैठते हुए वे और भी असहज हो गईं. उन्हें ये भी पसंद नहीं आया कि बबली एक्ट्रेस कहा जाए. उनका कहना है कि बबली कोल्ड ड्रिंक या शैंपेन हो सकती है, कोई लड़की नहीं. जबकि नई भाषा में बबली का अर्थ खुशनुमा से लगाया जाता है. पर वे गुस्सा हो गईं. ■

फिर कमीने बनेंगे शाहिद

कमीने के बाद शाहिद कपूर को हैदर बनाने वाले विशाल भारद्वाज जल्द ही शाहिद को लेकर कमीने के सीक्वल पर काम शुरू करने वाले हैं. यह बात विशाल ने अभी आधिकारिक रूप से नहीं कही है, लेकिन अपने एक इंटरव्यू में वह इशारा कर चुके हैं. विशाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि राइटर के साथ बैठ कर मैं कमीने के सीक्वल की पटकथा लिखनी शुरू कर दूं और जल्द ही मैं इस पर काम शुरू करनेवाला हूं. बताया जाता है कि कमीने के सीक्वल के लिए खुद शाहिद कपूर काफी उत्साहित हैं और इसके लिए विशाल से खुद शाहिद ने सिफारिश की है. कमीने के बाद हैदर में शाहिद की परफॉर्मेंस से खुश विशाल का मानना है कि युवा कलाकारों में एकमात्र शाहिद कपूर हैं जिनमें पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन कलाकारों की काबिलियत है. सिर्फ यही नहीं हैदर के अंतिम हिस्से की शूटिंग के दौरान शाहिद ने यह बात साबित भी कर दी. विशाल का कहना है कि फिल्म के ब्लाइमैक्स सीन में जब हैदर पागल हो जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है, उसमें शाहिद को छह पेज का मोनोलॉग पेश करते देख जेहन में पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह की यादें ताज़ा हो गईं. ■

कमीने के सीक्वल के लिए खुद शाहिद कपूर काफी उत्साहित हैं और इसके लिए विशाल से खुद शाहिद ने सिफारिश की है. कमीने के बाद हैदर में शाहिद की परफॉर्मेंस से खुश विशाल का मानना है कि युवा कलाकारों में एकमात्र शाहिद कपूर हैं जिनमें पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन कलाकारों की काबिलियत है.

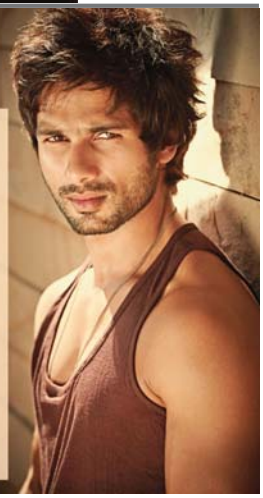

सोनाक्षी को पसंद नहीं बेइज्जती

सोनाक्षी सिन्हा दिखती तो बहुत कूल हैं, लेकिन वो भी गुस्सा करती हैं. उनको जब गुस्सा आता है, तो वो किसी नहीं सुनती हैं. सोनाक्षी कहती हैं कि जब कोई किसी का अपमान करता है, तो उन्हें गुस्सा आता है. यही नहीं, वह बड़ी मुश्किल से अपने आपको कंट्रोल करती हैं.

सोनाक्षी ने बताया कि मैंने खुद ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जो दूसरों को छोटी सी बात पर बेइज्जत कर देते हैं. आखिर आप प्रभावशाली हों, तो आप दूसरे के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते. ऐसा देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है.

सोना लाइफ में अच्छी वैल्यूज को फॉलो करने में विश्वास करती हैं. उनका मानना है कि अगर आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लो, तो यह जरूरी नहीं है कि आप खुद पर घमंड करने लगो. अपने आगे किसी को कुछ न समझो. सोनाक्षी का कहना है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन दूसरों की रेस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए. किसी भी इंसान को ठेस पहुंचाना सही नहीं है. सोनाक्षी इस समय अपनी आने फिल्म तेवर की शूटिंग में बिजी हैं. ■

सोना लाइफ में अच्छी वैल्यूज को फॉलो करने में विश्वास करती हैं. उनका मानना है कि अगर आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लो, तो यह जरूरी नहीं है कि आप खुद पर घमंड करने लगो. अपने आगे किसी को कुछ न समझो.

आधी रात को सुजैन के घर पहुंचे रितिक

रितिक रोशन और सुजैन खान भले ही एक-दूसरे से अलग रहे हों, लेकिन रितिक अभी भी शायद उनके लौटने की उम्मीद है, हालांकि सुजैन ने अपने सरनेम से रोशन भी निकाल दिया है, लेकिन बावजूद इसके रितिक उनके परिवार के संपर्क में हैं. ताजी खबर यह है कि रितिक हाल ही में ही फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग को छोड़कर आधी रात को ही सुजैन के घर पहुंच गए. रितिक फिल्म की स्क्रीनिंग छोड़कर सीधे संजय खान के घर जा पहुंचे और वह वहां पर तकरीबन 45 मिनट तक रुके. इस दौरान रितिक के बॉडीगार्ड ने कैमरामैन को भी उनकी तस्वीरें नहीं खींचने दी. ऐसे में सभी को आश्चर्य हो रहा है कि आधी रात को रितिक को सुजैन के घर क्यों जाना पड़ा. बालीवुड में कयास लगाए जा रहे हैं कि रितिक अपने और सुजैन के बीच आए मनमुटाव को दीर करना चाहते हैं. ■

ईवलिन बॉक्सर विजेंदर सिंह की दीवानी हुई

जॉन मूल की मॉडल और एक्ट्रेस ईवलिन शर्मा बॉक्सर विजेन्द्र सिंह की दीवानी हो गई हैं. एक रिएलिटी शो में विजेंदर के साथ शूटिंग के दौरान ईवलिन ने अपने रुख का खुला इजहार भी किया. ईवलिन और विजेन्द्र एक मॉडलिंग इवेंट में जज तौर पहुंचे थे. इस दौरान ईवलिन जिस बेतकल्लुफी के साथ विजेंदर के साथ पेश आ रही थीं. जिस ढंग की गर्मजोशी दिखा रही थीं. उसके बाद मुंबई के गॉसिप सर्किट में अफवाहें तेज हो गईं. ईवलिन शर्मा फिल्म यारियां, ये जवानी है दीवानी और मैं तेरा हीरो में नजर आई हैं. उनके हिस्से ज्यादातर बोल्ड यानी बिकनी सीन ही आए हैं. उधर विजेंदर भी पिछले दिनों आई कबीर सदानंद की फ्लॉप फिल्म फगली में बतौर हीरो नजर आए थे. ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत चुके विजेंदर सिंह की 2011 में अर्चना सिंह से शादी हो चुकी है. ■

एक रिएलिटी शो में विजेंदर के साथ शूटिंग के दौरान ईवलिन ने अपने रुख का खुला इजहार भी किया. ईवलिन और विजेन्द्र एक मॉडलिंग इवेंट में जज तौर पहुंचे थे. इस दौरान ईवलिन जिस बेतकल्लुफी के साथ विजेंदर के साथ पेश आ रही थीं.

पीके में पत्रकार बनेंगी अनुष्का

राजकुमार हीरानी की इस फिल्म में अब तक सिर्फ आमिर खान के रोल का ही खुलासा हुआ है, जो एक एलियन का है. अब खबर है कि फिल्म में अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी. शूटिंग के दौरान उनकों अलग किस्म के विग में नजर आई हैं. फिल्म में वे एक ऐसी पत्रकार के रोल में होंगी, जो अजीब किरदारों पर लिखती हैं. कहानी शुरू होती है अनुष्का के किरदार से जो जर्मनी के ब्रुग्स में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं. सुशांत सिंह राजपूत उनके बॉयफ्रेंड के किरदार में हैं. दोनों प्यार करते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते में कई अड़चनें हैं. असामान्य खबरों की तलाश अनुष्का को भारत ले आती है, जहां उसकी मुलाकात आमिर के किरदार यानी पीके से होती है. वह भगवान को ढूंढते हुए दूसरी दुनिया से धरती पर आया है. पीके उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, जिसके जवाब उसके पास नहीं है. फिर उन सवालों की तलाश में ये दोनों ही निकलते हैं, जो उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

चौथी दुनिया

15 सितंबर-28 सितंबर 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार झारखंड

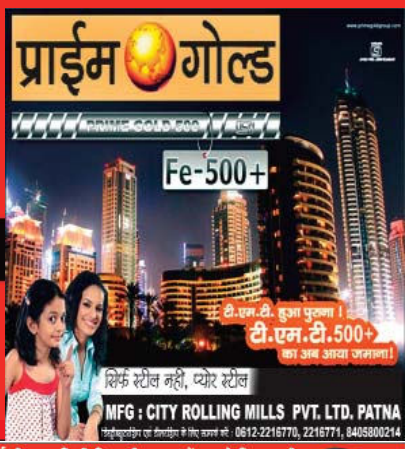

समता के शहीदों को क्यों भूले नीतीश

कोई भी राजनीतिक दल कुछ एक को छोड़कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देता ही क्या है? संघर्ष के साथी रहे ये कार्यकर्ता और नेता अपने दल और दल के प्रमुख से केवल मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं. वे चाहते हैं कि जिस पवित्र मकसद के लिए उन्होंने पार्टी के कहने पर अपना पसीना और खून दोनों बहाया कम से कम उसकी गरिमा बनी रहे. इस पवित्र मकसद के पीछे की भावना को राज पाने के लिए या राज बचाने के लिए ठेस न पहुंचाई जाए. लेकिन लालू प्रसाद के साथ चलने का फैसला कर लगता है नीतीश कुमार ने समता पार्टी के शहीदों , नेताओं और कार्यकर्ताओं की इसी भावना को ठेस पहुंचा दी. इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को ऐसा करने का नैतिक हक था. क्या नीतीश कुमार ने समता के शहीदों को अपमानित तो नहीं कर दिया?

सरोज सिंह

लालू- राबड़ी शासन के खिलाफ जीवन और मरण की लड़ाई लड़ने वाली समता पार्टी के कुछ पुराने चेहरे इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. अफसोस की बात यह है कि ये ऐसे चेहरे हैं जो आज हमलोगों के बीच नहीं हैं. लालू-राबड़ी के शासन का विरोध करते-करते अलग-अलग स्थानों पर या तो इनकी हत्या हो गई या वे मर गए. यह वह दौर था जिसे लालू प्रसाद के विरोधी जंगलराज का नाम देते हैं. न जाने कितने जाने-अनजाने चेहरों ने समता पार्टी की लड़ाई में अपना खून दिया होगा. कुछ के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं पर उनकी संख्या कहीं ज्यादा है जो परदे के पीछे रहकर समता पार्टी को ताकत देते थे. ऐसे बहुत सारे चेहरे अब इस दुनिया में नहीं हैं जिन्होंने समता पार्टी को एक मजबूत ताकत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आज जब समता पार्टी में खास रहे नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक फैसला लेकर लालू प्रसाद के साथ आगे बढ़ने का काम आगे बढ़ा दिया है तो यहीं से यह सवाल भी साथ ही साथ आगे बढ़ गया कि आखिर समता पार्टी के शहीदों को नीतीश कुमार क्यूं भूल गए? क्या इन लोगों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि नीतीश कुमार अपना राज बचाने के लिए लालू प्रसाद की गोद में जाकर बैठ जाएं.

लालू-राबड़ी शासन काल में समता पार्टी के जिन संस्थापक सदस्यों की हत्या हुई थी उनमें कैमूर के रणविजय पटेल, नालंदा के डॉ. अशोक सिन्हा, पुनपुन के कामेश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर के शंभू सिंह, सीवान के सुरेंद्र पटेल, अश्वमेध देवी के पति प्रदीप महतो और मौजूदा समाज कल्याण मंत्री के पति बूटन सिंह भी शामिल हैं. इनके अलावा ऐसे सैंकड़ों नाम हैं जिन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल के खिलाफ समता पार्टी की लड़ाई में नीतीश कुमार और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार और देश के लोगों को यह संदेश दिया कि जंगलराज को मिटा कर रहेंगे या खुद मिट जाएंगे. उनकी लड़ाई सफल रही और 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए. इस पल को देखने के लिए उनमें से बहुत सारे चेहरे मौजूद नहीं थे जिन्होंने अपना सब कुछ इस पल के लिए कुर्बान कर दिया. समता पार्टी के उन शहीदों और कार्यकर्ताओं का दर्द उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा काफी शिद्दत से महसूस कर रही है.

इसलिए बिहार के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में समता के इन शहीदों को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने याद करने का फैसला किया है. रालोसपा ने अक्टूबर के महीने में इन शहीदों को अपने पार्टी मंच से श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है. रालोसपा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समता पार्टी के दौर के तपे-तपाए नेता रामबिहारी सिंह को संयोजक बनाया है. रामबिहारी सिंह कहते हैं कि हम अपने पुराने शहीद साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं. आखिर हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने लालू-राबड़ी के जंगलराज के खिलाफ लड़ाई में अपना खून बहाया है. रामबिहारी कहते हैं कि हमलोग शहीदों के परिजनों से मिलेंगे. उनकी भावनाओं से अवगत होंगे और पार्टी की ओर से श्रद्धाभाव प्रकट करेंगे. रामबिहारी सिंह इसके साथ यह भी जोड़ते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा. यह पूरी तरह परिवार का मामला है क्योंकि हमलोग पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को परिवार का अंग मानते हैं. रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार नीतीश कुमार से सीधा सवाल करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार समता पार्टी के इन शहीदों को क्या जवाब देंगे. जिस जंगलराज के खात्मे के लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी और इसी जंगलराज की वापसी के लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद से हाथ मिला रहे हैं. समता पार्टी के हमारे सैंकड़ों साथियों ने क्या इसी दिन के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी. नीतीश कुमार को समता पार्टी के शहीदों, उनके परिजनों और बिहार की जनता को यह बताना होगा कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने जंगलराज की वापसी के लिए लालू प्रसाद को गले लगा लिया. अरुण कुमार सवाल करते हैं कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई अपने ही साथियों की कुर्बानियों को भूला सकता है? रालोसपा नीतीश कुमार के इस चेहरे को बेनकाब करेगी. समता पार्टी के शहीदों के लिए हमारे दिल में बेहद सम्मान है और हम चाहते हैं कि उन्हें दगा देने वालों को जनता सबक सिखाए. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि रालोसपा अपने इस अभियान के मारफत जद्यू के परंपरागत वोटबैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है. रालोसपा चूंकि बिहार में अपने विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है तो समता के शहीदों की याद ताजा कर पार्टी अपने इन सभी पुराने साथियों को जोड़ना चाहती है जो नीतीश कुमार के लालू के साथ जाने के फैसले से बेहद खफा हैं. रालोसपा ने जगदेव बाबू को याद कर पांच सितंबर से अपने जिलावार सम्मेलनों का श्रीगणेश कर दिया है. इन सम्मेलनों का चौथा चरण 13 अक्टूबर में कटिहार की रैली के साथ खत्म होगा. इस दौरान पार्टी भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करेगी. चौथे चरण में मधुबनी, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में कार्यक्रम होगा. इन चार चरणों के बाद पूर्वी बिहार का कार्यक्रम प्रस्तावित है. कहने का मतलब यह है कि रालोसपा ने अपने स्तर से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है. बिहार की जनता को व्यापक समर्थन पार्टी को मिल रहा है. हम चाहते हैं कि रालोसपा की ताकत इतनी हो जाए कि देश में कोई भी दल या नेता हमारी उपेक्षा न करे. उनका कहना है कि हमलोग एनडीए में हैं और गठबंधन का पूरा सम्मान करते हैं. लेकिन रालोसपा पूरे बिहार के स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगी है ताकि एनडीए को और भी मजबूत किया जा सके. कार्यकर्ताओं के मान व सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है. सत्ता तो आती है चली जाती है. लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और मंजिल पाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की वैसे समर्पित नेताओं और शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं. नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि क्या वे समता पार्टी के शहीदों के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं. हमारे जो साथी जंगलराज के खात्मे की लड़ाई में हमसे हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो गए आखिर उन्हें नीतीश कुमार अपना कौन सा मुंह दिखाएंगे?

रालोसपा का यह संकल्प है कि समता पार्टी के शहीदों और उनके परिजनों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा. समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार राज पाने और राज बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. लालू प्रसाद से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने यह बात साबित भी कर दी. जंगलराज में हमारे कई साथी मारे गए और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने अपने समता के कई साथियों को राजनीतिक तौर पर मारना शुरू कर दिया. जार्ज साहब और दिग्विजय बाबू का उदाहरण तो सबके सामने ही है. शंभू श्रीवास्तव, प्रेमकुमार मणि, शकुनी चौधरी और ब्रह्मानंद मंडल और खुद मेरे साथ नीतीश कुमार ने क्या किया, यह बात किसी से छिपी है क्या?

नेताजी कहिन

नीतीश कुमार राज पाने और राज बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. लालू प्रसाद से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने यह बात साबित भी कर दी. जंगलराज में हमारे कई साथी मारे गए और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने अपने समता के कई साथियों को राजनीतिक तौर पर मारना शुरू कर दिया. जार्ज साहब और दिग्विजय बाबू का उदाहरण तो सबके सामने ही है. शंभू श्रीवास्तव, प्रेमकुमार मणि, शकुनी चौधरी और ब्रह्मानंद मंडल और खुद मेरे साथ नीतीश कुमार ने क्या किया, यह बात किसी से छिपी है क्या?

– पी के सिन्हा

हम अपने पुराने शहीद साथियों को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं. आखिर हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने लालू- राबड़ी के जंगलराज के खिलाफ लड़ाई में अपना खून बहाया है. राम बिहारी कहते हैं कि हमलोग शहीदों के परिजनों से मिलेंगे. उनकी भावनाओं से अवगत होंगे और पार्टी की ओर से श्रद्धाभाव प्रकट करेंगे. इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा. यह पूरी तरह परिवार का मामला है क्योंकि हमलोग पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को परिवार का अंग मानते हैं.

– रामबिहारी सिंह

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

एसबीआई ने दिया कम्प्यूटर

भारतीय स्टेट बैंक शाखा जुम्मन चौक फॉरबिसगंज के प्रबंधक अरुण कुमार के द्वारा विद्यालय ली अकादमी को एक कम्प्यूटर सेट प्रदान किया गया. इस अवसर पर मुख्य शाखा प्रबंधक ए.के. पाठक ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं के अनुशासन की सराहना करते हुए बैंक के द्वारा हर संभव योजना का लाभ इस विद्यालय को दिलाने की घोषणा की. इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य शिवनारायण दास ने आगत अतिथियों का स्वागत किया जबकि विद्यालय की छात्रा नीतू कुमारी के द्वारा उनके सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया गया. बैंक अधिकारी बी.डी. गुप्ता, नीरज कुमार, शिक्षक मुस्ताक आलम, प्रमोद कुमार दास, मो. तनजीम खान, ओम प्रकाश चौधरी, शारदा देवी, कुणाल भारती आदि उपस्थित थे. मंच का संचालन हरिशंकर झा एवं ललित कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया.

श्रद्धांजलि सभा

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा फारबिसगंज में ओम् शांति केन्द्र की पूर्व मुख्य संचालिका परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को उनके स्मृति दिवस पर भावभिनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी. इस अवसर पर फारबिसगंज शाखा केन्द्र की संचालिका ब्रम्हाकुमारी रुकमा दीदी के द्वारा स्मृति पूज्य दादी को उनके तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गयी. इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित ब्रह्मकुमारियों एवं ब्रह्मकुमारों को बताया कि पूज्य दादी जी का जीवन काल पूर्णतः सरल एवं सादगी भरा रहा. इस अवसर पर बीके दीदियों में सीता दीदी, संतोषी दीदी, इन्दु दीदी, मृदुला दीदी, अंजू दीदी, अनिता दीदी, सिंधु दीदी, रंजू दीदी, बीके भाईयों में राजू भगत, पप्पू डालमियां, आदित्य भाई, कुलानंद चौधरी, अशोक डाबरीवाला, राजीव भाई, संजय बोथरा, राजेन्द्र बोथरा आदि उपस्थित थे. कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव भाई एवं आदित्य भाई के द्वारा पूज्य दादीजी की स्मृति में गीतों एवं कविताओं की अलौकिक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई.

– अजातशत्रु अग्रवाल

महावीरी झंडा शोभायात्रा

फारबिसगंज में सांवलिया कुंज ठाकुरबाड़ी की अगुआई में प्रतिवर्ष निकलने वाली विशाल शोभायात्रा इस बार कई मायनों में खास रही. प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष शोभायात्रा में अप्रत्याशित हजारों हजार की भीड़ रही. फारबिसगंज शहर के अलावा आस-पास के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. जय श्रीराम जय हनुमान के जयघोष से पूरा शहर भक्ति के रस में घंटो डूबा रहा. जगह-जगह स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा शर्बत, चने आदि की व्यवस्था की गई थी. नगर भ्रमण के द्वारा मंदिर के महंत तथा महावीरी झंडा शोभायात्रा में मुख्य रूप से विधायक पद्मपराग राय वेणु, मुख्य पार्षद वीणा देवी, विहिप के मंचन केशरी, दिलीप मेहता, उपमुख्य पार्षद मोती खान, जागरण कल्याण भारती के संजय कुमार, शाहजहां शाद, सुरेश पासवान, प्रमुख अशोक विश्वास, रमेश सिंह, श्री कुमार ठाकुर, अमरीश राहुल, मनोज झा, आशुतोष मिश्रा, विमल सिंह, रमेश मेहता आदि उपस्थित थे. वहीं विधि व्यवस्था की कमान अररिया एसपी विजय कुमार वर्मा संभाल रहे थे जबकि फारबिसगंज एसडीएम सुभाष नारायण, एसडीपीओ अजित सिंह, सीओ विष्णुदेव सिंह, इंसपेक्टर हरि राम, थानाध्यक्ष विपिन कुमार के द्वारा सक्रिय रूप से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दिया गया. ■

–अमित ठाकुर

भागलपुर

भितरघात ले डूबा भाजपा को

भागलपुर की मुख्य समस्या चम्पानाला पुल, घोरघटपुल, जाम, बिजली, पानी व सड़क उनके लिए चुनौती के रुप में मुंह बाए खडी हैं. वहीं अगर भाजपा की हार की बात की जाऐ, तो उसका मुख्य कारण आपसी तिलिस्म व भितरघात सामने उभर कर आ रहा है. भाजपा के भीतर गुटबाजी तब से शुरू हुई जब भागलपुर लोकसभा सीट से वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन को उतारा गया था.

नमन कुमार चौधरी

विधानसभा उपचुनाव में भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा की जीत महागठबंधन की बड़ी जीत है. शर्मा को मिली कामयाबी से भाजपा का 24 साल पुराना किला ढह गया. हालांकि जीत के बाद दोनों ओर से जुबानी जंग और तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस जीत को जहां ऐतिहासिक करार दिया वहीं भाजपा से पराजित उम्मीदवार नभय चौधरी ने इसे धनबल की जीत व जनबल की हार बताया. पिछले कई चुनावों में भाग्य आजमा रहे अजित शर्मा को इस बार भागलपुर की जनता का भरपुर सहयोग मिला. बेशक वह सहयोग कितना कारगर साबित होगा यह नवोदित विधायक की प्रयास व कार्यों पर निर्भर करेगा.

भागलपुर की मुख्य समस्या चम्पानाला पुल, घोरघटपुल, जाम, बिजली, पानी व सड़क उनके लिए चुनौती के रुप में मुंह बाए खडी हैं. वहीं अगर भाजपा की हार की बात की जाए, तो उसका मुख्य कारण आपसी तिलिस्म व भितरघात सामने उभर कर सामने आ रहा है. भाजपा के भीतर गुटबाजी तब से शुरू हुई है जब भागलपुर लोकसभा सीट से वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन को उतारा गया था. हालांकि इस बात को भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वीकार करने को कतई तैयार नही हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा में आपसी गुटबादी चरम पर है. उन्होंने तो इस मुदद्दे पर यहां तक कह डाला की वे संगठन का ऑपरेशन करेंगे कई पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरों को पार्टी मे शामिल करेंगे. संगठन से पूर्णगठन को लेकर प्रदेश नेताओं से अनुमति लेंगे. अगर नहीं मिली तो जिलाध्यक्ष का पद त्याग कर देंगे.

उन्होंने कहा कि संगठन के अधिकांशत: लोगो ने उनके लिए काम नहीं किया जिसकी सूची उनके दिमाग मे है. प्रदेश इकाई के समक्ष गद्दार सिपाही का पत्ता खोलेंगे, उन्हें शिकायत मिली है कि अपने ही कार्यकर्ताओं ने लोगों को मतदान करने से रोका व मत देने के लिए मतदाताओं को अपने घर से नहीं निकलने दिया. कई कार्यकर्ता मतदान के दिन क्षेत्र व मतदान केन्द्रों पर नहीं दिखे और न ही कोई परची बांटी. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता मतदान के दिन दिनभर सोए रहे संपर्क करने पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाता था. विधानसभा उपचुनाव का परिणाम बताता है कि भाजपा के इलाकाई क्षत्रपों ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया. इलाकाई क्षत्रपों को जो ईलाका बांटकर जिम्मेदारी दी गई थी. वो अपने वोटरों को सहेज कर नहीं रख पाए. जानकारों के अनुसार भागलपुर मे वैश्य समुदाय को इस बार टिकट मिलने की उम्मीद थी. करीब आधा दर्जन वैश्य उम्मीदवारी के लिए पटना व दिल्ली की खाक छान रहे थे, लेकिन पार्टी अलाकमान ने उनके दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह सीट ब्राह्मण की खाली हुई है. इसलिए ब्राह्मण को टिकट देना मजबूरी है. इस बात को लेकर वैश्य समाज में काफी असंतोष व्याप्त था. इन लोगों में अपना प्रतिनिधित्व करने की व्याकुलता थी. स्थानीय स्तर पर वैश्य समाज के नेता कहते हैं कि कब तक हमलोग दुसरों की झोली ढोते रहेंगे. जबकि भागलुपर सीट पर जीत का दारोमदार मारवाड़ी व वैश्य पर रहता है.

दोनो वर्गों के करीब सवा लाख के करीब मतदाता हैं. इस समाज से जिला उपाध्यक्ष निरंजन साह नगर अध्यक्ष विजय साह, पवन गुप्ता, विनय जैन व संतोष कुमार अपने को सिनियर प्रत्याशी मानते हैं. उनकी उपेक्षा करने से ही भाजपा की हार हुई. भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि हम लोगों पर जो दोष मढ़ा जा रहा है वह बिलकुल गलत है. यहां भाजपा के भीतर गुटबाजी के कारण कार्यकर्ता अपने को ठगा महसुस करते हैं. पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नए व दलबदलुओं को अधिक तवज्जो दिया जाता है, जो कि काफी गलत है. कार्यकर्ताओं को नेता से दूर रखना चाहिए, उन्हें सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी देनी चाहिए. न कि नेता की अगुवाई की. इस बीच जगदीशपुर भाजपा के सक्रिय व युवा कार्यकर्ता सुजेश खन्ना ने चौथी दुनिया को बताया कि भाजपा की बदतर स्थिति के बारे में प्रदेश समिति को गंभीर होना चाहिए. टिकट इस समाज के लोगों को मिलना चाहिए, जिसकी संख्या क्षेत्र मे अधिक है. टिकट बंटवारे में सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के विचार को लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि गुटबाजी भाजपा की हार का मुख्य कारण है और इसका जन्मदाता अश्विनी चौबे व शाहनवाज हुसैन हैं, उन्हें यहां की राजनिति से दूर रखा जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

नेपाल के पानी ने मचाई तबाही!

नेपाली भू-भाग से निकल कर भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली वैसे तो कई नदिया है, लेकिन सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड में तकरीबन प्रति वर्ष तबाही का पैगाम लेकर आने वाली रातो नदी प्रमुख है.' चौथी दुनिया' ने पिछले साल 29 जुलाई से 04 अगस्त के अंक में ' नेपाल के पानी से मचेगी तबाही ' शीर्षक से एक रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 19 पर प्रकाशित की थी. रिपोर्ट में साफ तौर पर नेपाल सरकार की ओर से नेपाली क्षेत्र में रातो नदी के तटबंध निर्माण कराए जाने से भारतीय क्षेत्र में संभावित खतरा को लेकर अगाह किया गया था, लेकिन सत्ता की कुस्ती में मस्त रहने वाले हुक्मरान से लेकर प्रशासनिक तंत्र तक ने इसे नजर अंदाज किया. नतीजा है कि रातो नदी के भारतीय क्षेत्र में निर्मित जर्जर तटबंध महज एक सप्ताह में दुसरी बार टूट गया और सुरसंड प्रखंड में जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है...

वाल्मीकि कुमार

टूटे तटबंध का मुआयना करती कांग्रेस की टीम

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिला का सुरसंड व चोरौत प्रखंड के अलावा कई अन्य प्रखंड एवं पड़ोसी जिला मधुबनी का हिस्सा कभी भी नेपाल से प्रवाहित होने वाली रातों नदी के जल प्रलय का शिकार हो सकता है. कारण कि नेपाल सरकार ने रातों नदी के दोनों ही किनारे अपने क्षेत्र में मजबूत तटबंध का निर्माण कर खुद को सुरक्षित कर लिया है. जबकि भारतीय क्षेत्र में बाढ़ की संभावित खतरा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक महकमा तक ने कोई आवश्यक पहल नहीं की है. पिछले साल ' चौथी दुनिया ' के प्रकाशित रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही स्थिति को बयां किया था. जिसे सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर नजर अंदाज कर छोड दिया गया. नतीजा है कि इस साल एक बार फिर क्षेत्र के लोगों को जहां भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन जनता की परेशानी से अंजान बनी है. घरों में बाढ़ का पानी रहने के बाद भी पीड़ित परिवारों के बीच राहत का वितरण सरकारी प्रावधान के कुचक्र में फंसा है.

रिपोर्ट में बताया गया था कि सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के अंतर्गत श्रीखंडी भिट्ठा पंचायत नेपाली सीमा को छूती है. नेपाल सरकार ने वर्ष 2009 में नेपाल के बरदीबास से निकलने वाली रातों नदी के दोनों किनारे मजबूत तटबंध का निर्माण करा दी है. यह भारतीय सीमा पर स्थित भिट्ठा मोड़ के समीप तक नेपाली क्षेत्र में मौजूद है. नेपाल सरकार द्वारा नदी के किनारे तटबंध का निर्माण कराने के साथ ही नदी की धारा की खुदाई कर गहराई बढ़ाने का काम किए जाने का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया था. जिसे भारत अथवा बिहार सरकार या इनके तंत्र ने गंभीरता पूर्वक नही लिया.

नतीजतन पूर्व में खुले स्थान में फैलने के साथ आने वाला बाढ़ का पानी अब तटबंध के अंदर से सीधा खतरनाक अंदाज में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है. इससे न केवल भारतीय क्षेत्र के श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत बल्कि सिमियाही, दिवारी, मतौना, मेघपुर, हनुमान नगर, परिगामा, बसोतरा, चिकना, जमुनिया, बीसपटी, बघारी, लक्ष्मीपुर समेत दर्जनों गांव का अस्तित्व संकट में पड़ गया है, बल्कि श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी-पश्चिमी व दिवारी-मतौना पंचायत पूर्णतः प्रभावित हो रहा है. बावजूद इसके अब तक इस गंभीर समस्या के निदान की दिशा में आवश्यक पहल तक नहीं की जा सकी है. आलम है कि क्षेत्र के लोगों के लिए अब जीवन यापन की समस्या भी एक गंभीर चुनौती बनने लगी है. सैकड़ों मन अनाज की उपज देने वाली जमीन अब महज 40-50 मन से ज्यादा प्रयास के बावजूद भी किसानों को उपज नहीं दे पा रही है. बचाव कार्य के नाम पर बागमती प्रमंडल संख्या-1 द्वारा भिट्ठा मोड़ से सिमियाही तक करीब 3 किलोमीटर में करोड़ों की लागत से नदी के धारा की उड़ाही की कवायद किए जाने का जिक्र भी रिपोर्ट में शामिल था. बताया गया था कि नदी के पुरानी धारा को छोड़ कर इसे नई राह भी दिखाने का प्रयास किया गया है. जिसके कारण श्रीखंडी भिट्ठा पंचायत का वार्ड संख्या-5 के अलावा कंटाही टोला के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है. जब बाढ़ की बिकरालता चरम पर होती है तब लोगों को किसी प्रकार एनएच समेत अन्य स्थानों पर शरण लेने की विवशता बनी रहती है.

हाल ही में तटबंध टूटने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व में जब एक टीम रातों के क्षतिग्रस्त बांध के भाग का मुआयना करने पहुंची तो बागमती प्रमंडल संख्या-1 के नव पदस्थापित कार्यपालक अभियंता विनय सिंह ने यह कह कर सबको चौंका दिया कि हकीकत में रातों पर निर्मित बांध मानक के अनुसार बनाया ही नहीं गया है. कहा कि इस संबंध में सरकार को शीघ्र रिपोर्ट कर स्थिति से अवगत कराया जाएगा और रातों नदी के पानी को नियंत्रित करने को लेकर मजबूत व मानक के अनुरूप तटबंध का निर्माण आवश्यक है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लालू यादव, राज कुमार साह, कमलेश झा, ओम प्रकाश झा, संजय कुमार व गोविंद चौधरी समेत अन्य के साथ प्रभावित क्षेत्र मेघपुर, दिवारी मतौना, सुरसंड पूर्वी व पश्चिमी पंचायत का भ्रमण के बाद स्थिति को दु:खद बताया. कहा कि तटबंध टूटने की शिकायत सिंचाई मंत्री विजय कुमार चौधरी से की है. जबकि सीतामढ़ी डीएम ने बातचीत के क्रम में साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ की रिपोर्ट ही गलत भेजी गई है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने घटिया बांध निर्माण में शामिल अभियंताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़ितों के बीच समुचित राहत वितरण की मांग की है. कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन के लिए बाध्य होगी. वहीं दूसरी ओर पीडितों का कहना है कि जिले के एक कद्दावर नेता ने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से गलत बांध निर्माण कराने में अहम भूमिका निभायी है. जिसका खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

अब ऐसी हालात के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन मामले को गंभीरता पूर्वक नही लेती है तो आने वाले वर्षों में लोगों की तबाही में इजाफा की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है. पीड़ित को अब न नेताओं की चहलकदमी रास आ रही है और न ही सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली घोषणाएं. सबको समस्या का स्थायी निदान कराने वालों की दरकार है. संभव है अगर समस्या निदान को लेकर अविलंब आवश्यक पहल नहीं की गई, तो आगामी विधानसभा चुनाव में यह मामला चुनावी रंग में भंग डाल सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

बालश्रमिक स्कूलों के अस्तित्व पर संकट

यहां यह भी बता दें कि पूर्वी चंपारण जिला भारत-नेपाल की सीमा पर है और आर्थिक तंगी के कारण यहां के लोग अपने-अपने बच्चों से मजदुरी कराते रहे हैं और दलालों के साथ देश के महानगरों में मजदूरी के लिए भेजा रहा है जहां इनका शारीरिक व मांसिक रूप से शोषण किया जाता रहा है. हाल ही के महीनों में बंगलौर व अन्य इलाकों में हुई छापेमारी में बरामद बच्चे इस के ज्वलन्त उदहारण हैं.

इंतेजारुल हक

बाल श्रमिकों को शिक्षित करने व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केन्द्र व राज्य की सरकारें भले ही अनेक घोषणाएं करती हैं और कठोर से कठोर कानून बना छोटे-छोटे बच्चों से मजदूरी कराने वाले लोगों को सजा दिलाती हैं, लेकिन पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों से संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों व इसमें कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की बदहाली की खबर नहीं लेती. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन विद्यालयों को संचालित करने के लिए आवंटित लीज के घर का एक तरफ दो वर्षों से जहां किराया नहीं मिला है, जिससे इन विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट का बादल मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ इन विद्यालयों में सेवा दे रहे करीब पांच सौ से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों को चार वर्षों मानदेय नहीं मिला है. इस कारण उनके बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वे अनेक कठिन चुनौतियों से जुझ रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल पचास बाल श्रमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं. इन सभी विद्यालयों में पचास-पचास बाल श्रमिकों का नामांकन भी हुआ है और उन्हें शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई गई हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व उनकी उदासिनता ने शिक्षकों के साथ-साथ बालश्रमिकों के सभी सपनों को चकनाचुर कर दिया है.

जानकार बताते हैं कि एनसीपीएल के तहत ये सभी विद्यालय संचालित हैं और विद्यालयों से दूर रहने वाले समाज के दबे-कुचले लोगों के बच्चों का यहां नामांकन कराया गया है. यहां यह भी बता दें कि पूर्वी चम्पारण जिला भारत-नेपाल की सीमा पर है और आर्थिक तंगी के कारण यहां के लोग अपने-अपने बच्चों से मजदूरी कराते रहे हैं और दलालों के साथ देश के महानगरों में मजदूरी के लिए भेजा जाता रहा है. जहां उनका शारीरिक व मांसिक रूप से शोषण किया जाता रहा है. हाल ही के महीनों में बंगलौर व अन्य इलाकों में हुई छापेमारी में बरामद बच्चे इस के ज्वलंत उदहारण हैं. यही सब कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में सरकार ने पूर्वी चम्पारण में बाल श्रमिक विद्यालय चलाने का निर्णय लिया और अगस्त माह में एनजीओ के माध्यम से जिले भर में पचास विद्यालय खोले गए. करीब दो वर्षों तक इन विद्यालयों में पढ़ाई हुई, लेकिन वर्ष 2010 में बन्द हो गई. फिर 2012 के दिसंबर में इन विद्यालयों को नए तरीके से संचालित किया गया और बाल श्रमिकों को नामांकित कर शिक्षकों व कर्मियों की बहाली की गई. तब से लेकर अब तक इन विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी अनेक कठिन चुनौतियों से जुझते रहे हैं और बार-बार आंदोलन व धरना प्रदर्शन के बावजूद इनकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. यहां के कार्यरत शिक्षकों को मात्र चार हजार, लेखा पाल को तीन हजार व आदेश पाल को दो हजार रुपये दिये जाते हैं. एक तरफ आसमान छू रही महंगाई और इसमें में एक मनरेगा के मजदूर के बराबर भी मानदेय नही है. इसके बावजूद समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होना विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं. बीते दिनों मोतिहारी के नरसिंह बाबा के मठ परिसर में इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मानदेय मिलने में हो रही देरी पर गहन चर्चा की गई और उसके लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. बैठक में मौजूद शिक्षिका शशिबाला, प्रदेश कमिटी सदस्य रामविलास यादव, अध्यक्ष अजय गिरी, आशा कुमारी, उषा कुमारी श्रीवास्तव, सीमा देवी, विकास कुमार, फुलेना गिरी, पम्मी पाण्डेय, शाहिन सब्बा, मौजेलाल प्रसाद, तमन्ना आलम, देवी कुमारी, रामाधार, सिकन्दर प्रसाद यादव आदि ने इसके लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया और कड़ा दु:ख व्यक्त करते हुए सरकार व विभाग के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया. दूसरी तरफ पूछे जाने पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक विवेक सिंह ने बताया कि विभाग इन विद्यालयों व शिक्षकों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है और हर संभव प्रयास जारी है. सहायक निदेशक ने बताया कि विभाग को प्रतिवेदन भेज दिया गया है और राशि का आवंटन होते ही इनका भुगतान कर दिया जाएगा. कुल मिलाकर बाल श्रमिक विद्यालयों की हालत अच्छी नहीं है और सरकार की बाल श्रम मिटाने के लिए की गई कार्रवाई सफेद हाथी साबित हो रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

मोहनिया में अपनों से हार गया महागठबंधन

एक तरफ भाजपा सांसद छेदी पासवान की परिवारिक संरचना में आए बिखराव के बीच से निकले इनके भतीजा चंद्रशेखर पासवान महागठबंधन का उम्मीदवार तो दूसरी अचानक राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए निरंजन राम की उम्मीदवारी पर मतदाताओं में अच्छी खासी जदोजहद थी. लोकप्रियता स्वभाविकता सहित कई मापदंडों पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे. कमी इसकी सिर्फ इतनी थी कि महागठबंधन के स्थानीय दिग्गज किसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं. सारे समीकरण तहस-नहस हो चुके थे.

ममता चौहान

राज्य में सेमीफाईनल के नाम से दस विधान सभा सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन ने बाजी जरूर मार ली, लेकिन टेलीविजन सर्वे और समीक्षकों की राय से चुनाव के दिन तक मोहनियां सुरक्षित सीट पर चली काटे की टक्कर. फिर परिणामों में बड़े अंतर ने हर किसी को चौंका दिया. जिसका कारण रहा कि जदयू का यह सीट भाजपा के झोली में चला गया. जहां महागठबंधन के नेताओं के दावे धरे के धरे रह गए. जाहिर है यह चुनाव दोनों गठबंधनों के प्रत्याशियों के लिए कम शीर्ष नेताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था. एक तरफ भाजपा सांसद छेदी पासवान की परिवारिक संरचना में आए बिखराव के बीच से निकले उनके भतीजा चंद्रशेखर पासवान महागठबंधन का उम्मीदवार तो दूसरी अचानक राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए निरंजन राम की उम्मीदवारी पर मतदाताओं में अच्छी खासी जदोजहद थी. लोकप्रियता स्वभाविकता सहित कई मापदंडों पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे. कमी इसकी सिर्फ इतनी थी कि महागठबंधन के स्थानीय दिग्गज किसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं. सारे समीकरण तहस नहस हो चुके थे. कुछ दिन पहले तक राजद उम्मीदवार के रूप में मोहनियां से चुनाव लड़ चुके निरंजन राम जगदबाबु के प्रिय पात्रों में से थे. जो अब उनके बेटे सुधाकर के प्रिय पात्र हो गए. यहां बताते चलें कि सुधाकर सिंह बीजेपी नेता हैं. जो रामगढ़ विधान सभा से चुनाव लड़ चुके हैं. अगले चुनाव की तैयारी में हैं. सुधाकर मोहनियां में बीजेपी का चुनाव अभियान रथ भी हाक रहे थे. लेकिन जगदबाबु पूरे चुनाव के दौरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे. यहां तक की महागठबंधन के दो नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के चुनावी मंच पर भी नहीं दिखे. जिसको लेकर कयास बाजियों के दौर तेज थे. उधर महागठबंधन की एक और मजबूत नेत्री मीरा कुमार से कई संपर्क के बाद जब वे चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची तो सबके मन में एक बात चलने लगी कि यह सब कुछ हाल ही में भाजपा प्रत्याशी छेदी पासवान से मिली हार के कारण हो रहा है.

क्योंकि महागठबंधन प्रत्याशी चंद्रशेखर पासवान के सर पर छेदी पासवान का भतीजा होने का बड़ा लेबल था. ऐसा हो भी क्यों नहीं चंद्रशेखर पासवान ने लोकसभा चुनाव में छेदी पासवान के लिए दिन रात एक कर रखा था. जिसका पूरा नुकसान चंद्रशेखर पासवान को झेलना पड़ा. उल्टे लाभ भाजपा प्रत्याशी निरंजन राम को मिला. जो छेदी पासवान के विरोधी नेताओं और क्षेत्र में होने वाले विरोध का श्रेय ले उडे. जातिय अधार पर भी भाजपा के मतदाताओं की संख्या ज्यादा मानी जा रही थी. लेकिन जिस तरह से रविदास मतों के बाद कुशवाहा मतों पर श्री भगवान कुशवाहा, महाबली सिंह, पीके सिन्हा, राजपुत मतदाताओं पर वशिष्ठ नारायण सिंह, सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह, विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ने प्रयास किया. इसका उल्लेखित प्रतिफल नहीं मिला. यहां तक की महागठबंधन के आधार पर गत मतों वाले मतदान केन्द्रों पर मिली हार ने सबको सकते में डाल दिया. वैसे पिछली बार जदयू को मिले 36 हजार मत के बदले महागठबंधन प्रत्याशी को लगभग 42 हजार मत मिले थे. लेकिन भाजपा प्रत्याशी को 60 हजार से ज्यादा मत मिलने के कारण हार का अंतर ज्यादा दिखा. वैसे कहा तो यह भी जाता है कि पूरे चुनाव अभियान में महागठबंधन के स्थानीय क्षत्रप जिसमें कांग्रेस, जदयू और राजद तीनो दल शामिल हैं. दिल खोलकर प्रत्यासी का साथ नहीं दिए.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

रिलायंस सीमेंट की लॉचिंग

रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने होटल मौर्या में रिलायंस सीमेंट लांच किया. लॉचिंग रिलायंस सीमेंट के सीएमओ अतुल देसाई ने की. उन्होंने कहा कि लगभग 14 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल खपत के साथ बिहार सबसे ज्यादा सीमेंट की खपत करने वाले राज्यों में है. सीमेंट के क्षेत्र में हम नए हैं, लेकिन भारत की टॉप थ्री कंपनियों में से एक रिलायंस सीमेंट कंपनी बनेगी. आने वाले दिनों में रिलायंस सीमेंट भारत के हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी. एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट सह मार्केटिंग हेड राजेश शारदा ने बताया कि रिलायंस सीमेंट दूसरे सीमेंट से तेज सेट होता है और इसमें धूल न के बराबर होती है और इसकी पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि सीलन नहीं घुसने देता है. ग्राहक अपने स्मार्टफोन से इसक्यू आर कोड को स्कैन कर प्रोडक्ट की विशेषताओं पर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. इस मौके पर रीजनल सेल्स हेड अभय वर्मा आदि उपस्थित थे.

– निक्की

मारवाड़ी महिला समिति की बैठक

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी शहर के होटल सीतायन के सभागार में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की प्रांतीय बैठक हुई. सीतामढ़ी शाखा की अध्यक्ष सरिता सर्राफ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन पुष्पा लोहिया ने की. धार्मिक चर्चाओं के बीच संपन्न बैठक में समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना गुप्ता, नव निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष लता खेतान, सचिव मीना मोतानी, प्रो ज्योति सुंदरका, सुनीता सिकारिया, अल्का अग्रवाल, आशा खेमका, रीतु सर्राफ, वीणा सरावगी, अनु सर्राफ, अर्चना सर्राफ, रजनी हिसारिया, गायत्री अग्रवाल, मीनु अग्रवाल, सुमन लक्कड़, मधु शर्मा, सुनीता सर्राफ, मीना छापोलिया, तारा खेमका, जुली सर्राफ, सविता व्यास, अर्चना सर्राफ व श्वेता समेत अन्य सदस्य मौजूद थी. धन्यवाद ज्ञापन अनु सर्रा ने की.

– विम्मी

पूजा-अर्चना

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में पिछले 30 सालों से अनंत चतुर्थी के अवसर पर वृहद पुजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस साल भी सोनबरसा बाजार समेत रोहुआ, विशनपुर व बसदपुर गांव में आनंद कंद भगवान का प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा की. प्रति वर्ष पूजा के मौके पर दो दिवसीय मेला का भी आयोजन किया जाता है. पंडित बैजू झा के मार्ग दर्शन में आयोजित पुजनोत्सव में संघ के अध्यक्ष रवींद्र महतो, राम ईश्वर महतो, मुन्ना यादव, रघुवीर महतो, श्यामबाबू गुप्ता व संजय कुमार समेत अन्य ने सराहनीय योगदान दिया.

– अमरनाथ

ओभर ब्रीज निर्माण आवश्यक

भारत-नेपाल सीमा पर मौजूद बैरगनिया स्टेशन पर रेल ओभर ब्रीज निर्माण की आवश्यकता है. इस संबंध में रेल यात्री संघ के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर को दर्जनों आवेदन देकर समस्या निदान कराने का आग्रह किया, लेकिन अब तक इस दिशा में पहल नहीं की जा सकी है. बताया जाता है कि उक्त मार्ग से प्रतिदिन सैकडों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अक्सर मालगाड़ी के आवागमन की बजह से लोगों को जान जोखिम में डाल कर यात्रा करने की विवशता बनी रहती है. खास कर स्कूली बच्चों के लिए आवागमन की समस्या गंभीर बनी है.

– विनोद

स्मृति दिवस मनाया

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी स्थित प्रजापिता बह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सेवा केंद्र में दादी प्रकाशमणी की स्मृति दिवस मनायी गई. डॉ रेणु चटर्जी के आवासीय सेवा केंद्र में विश्व शांति दिवस के रूप में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर संचालिका वन्दना बहन, रीना बहन, डॉ रेणु चटर्जी, राम एकबाल भाई, प्रो डॉ विजय कुमार व डॉ वीणा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.

– ब्रजेश

बैडमिंटन खिलाडी का स्वागत

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जीतन राम माझी व खेल मंत्री विनय बिहारी से सम्मानित होकर पटना से लौटे अंतरराष्ट्रीय पारा बैडमिंटन खिलाडी विक्रम कुमार का राजबाग युवा संस्थान, खेल संघ पुपरी व आम नागरिकों ने भव्य स्वागत किया. पूर्व मुखिया राम स्नेही पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में षिवाचंद्र मिश्र, राज कुमार मंडल, अरविंद कुमार चौधरी, अरविंद कुमार अमित, मो शाकिर हुसैन, मिथिला बिहारी मिश्र समेत अन्य ने खेल प्रतिभा की प्रशंसा की. संस्थान के संयोजक अतुल कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में उमेश प्रसाद, रीता देवी, अंजनी कुमार सिंह, दिलीप राय, रवि वर्मा, विक्की पासवान, अमरेंद्र पांडेय, कुंदन कुमार, नेसार अहमद, राजन कुमार, नागेश्वर कुमार, मो शेर अली व आशीष कुमार समेत अन्य थे.

– गोविंद

निशा को दूसरा स्थान

ली अकादमी विद्यालय फारबिसगंज की दशम वर्ग की प्रतिभाशाली छात्रा निशा भारती ने राजधानी पटना में भविष्य के लिए कृषि में नव प्रवर्तन-संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित राज स्तरीय विज्ञान संगोष्ठि में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. सुश्री निशा ने इस संगोष्ठि में पूर्णियां प्रमंडल के प्रतिभागी के रूप में सहभागिता दी. सनद् रहे कि सुश्री निशा ने उससे पूर्व प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठि में प्रथम स्थान प्राप्त कर न सिर्फ अपने विद्यालय और अपने परिवार वरन् पूरे जिला को गौरवान्ति करने का कार्य किया है. उसकी इस सफलता से विद्यालय परिवार गदगद है. अपनी राज्य स्तरीय प्रतिभा में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर सुश्री निशा भारती ने चौथी दुनिया को बताया कि उसकी इस सफलता के पीछे यूं तो पूरे विद्यालय परिवार का सहयोग रहा किन्तु विशेषकर प्रधानाचार्य शिवनारायण दास की प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन की विशेष भूमिका रही है. उसने अपनी इस सफलता के पीछे शिक्षक प्रमोद कुमार दास, मनोज कुमार मेहता, ललित कुमार यादव, मनोज कुमार मिश्र, राजेश वाल्मिकी, प्रवीण कुमार, जयमाला देवी एवं लिपि भारती के विशेष प्रयास की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की. ■

–अजातशत्रु अग्रवाल

दिनकर की जयंती हो या पुण्य तिथि हर बार राष्ट्रकवि के आशियाने को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सजाने-संवारने के कवायद की घोषणा की जाती रही हैं और यह घोषणा विगत तीन दशक से की जा रही है. घोषणाओं का यह सिलसिला 01 नवम्बर 1986 से चल पड़ा.

बेगूसराय

आज भी अछूता है दिनकर का गांव

12 नवंबर 2008 को उर्वरक नगर बरौनी के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने चुनावी राजनीति में सिमरिया स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की थी. वर्ष 2008 में ही तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री वृषिण पटेल ने सिमरिया स्थित राष्ट्रकवि दिनकर उच्च विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई कराये जाने की बात कहीं थी.

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर

सुरेश चौहान

''तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा.
अपनी आग तेज रखने को, नाम तुम्हारा लेगा.''

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई उक्त पंक्ति आज उन्हीं पर पूरी तरह चरितार्थ हो रही है. राष्ट्रकवि दिनकर ने जिस समाज और राष्ट्र की कल्पना अपनी कविताओं में उकेरने की कोशिश की थी. उन्हीं दिनकर का गांव और जिला आज अछूता रह गया है. दिनकर की जयंती हो या पुण्य तिथि हर बार राष्ट्रकवि के आशियाने को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सजाने-संवारने की कवायद की घोषणा की जाती रही हैं और यह घोषणा विगत तीन दशक से की जा रही है. घोषणाओं का यह सिलसिला 01 नवम्बर 1986 से चल पड़ा. जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने सिमरिया में दिनकर पुस्तकालय का शिलान्यास करते हुए सिमरिया को आदर्श ग्राम बनाये जाने की घोषणा की थी. सच तो यह है कि इन तीन दशकों में सिमरिया के लोग आदर्श ग्राम जैसे शब्दों से वाकिफ नहीं हो पाये हैं. अमूमन अब, जब घोषणा के 28 वर्ष हो चुके हैं. सिमरिया अपने आप को आदर्श ग्राम कहलाने की स्थिति में नहीं है. दिनकर का यह गांव, जहां दसवीं पास करने के बाद लड़के व लड़कियों को जिला मुख्यालय की ओर टकटकी लगाना पड़ता है. जहां प्रसव के लिए निजी अस्पतालों पर ही आधारित होना पड़ता है. जहां बिजली के लिए लोगों का बरौनी थर्मल के राख से चेहरा और फेफड़ा काला होता जा रहा है. जहां रह-रहकर कल-कल करती गंगा उफान और दहाड़ मारती हो. जहां हर वक्त किसानों की जमीन पर ईंट चिमनियों के धुंए दूर आसामान तक बाजारवाद का पोषक बन मंडरा रहे हों. ऐसी स्थिति में आज भी सिमरिया के लोगों के समक्ष यह जटिल प्रश्न है कि आखिर कैसा होगा आदर्श ग्राम सिमरिया. आज जब हम पुन: 23 सितम्बर 2014 को दिनकर की 106वीं जयंती मना रहें होगें तो मुझे फिर से घोषणाओं की लम्बी श्रृंखला दिख रही है. बीतें दिनों 12 नवंबर 2008 को उर्वरक नगर बरौनी के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने चुनावी राजनीति में सिमरिया स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की थी. वर्ष 2008 में ही राज्य के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री वृषिण पटेल ने सिमरिया स्थित राष्ट्रकवि दिनकर उच्च विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई किये जाने की बात कहीं थी. लेकिन आजतक वह घोषणा सही रूप में सरजमीं पर नहीं उतर पायी. दिनकर के गर्भगृह को राष्ट्रीय धरोहर या साहित्य शोध स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया नहीं जा सका. यों तो 15 जनवरी 04 को बरौनी रिफाइनरी के तत्कालीन महाप्रबंधक आनंद कुमार ने दिनकर जन्मस्थली उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया था. अगले ही दिन आनंद कुमार ने दिनकर जन्मस्थली उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया था.

अगले ही दिन उन्नयन समिति के सचिव दिनेश सिंह की हत्या हो गई और सारे सपने बिखर गये. वर्ष 2005 में दिनकर जयंती समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि की हैसियत से पधारे पूर्व एयर वाईस मार्शल डॉ. विश्वमोहन तिवारी ने एक बार फिर जन्मस्थली के उन्नयन का मामला उठाया था. आखिर दिनकर के इस गर्भगृह को, जो हमारे लिए राष्ट्रीय स्मारक होता, दिनकर जी के छोटे पुत्र केदारनाथ सिंह ने अपने स्तर से एक लघु स्मारक के रूप में बना दिया. इस बीच विगत वर्ष 2012 में बरौनी रिफाइनरी के प्रयास से दिनकर पुस्तकालय, सिमरिया के आंगन में दिनकर स्मृति सभागार का निर्माण किया गया. इस सिमरिया को आदर्श ग्राम बनाये जाने के पीछे पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी इसे दिनकर शोध संस्थान स्थापित किये जाने की मांग की थी. वहीं दिनकर जन्मभूमि उन्नयन समिति के सदस्यों और वर्तमान में बीएचयू हिन्दी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत डॉ. रामाज्ञा शशिधर ने मिलकर एक कोरे कागज पर सिमरिया को साहित्यिक तीर्थ भूमि निर्माण की परिकल्पना की थी. जिसमें दिनकर द्वार का नव निर्माण, सिमरिया को मॉडल स्टेशन बनाने, गांव के अन्दर कई जगहों चौक-चौराहों पर दिनकर की प्रतिमा, शिलालेख लगाने, उच्च विद्यालयों को महाविद्यालय में बदलने, दिनकर शोध संस्थान खोलने एवं खेल का मैदान तैयार करने, सहित अन्य सपने बुने गये थे.

इसके अलावा सिमरिया के 'रूपनगर टीशन' पर 1942 के आंदोलन का प्रतीक 'मलैट्री गाछी' और रूपनगर टीशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग फिलवक्त बंद बस्ते में पड़ी हुई है. शायद इन्हीं उपेक्षाओं पर द्रवित होकर कवि ने लिखा

''कहां सिमरिया घाट, कहां दिल्ली का दूर नगर है.
मानचित्र पर ढूंढो कविवर कहां तुम्हारा घर है.''

राष्ट्रकवि दिनकर की एक मात्र आदमकद प्रतिमा एन.एच. 31 के जीरोमाईल पर अवस्थित है. जनपद के साहित्यप्रेमियों ने तत्कालीन जिला पदाधिकारी विमल कीर्ति सिंह के सौजन्य से 24 अप्रैल 1997 को तत्कालीन राज्यपाल एआर किदवई के द्वारा इस आदमकद प्रतिमा को स्थापित किया था. दिनकर ने एक जगह स्वयं के बारे में लिखा-

''मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं.''

आज वही सूर्य, वहीं दिनकर, बिहार सरकार, रिफाइनरी प्रशासन एवं साहित्यिक संस्थाओं की इदासीनता का दंश झेल रहे हैं. आखिर क्यों कोई दिनकर के लिए करे-धरे ? दिनकर तो राष्ट्र के लिये जिया. राष्ट्र उन्हें आखिर क्या दे सकता है ? जब-जब सत्ता के लोगों को दिनकर की जरूरत पड़ती है. वे दिनकर का नाम लेते रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिनकर का पुस्तैनी घर

गुरु वन्दना प्रस्तुत करती छात्राएं.

जिला माध्यमिक शिक्षक संघ, बेगूसराय द्वारा दिनकर भवन में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस व सम्मान समारोह. संघ के जिलाध्यक्ष उमानन्द चौधरी ने अध्यक्षता एवं राजेन्द्र नारायण सिंह ने मंच संचालन किया. स्थानीय सांसद भोला सिंह, जिला पदाधिकारी, सीमा त्रिपाठी, जिला शिक्षा पदाधिकारी रतीश कुमार झा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पूर्व प्राचार्य भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, सचिव सुधाकर राय, शिक्षक नेता डॉ. सुरेश प्रसाद राय, डीडीसी, डॉ. कौशल ने समवेत रूप से मंगलदीप प्रज्वलित किया. सचिव सुधाकर राय ने स्वागत भाषण, एमआरजेडी इन्टर कालेज की छात्राओं ने स्वागत गान एवं गुरु वन्दना प्रस्तुत किया. जिला पदाधिकारी ने अपने सम्बोधन में शिक्षकों की महत्व-पूर्ण भूमिका उनकी स्थिति एवं नियोजन की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा जिला प्रशासन का मुखौटा होता है. शिक्षकों की पहुंच जन-जन तक होती है. शिक्षकों की सफलता का मापदंड होता है उनके शिष्यों द्वारा सफलता के उच्चतम मापदंड को छू लेना. इस अवसर पर जिला माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत हुए जिले के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों सुधाकर राय, सैयद मजाहिर हुसैन, श्रीमती कुमुद कुमारी, हरेराम महतो, उमर सिंह, सच्चिदानन्द पाठक सहित 49 को शॉल एवं माला भेंटकर सम्मानित किया गया.■

दिनकर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार

वर्ष 2014 के लिए डॉ. सत्येन्द्र अरुण को दिनकर राष्ट्रीय सम्मान एवं डॉ. श्रीमती मृदुला झा तथा स्व. शिवनन्द सिंह को दिनकर जनपदीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाएगा. दिनकर सम्मान समारोह समिति ने चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए अनुशंसित साहित्यकारों के नामों का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है. दिनकर राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करनेवाले को दस हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह एवं शॉल प्रदान किया जाता है जबकि जनपदीय पुरस्कार प्राप्त करनेवाले को पांच हजार रूपये, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं शॉल प्रदान किया जाता है. दिनकर सम्मान समारोह समिति के महासचिव जनार्दन प्रसाद सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के सम्मान में वर्ष 1993 से इन पुरस्कारों की शुरुआत की गयी है. दिनकर की 106वीं जन्मतिथि 23 सितम्बर 2014 को दिनकर भवन बेगूसराय में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. वर्ष 1993 से गतवर्ष तक राष्ट्र एवं बेगूसराय जनपद के नामचीन 20-20 साहित्यकार इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं. ■

दिनकर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार

वर्ष	राष्ट्रीय सम्मान	जनपदीय सम्मान
1993	डॉ. भगवती शरण मिश्र	अरुण प्रकाश
1994	डॉ. मैनेजर पांडेय	डॉ. आनन्दनारायण शर्मा
1995	श्री आरसी प्रसाद सिंह	कुमुद विद्यालंकार
1996	डॉ. विजेन्द्र नारायण सिंह	कीर्ति नारायण मिश्र
1997	बाबा नागार्जुन	लक्ष्मी नारायण शर्मा
1998	जानकीवल्लभ शास्त्री	फजलुर्रहमान हाशमी
1999	डॉ. विष्णु किशोर झा	प्रो. उमाकान्त राय
2000	डॉ. प्रभु नारायण विद्यार्थी	डॉ. सीताराम सिंह
2001	श्री रामदयाल पांडेय	डॉ. जगदीश चन्द्र मिश्र
2002	श्रीमती उषा किरण खान	डॉ. सुकन पासवान
2003	डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव	डॉ. दिवाकर
2004	डॉ. नन्दकिशोर नवल	प्रदीप बिहारी
2005	डॉ. हरिवंश तरुण	अशांत भोला
2006	अरुण कमल	चन्द्रशेखर भारद्वाज
2007	डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र	लक्ष्मीनारायण सिंह
2008	विभूति आनंद	वेंकटेश्वर प्रसाद
2009	डॉ. परमेश्वर गोयल	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद
2010	स्थगित	स्थगित
2011	डॉ. प्रमोद कुमार सिंह	रामेश्वर प्रशांत
2012	डॉ. खगेन्द्र ठाकुर	रामावतार 'अनुरागी'
2013	डॉ. प्रभाकर पाठक	कस्तूरी झा कोकिल

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

15 सितंबर–28 सितंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

राहुल गांधी के ख़िलाफ़ बढ़ता जनाक्रोश

पंकज सिंह

सच ही कहा गया है कि सियासत यूं तो आग का एक दरिया है और इस दरिया को किसी कस्ती के सहारे नहीं बल्कि खुद तैरकर ही पार किया जा सकता है. ऐसा ही वाकया अमेठी में देखने को मिल रहा है. जहां के सांसद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हैं. जीत के बाद भी राहुल गांधी को जनता के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कह सकते हैं कि अमेठी में राहुल के विरोध की लहर चल रही है. इसका सीधा कारण जनता व जमीनी कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि है. कांग्रेस संगठन एक ऐसा विशाल समुद्र है जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में राजनीतिक मगरमच्छ अपनी शरणस्थली बनाए हुए हैं. उन्हीं में से उनके ही नेता राष्ट्रीय स्तर से ब्लाक स्तर तक पुरजोर विरोध कर रहे हैं. अमेठी में जिस तरह राहुल गांधी के विरोध की लहर चल रही है, वह निकट भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. किसी तरह 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी दो बार अमेठी दौरे पर आए और यहां आने के बाद सड़क और बिजली को लेकर उनको लोगों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा. दोनों बार ही उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा. एक बार काले झण्डे दिखाकर तो दूसरी बार मुर्दाबाद के नारे लगाकर लोगों ने अविश्वास जताया. निश्चित ही विरोध का कारण अमेठी में विकास व जनसमस्याओं का निस्तारण न होना ही रहा है. कांग्रेस संगठन में ही दो भाग नजर आने लगे हैं. एक तो कांग्रेस के सत्ता में न होने से आंतरिक विरोध कर रहा है, तो दूसरे राहुल गांधी के कामों को देखने को लेकर हायतौबा मचाये हुए हैं. राहुल गांधी से लेकर कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जनसमस्याओं के निस्तारण को प्रमुखता न देकर अपनी–अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं. यही कारण है कि नाराज आम जनता कांग्रेस कार्यालय तक आकर अपना विरोध प्रकट कर चुकी है. जनता की मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी आदि पर कांग्रेस युवराज की गंभीरता न होने से आम जनता अब राहुल गांधी से किनारा करने लगी है. यही कारण रहा है कि जनता का अपना झुकाव भाजपा के पक्ष में दिखा. सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को जब अमेठी से रायबरेली की कमान सौंपी गई, तो आते ही उन्होंने संगठन को दो भागों में बांट दिया. जिसका एक भाग पूरी तरह असंतुष्ट व उदासीन हो गया तो दूसरा किसी तरह कांग्रेस को जिंदा रखने का प्रयास करने लगा. जिससे कार्यकर्ताओं के साथ–साथ आम जनता भी राहुल गांधी के विरोध में नारे बुलंद कर रही है. कांग्रेस से असंतुष्ट डा. संजय सिंह ने भी दूसरी पार्टी में संभावनाएं तलाश करना शुरू कर दिया था. तब निवर्तमान प्रतिनिधि चंद्रकांत द्विवेदी ने भविष्य के खतरे को भांपकर मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंचाया. फिर क्या था उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राज्यसभा भेज दिया गया. ऐसा कर कांग्रेस ने डा. संजय सिंह को तो मना लिया, लेकिन आम जनता को मनाने में बहुत कामयाब नहीं हो सकी. चुनावी दौरे पर आयी प्रियंका गांधी से एक अल्पसंख्यक महिला ने अपनी समस्या के समाधान की गुजारिश की, तो प्रियंका ने किशोरी लाल से समस्या के निदान की बात कही. इतना सुनते ही वह महिला भड़क गई और कहने लगी कि दीदी यह तो खुद ही दलाल है, यह हमारी समस्या क्या दूर करेगा. दूसरी घटना उसी दिन की है जब अमेठी से आए एक भुक्तभोगी ने प्रियंका से फरियाद की कि वह एचएएल कोरवा में संविदा पर कम पैसे पर काम करता है. जिससे उसका परिवार नहीं चल पा रहा है. अगर उसे नियमित कर दिया जाए, तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेगा. इस पर जब पुन: प्रियंका ने किशोरी से देख लेने की बात कहीं तो, उन्होंने तुरंत कहा मैडम मामला अमेठी का है इसे चंद्रप्रकाश के पास भेज दीजिए. इतना सुनते ही परेशान भुक्तभोगी बिफर उठा और कहा कि मैडम अगर आप नहीं करा सकती हैं, तो मै अपना काम मोदी जी से जाकर करवालूंगा. इतना सुनते ही वहां उपस्थित लोगों के कान खड़े हो गए. उस समय किशोरी व अन्य के साथ–साथ मैडम प्रियंका भी बिना उत्तर के नजर आईं. ऐसी घटनाएं तो बानगी मात्र हैं. अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का महज इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया कि विकास के नाम पर राहुल गांधी का सफर अमेठी के लिए सिफर ही रहा. राहुल द्वारा दी गई परियोजनाएं जैसे बी.एस.एफ यूनिट, होटल मैनेजमेंट कालेज, किसानों के लिये फुडपार्क, सुल्तानपुर–अमेठी–सलोन–ऊंचाहार रेल लाइन परियोजना आदि का शुभारंभ ही नहीं हो पाया. इतना ही नहीं अमेठी की सड़कों पर चलने से पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क. किसानों की मूलभूत समस्याएं बिजली, पानी, सड़क व चिकित्सा ही रही है, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह उन सभी सुविधाएं को पाने से मरहूम हैं. अमेठी क्षेत्र के दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि मुंशीगंज स्थित संजय गांधी चिकित्सालय में पहले कम धन में अधिक सुविधाएं मुहैया होती थी, लेकिन इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. जिससे गरीब व आम जनता संजय गांधी द्वारा स्थापित चिकित्सालय से कट गई. जब गरीब जनता को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वह इससे बहुत दिनों तक कैसे जुड़ी रह सकती हैं.

अमेठी में जमीन से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता इसलिये नाराज हैं कि उन्हें पार्टी में तव्वजो नहीं मिलती. जब भी सांसद राहुल गांधी दौरे पर आते हैं तो उनका काफिला किधर जाएगा यह किसी कार्यकर्ता को पता तक नहीं होता. पता होता है तो सिर्फ राहुल के ठीक नीचे वाले पदाधिकारियों को जो नीचे के जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास तक नहीं करते. राहुल के विरोध में उठ रहे स्वर शांत किये जा सकते हैं, लेकिन उसके लिये राहुल गांधी को स्वयं ब्लाक स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क करना होगा. हालांकि वर्तमान प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे के मृदभाषी व शालीन रवैये से जनता कांग्रेस से अभी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए राहुल को संगठन में अमूलचूक परिवर्तन करना होगा. साथ ही कांग्रेस कार्यालय को वर्षों से जमें मठाधीशों से भी छुटकारा दिलवाना होगा. जिससे कि जनता की समस्या इन तक पहुंचे और इसका निस्तारण हो सके. तभी संभव है अमेठी की जनता का पुन: गांधी नेहरू परिवार से जुड़े, नहीं तो यह दूरी बढ़ती जाएगी. अमेठी राहुल गांधी को चुनाव के समय से लेकर अब तक वहां के लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है. अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों को अपनी–अपनी सीटे गवानी पड़े, क्योंकि राहुल गांधी को जो विरोध उनके संसदीय क्षेत्र में झेलना पड़ रहा है, वह उनके के लिए खतरे घंटी है.

feedback@chauthiduniya.com

अमेठी में जमीन से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता इसलिये नाराज हैं कि उन्हें पार्टी में तव्वजो नहीं मिलती. जब भी सांसद राहुल गांधी दौरे पर आते हैं, तो उनका काफिला किधर जाएगा यह किसी कार्यकर्ता को पता तक नहीं होता. पता होता है तो सिर्फ राहुल के ठीक नीचे वाले पदाधिकारियों को जो नीचे के जमीनी कार्यकर्ताओं को जोइने का प्रयास तक नहीं करते. राहुल के विरोध में उठ रहे स्वर शांत किये जा सकते हैं, लेकिन उसके लिये राहुल गांधी को स्वयं ब्लाक स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क करना होगा.

गांधी परिवार के लिए खतरे की घंटी

पिछले करीब छ: दशकों से अमेठी व रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ बरकरार है. 1977 में आपातकाल के चलते विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ और इंदिरा गांधी को राजनरायन से पराजित होना पड़ा. फिर क्या था पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया. इसी चुनाव में कांग्रेस को अमेठी के साथ–साथ निकट संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी पराजय का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस के लिए बड़ा सदमा था. 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद कांग्रेस ने सहानुभूति का लाभ उठाया और बड़ी जीत दर्ज की. अमेठी संसदीय सीट पर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उसके 1981 से 1991 तक राजीव गांधी ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की. 1991 में राजीव गांधी की हत्या से गांधी परिवार सदमें में आ गया. फिर अमेठी की कमान कैप्टन सतीश शर्मा को सौंपा. कांग्रेस परिवार से दिल से जुड़ी अमेठी की जनता ने कैप्टन को अपना प्रतिनिधि चुना. कैप्टन 1991 से 1998 तक अमेठी की जनता की सेवा में रहे, लेकिन धीरे धीरे लगाव कम होता गया फिर क्षेत्रीय राजा डा. संजय सिंह भाजपा ने अमेठी सीट कांग्रेस से झटक तो लिया, लेकिन अमेठी की बहू बनकर सोनिया गांधी ने जोरदार वापसी की और सीट को पुन: कांग्रेस की झोली में डाल दिया. 2004 में कांग्रेस युवराज राहुल गांधी पहली बार अमेठी से संसद पहुंचे. राहुल गांधी के सांसद बनते ही अमेठी की संभावनाएं भी बड़ी हो गई. लोगों को लगा कि एक बार अमेठी भारत के नक्शे में चमकेगा. लेकिन जनता की स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल होती गयी. दस सालों तक अमेठी की जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम किया. लेकिन जिस तरह 2014 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत खतरे में पड़ी वह निश्चित ही अमेठी की जनता का गांधी –नेहरू परिवार से मोह भंग होने का संकेत करता है. किसी तरह राहुल ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उन्हें लगातार अमेठी की जनता व जमीनी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जो इनके निकट भविष्य के लिये खतरे का संकेत है.

बाढ़ की मार झेलती हर साल लाखों जिंदगियां

यूपी के तराई में तब बाढ़ बढ़ जाती है जब नेपाल में अपेक्षा से ज्यादा बारिश होती है और साथ ही इसके लिए प्रकृति का साम्राज्यवादी दोहन भी जिम्मेदार है. जहां तक यूपी सरकार का यह कहना कि बाढ़ के लिए नेपाल जिम्मेदार है, तो यह बहुत ही गैरजिम्मेदराना बयान है, क्योंकि नेपाल सरकार के पास न तो नीतियां है और न संसाधन. बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों का निर्माण तो यूपी सरकार को करना है. जब कभी किसी प्रकार की समस्या आती है, तो यूपी सरकार अपने हाथ को देखने के बजाए दूसरे को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से भागती है. पिछले एक दशक में नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के चलते छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ा गया है.

हिमांशु कुमार

14 अगस्त यानी आजादी की पूर्व संध्या पर जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मनाने की तैयारी में मशगूल था, तभी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के तकरीबन आधा दर्जन जिले अचानक आई बाढ़ में डूब गए. तराई का अस्तित्व बाढ़ रूपी तबाही की भीषण चपेट में आ गया. सरकार ने इस तबाही को पहले दैवीय आपदा कहकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब पानी का सैलाब सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनकर सामने खड़ा हो गया, तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार और नेपाल सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, लेकिन इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विधानसभा उप चुनाव होने हैं. इसी को देखते हुए प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव व उनके चाचा शिवपाल यादव ने बाढ़ से फैली तबाही से ग्रसित लोगों के लिए कुछ कार्य कर उनको अपने वोटों में बदलने के लिए लखनऊ से बाहर निकले और बाढ़ रूपी तबाही के इस सागर में सियासी टापू बनाने में जुट गए. वैसे तो यह नजारा इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (तराई) में हर सरकार ने देखा, लेकिन इस बार सियासत का यह नंगा नाच अपने चरम पर दिखा. शायद इसका कारण यह था, क्योंकि निघासन जिला लखीमपुर, बलहा जिला बहराइच की विधानसभा सीटें इसी बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र का हिस्सा हैं. बाढ़ की इस तबाही ने सैकड़ों गांवों को अपने जिलों की सीमा से काट कर दूसरे जिलों में ढकेलने का काम किया है. लखीमपुर के दर्जनों गांव बहराइच की जमीन पर और बहराइच के तमाम गांव बाराबंकी में मिला दिए. श्रावस्ती की सीमा और गोण्डा के सीमावर्ती गांवों के लोग लापता हो गए. सीतापुर के अंदपुर गांव बहराइच में चले गए और बहराइच के कई गांव शारदा, घाघरा नदी की बाढ़ में डूबते उतराते लखीमपुर, सीतापुर में घरों, मकानों के साथ-साथ हजारों, लाखों बीघें फसलें जलमग्न होकर गल गई.

वहीं सत्तारूढ़ पार्टी सहित सभी सियासी दल वोटों का गणित लगाने में मशगूल रहे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में वोटों की फसलों को कैसे अपने खलिहान में लाया जाए. जिला बहराइच के मिहीपुरवा निवासी तौफीक बताते हैं कि हम बाढ़ में तबाह हो गए और राजनेता हमारी तबाही का मजाक बना कर वोटों की राजनीति करने में लग गए. जिस दुकान से एक पाव लइया, एक बोतल मिट्टी का तेल (घासलेट) और तीन किलो राशन के साथ आरोप और आश्वासन बांटने के साथ-साथ सरकार इस तबाही का कारण पड़ोसी देश नेपाल को बताती है, क्योंकि बाढ़ का पानी नेपाली नदियों से ही आया, लेकिन अंदपुर (सीतापुर से कटकर बहराइच की सीमा में लग गया है) के महतिया यादव कहते हैं कि यह भ्रष्ट सियासत ही इस तबाही की असली जिम्मेदार है. इस तबाही से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद ही प्रयास करने चाहिए जिसके लिए इन सियासतदानों की जबान में ही इनकों जवाब देना होगा. इस त्रासदी को झेल रहे तराई के तेरह सौ गांव और मौत की मार झेल रहे सौकड़ों परिवार भी अपनी इस तबाही को भ्रष्ट सियासत को ही जिम्मेदार मानते हैं. क्या बाढ़ की इस तबाही के लिए नेपाल सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? या फिर प्रदेश सरकार की बाढ़ रोकने की नीतियां? इन सवालों का जवाब केंद्रीय जल आयोग अपनी रिपोर्ट में सबको झुठलाते हुए 14 अगस्त 2014 को नेपाल में बादल फटने की घटना को जिम्मेदार मानता है. केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त की देर रात नेपाल के चिसा पानी क्षेत्र में मात्र कुछ घण्टों में 500.8 मिमी. रिकार्ड वर्षा के साथ-साथ भालूबंद में 215 मिमी. बारिश से राप्ती नदी में उफान आ गया, जिससे नेपाली राप्ती नदी सहित भारत में घाघरा, शारदा सहित कई नदियों का जल स्तर इस कदर बढ़ गया जिसको उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के बैराज पानी के सैलाब को रोकने में नाकाम रहे. अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेपाल को जिम्मेदार माना, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि क्या यूपी के बैराज नेपाल चलाता है? इसका कारण लखीमपुर में नेपाल भी सुरक्षित रहे, तराई भी बची रहे आंदोलन की नेता एस रावत बताती हैं कि सरकारी विफलता कभी अपने बचाव के लिए दैवीय आपदा की चादर ओढ़ती है, तो कभी केंद्र सरकार की नाकामी की. इस इलाके के लाखों लोग इस बचकाने बयान और बाढ़ रोकने के 389 करोड़ रुपये के राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट का जवाब मांगने के लिए लखनऊ कूच की तैयारी में है. हम आपको यूपी के बैराजों की एक सूक्ष्म जानकारी देते है. यूपी बैराजों की बाढ़ रोकने की विफलता पर एक नजर डालते हुए 15 अगस्त की सुबह बहराइच के सरजू बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ यह पानी 1995 के छोड़े गए 1.19 लाख पानी से बहुत ज्यादा था. 1995 के बाद पहली बार सरजू बैराज की विफलता सामने आई. ऐसा ही हाल श्रावस्ती जिले के राप्ती बैराज का दिखा. 2006 में यहीं 1.35 लाख क्यूसेक पानी का रिकार्ड था जो इस बार 1.4 लाख क्यूसेक तक पानी रहा. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल सरजू और राप्ती बैराज से गुजरने वाले पानी को इस तबाही का जिम्मेदार बताते हैं. एक सरकार के इस दो बयानों यानी मुख्यमंत्री और उन्हीं की सरकार के एक प्रमुख सचिव के विरोधी बयानों के निहितार्थ क्या हैं? मतलब साफ है कि एक जगह बचकानी अवसरवादी सियासत है और दूसरी जगह सुरक्षित सच्चाई. आईये इस अवसरवादी बचकानी सियासत और सुरक्षित सच्चाई को नेपाल के आइने में देखा जाए. नेपाल की तराई के लोकप्रिय वामपंथी नेता मित्रलाल बताते है कि नेपाल में बारिश का पानी रोकने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. यूपी के तराई में तभी बाढ़ बढ जाती है जब नेपाल में अपेक्षा से ज्यादा बारिश होती है साथ ही इसके लिए प्रकृति का साम्राज्यवादी दोहन भी जिम्मेदार है. जहां तक यूपी सरकार का यह कहना कि बाढ़ के लिए नेपाल जिम्मेदार है, तो यह बहुत ही बचकाना बयान है, क्योंकि नेपाल सरकार के पास न तो नीतियां है और न संसाधन. बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों का निर्माण तो यूपी सरकार को करना है. जब कभी किसी प्रकार की समस्या आती है, तो यूपी सरकार अपने हाथ को देखने के बजाए नेपाल को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से भागती है. पिछले एक दशक में नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के चलते छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ा गया है. यहां पहाड़ी क्षेत्र की सियाली, राधा, वमनी और वनारा जैसी छोटी नदियों को यूपी की शारदा से जोड़ दिया गया है और यहां की दोंदा नदी को घाघरा से जोड़ दिया गया है. बस ठीक इसी बिंदु पर यूपी की सरकार बाढ़ तबाही पर उपजे जनाक्रोष को शांत करने के लिए कहती है कि तबाही इसलिए आयी, क्योंकि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है. लखीमपुर में तराई क्षेत्र में काम करने वाले किसान नेता राम कन्हैया और के.के. त्रिवेदी यूपी सरकार के ताजा बयान को नेपाल और भारत के बीच की मित्रता, अपनापन को खत्म करने की साजिश मानते हैं. एक नजर यूपी सरकार पर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ पर इसके ताजा गैर जिम्मेदाराना बयान के पीछे बाढ़ नियंत्रण पर इसकी क्या कमजोरियां है यह जानना जरूरी है. राज्य सरकार ने अपने बजट में वैसे तो बाढ़ नियंत्रण के लिए 389 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया है, लेकिन बहराइच में बाढ़ से बचाव के लिए बना 100 किमी लम्बा आदमपुर देव भी तटबंध हर साल रैटकोल और बढ़ते कटान के कारण कमजोर होता जा रहा है. जरवल कैरिंग बांध का यहीं हाल है. सूत्र बताते है कि 14 अगस्त को इसी रिंग बांध के कटने की सूचना सरकार के पास थी, लेकिन सरकार ने क्या उपाय किये ? इस पर पूरी सरकार चुप है, हां सरकार के ही बाढ़ खण्ड गोण्डा के अभियन्ता यू. पी. उपाध्याय का सरकार की चुप्पी के पीछे की सच्चाई सामने लाता है. उनका कहना है कि सरकार ने नया रिंग बांध बनाने और कटान रोकने के लिए धनराशि मुहैया ही नहीं कराई. सीतापुर के घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर कटान के लिए जो करोडों रुपये दिये गए उसमें भी व्यापक कमीशनखोरी के सरकार पर आरोप हैं और इसके चलते सीतापुर का पड़ोसी इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया. इसका कुप्रभाव लखीमपुर के श्रीनगर, वर्वाद नगर और आजाद नगर ने भी भोगा. जिसके तकरीबन पांच सौ से ज्यादा परिवार घर से बेघर हो गए.

घर बह गया बाढ़ में, राहत बंटी अखबार में

बाढ़ क्षेत्र लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच के बाढ़ पीड़ित आंदलन कर्मियों के हाथ में कराहती तख्तियों का यह नारा-घर बह गया बाढ़ में, राहत बंटी अखबार में, बाढ से निपटने की सरकारी कोशिशों की पोल खोलता है. आंदोलन के नेता और भाकपा (माले) के जिला कमेटी सदस्य राम कन्हैया कहते हैं कि इन तीन जिलों के 600 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आने से बिखर गए वहां का राशन, मिट्टी का तेल (घासलेट) और चीनी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आती है, कई माह की एक साथ कालाबाजारियों ने डकार ली. करोड़ों रुपयों का यह अनाज, मिट्टी का तेल (घासलेट) और चीनी कहां गई? स्थानीय प्रशासन इसका कोई समुचित जवाब नहीं दे रहा है. ऐसा ही हाल गोण्डा, श्रावस्ती का है. यहां तबाही क्षेत्र में काम करने वाले किसान नेता निर्मल रावत बताते है कि उनके क्षेत्र में लगभग 400 गांवों में परिवारों के बिखर जाने से राशन, मिट्टी का तेल (घासलेट) की जमकर काला बाजारी हुई. बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी राहत सामग्री तो यहां ऊंट के मुंह में जीरा है.

बाढ़ ने सब कुछ किया बर्बाद

छह दशक से भीषण बाढ़ त्रासदी ने लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर में कई तरह के तनावों व समस्याओं को जन्म दिया है. सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और रिश्तों में खटास आई है. कई तरीके के दमन बढ़े हैं. मसलन इन जिलों में कुछ नए गांन बस गए हैं. जिनकी बुनियाद में गहरा सांस्कृतिक, सामाजिक संकट है. बड़ी उम्र के अविवाहित स्त्री-पुरुषों की संख्या व्यापक स्तर पर बढ़ी है. इनकी शादी की इच्छा ने अनमेल विवाहों, दुल्हन खरीदने जैसी परम्पराओं को जन्म दिया है. कोई भी अपनी लड़की बाढ़ क्षेत्र में व्याहना नहीं चाहता है तो बाढ़ की तबाही में यहां की लड़की व्याहने का सपना बाढ़ में बह जाता है. इस संकट ने बाढ़ प्रभावित बिहार, पूर्वांचल से लड़कियां खरीदने, बेंचने के कारोबार को जन्म दिया है. इस इलाके के हर गांव में खरीदी गई बहुएं अपनी बेबसी छलकाती मिल जाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

खूनी संघर्ष का कारण बनती नदियां

बाढ़ कटान से नदियों की दिशा बदलने से उपजी लाखों एकड़ जमीन को लेकर भू-माफियाओं में खूनी संघर्ष यहां आम घटनाएं बनती जा रही है. हाल ही में 2 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा सीतापुर के रण्डाकोड़र की तीन हजार बीघे से ज्यादा जमीन पर छिड़ी खूनी जंग के निपटारे के लिए खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और मौके पर डीएम, एसपी को भेजना पड़ा. पिछले साल महमूदाबाद तहसील में ऐसी ही जमीन को लेकर हिंसक झड़पे हुई थी. महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसी जमीनों के रखरखाव, देखभाल के लिए कार्यरत सरकारी अमले के पास क्षेत्र में अपना कार्यालय नहीं है, जो बाढ़ से निपटने की सरकारी मंशा को जाहिर करता है.

यह जांच का विषय है कि हर साल बाढ़ में हजारों घर-परिवार व गांव बिखर जाते है. लोग जीवन यापन के लिए वहां से पलायन कर महानगरों की तरफ कूच करते हैं. जहां उनकी ऊर्जा का दोहन होता है वहीं वे खानाबदोश जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं और इसके विपरीत इसी बाढ़ कटान क्षेत्र के नेताओं के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की कोठियां राजधानी के गोमती नगर जैसे पॉश रिहायसी इलाका (जो पहले खुद ही बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था) में बनती चली जा रही है. शासन प्रशासन के उच्च ओहदेदारों की दोहरी भ्रष्ट नियत पर इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब राजधानी लखनऊ के गोमती नगर जैसे बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र को बाढ़ मुक्त कर राजधानी की सबसे अच्छी पॉश कालोनी में स्थापित किया जा सकता है तो लखीमपुर, गोण्डा, श्रावस्ती तथा सीतापुर के बेहटा, तम्बौर, सेइता, रेइसा, गुडियनपुरवा, लोनियनपुरवा को क्यों नही ? यह दोहरी सोंच सिर्फ इसलिए तो नहीं कि गोमती नगर जैसे पॉश कालोनियों में इस भ्रष्ट लोकतंत्र की वाह रहती है और लोनियनपुरवा, गोडियनपुरवा जैसे स्थानों में लोकतंत्र की आह. ■

सुमन विश्वविद्यालय जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा

रेनु शर्मा

राज्य के आंदोलनकारी सुमन जी के नाम पर खोला गया विश्वविद्यालय जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहा है. गढ़वाल विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद यहां के कॉलेजों की जरूरत को देखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी. लोगों का मानना है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बनने के बाद भी वह जरूरत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है. यह विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड तकनीकि विश्वविद्यालय की तर्ज पर चल पड़ा है, जो सिर्फ निजी कॉलेजों की दुकानदारी को बढ़ावा देने में जुट हुआ है. बड़ी बात यह है कि निजी कॉलेजों को संबद्धता देने में यूजीसी के मानकों को ताक पर रखा जा रहा है. इस विश्वविद्यालय ने अब तक सिर्फ मैदानी क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे निजी कॉलेजों को संबद्धता देने में ही दिलचस्पी दिखायी है. निजी कॉलेजों को संबद्धता देने में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश विवि के शासनादेश व उत्तराखंड के शासनादेश को भी ताक पर रख दिया है. श्री देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा मैदानी क्षेत्रों के निजी कॉलेजों को जिस तर्ज पर मान्यता दी जा रही है. इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं. वर्तमान में श्री देव सुमन विवि से 28 निजी बीएड कालेज संबद्ध हैं. उक्त कॉलेज की संबद्धता के दौरान सभी नियमों को दर किनार किया गया है. इनमें से आधा दर्जन कॉलेज ऐसे हैं, जिनके पास गढ़वाल विश्वविद्यालय से भी बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता है. इन कॉलेजों ने पुराने स्टाफ व इसी भवन पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से भी मान्यता ले रखी है. जिसका प्रयोग गढ़वाल विवि से मान्यता प्राप्त करने में किया गया था. नियम के तहत उक्त कॉलेजों को नए विवि से मान्यता के लिए नए भवन व नए स्टाफ की भर्ती करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया. इतना ही नहीं वर्तमान में 20 अन्य कॉलेज श्री देव सुमन विवि से संबद्ध हैं. उनमें से अधिकांश कॉलेज मैदानी जनपदों में ही संचालित हो रहे हैं. इनता ही नहीं उक्त 20 कॉलेजों में से एक दर्जन से अधिक तो हरिद्वार जनपद में ही चल रहे हैं, जिससे विवि की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं. मजेदार बात तो यह है कि उक्त कालेजों को संबद्धता देने में विवि ने यूजीसी व उत्तराखंड उच्च शिक्षा अधिनियम व उत्तरप्रदेश अधिनियम को भी नजरअंदाज किया है. उच्च शिक्षा शासनादेश के अनुसार किसी भी निजी कालेज को मान्यता देने से पूर्व इसका औचित्य निर्धारण किया जाता है. जिस स्थान पर नया महाविद्यालय, संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है. वहां औचित्य निर्धारण के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या यहां कालेज की आवश्यकता है या नहीं. विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय की जांच कमेटी ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर महज मान्यता देने का कार्य किया है, जिससे न सिर्फ विश्वविद्यालय की कमेटी बल्कि विश्वविद्यालय की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. इतना ही नहीं शिक्षा के जानकारों की मानें तो विवि की स्थापना के पीछे उत्तराखंड तकनीकि विवि में चल रहा खेल प्रमुख था. श्री देव सुमन विवि से भी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की तर्ज पर चल पड़ा विवि सिर्फ मैदानी क्षेत्र में खुल रहे निजी कालेजों को संबद्धता इठे सवाल मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद गोपेश्वर डिग्री कालेज में विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने के लिए श्री देव सुमन विवि द्वारा प्रयास नहीं किया गया. पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ सेलाकुई व अन्य मैदानी क्षेत्रों में ही विवि द्वारा भवन की तलाश की जा रही है. पर्वतीय क्षेत्रों में निजी कालेजों की संबद्धता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं.

> “*जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई है वह हरिद्वार जनपद में अधिक हैं. जहां तक नियमों का सवाल है, तो हम यूजीसी व उत्तराखंड शासनादेश के आधार पर ही संबंद्धता दे रहे हैं. महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक की नियुक्ति की जांच कमेटी द्वारा की जाती है. गड़बड़ी पर मिली शिकायतों कि जांच की जाएगी*
> *-डॉ. ए. के तिवारी, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन वि.वि.*”

मान्यता के लिए तय किए गए मानक

1-जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है इसके पास 15 किमी की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं. प्रस्तावित स्थान से इसकी दूरी का आकलन. 2-इस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित है? 3-क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने से पुराने महाविद्यालय की छात्र संख्या पर असर नहीं पड़ना चाहिए. 4-प्रस्तावित नए महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम छात्र उपलब्ध हो पायेंगे? 5-महाविद्यालय में निर्धारित अर्हत धारक शिक्षक नियुक्त किये गए हैं या नहीं ? 6-निजी कालेज में प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय कुलपति का अनुमोदन आवश्यक होगा या फिर उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत शिक्षक हों. ■

कार्बेट में ड्रोन के माध्यम से होगी निगरानी

राजकुमार शर्मा

जिम कार्बेट नेशनल पार्क की निगरानी 2015 से ड्रोन करते दिखाई देंगे. ये मानव रहित हवा में उड़ने वाले उपकरण (यूएवी-अनमैन्ड एरियर व्हीकल) ड्रोन कार्बेट नेशनल पार्क के ऊपर उड़ते हुए लगातार क्षेत्र का वीडियो फिल्म बनाते रहेंगे और फोटोग्राफ लेते रहेंगे, जो कि क्षेत्र की सुरक्षा, बाघों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित होगा. देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के बाघ विशेषज्ञ और डब्लूआईआई के यूएवी कार्यक्रम के संयोजक के. रमेश का कहना है कि हाल में ही डब्लूआईआई ने पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की अपनी पायलट परियोजना सफलता से पूरी की है. अब योजना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी इस योजना को लागू किया जाए और कार्बेटपार्क में भी बाघों व अन्यजीवों की ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाए. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी-एनटीसीए)इस परियोजना में डब्लूआईआई की मदद कर रहा है. 2008-09 में प्रदेश के वन विभाग ने भी हल्के विमानों से प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की हवाई निगरानी की योजना बनाई थी, वह परियोजना बजट हासिल न होने से परवान नहीं चढ़ सकी थी. रमेश का कहना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की ड्रोन के जरिए निगरानी का प्रस्ताव केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है और उम्मीद है कि अगले साल जनवरी तक मंत्रालय हरी झंडी दे देगा. इसके बाद ड्रोन कॉर्बेट में निगरानी करने के लिए लगाए जाएंगे. उनके अनुसार ड्रोन से निगरानी का फायदा यह है कि रात में भी जंगल की निगरानी हो सकती है, क्योंकि इनमें नाइट विजन कैमरा भी लगे होते हैं, यही नहीं वनकर्मियों की शिकारियों से अचानक सीधी भिंड़त से भी बचा जा सकता है और इन क्षेत्रों की निगरानी भी हो सकती है. जहां इंसान का जाना मुमकिन नहीं हो पाता वहां भी ड्रोन निगरानी की जा सकेगी. उत्तर प्रदेश से सटे कॉर्बेट नेशनल पार्क पर हमेशा अवैध वन्यजीव शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है. इसकी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां वन कर्मियों की नियमित गश्त को मुश्किल बना देती है. इस पार्क से रामगंगा, कोसी समेत बहुत सी छोटी-बड़ी नदियां गुजरती हैं, जो कि गश्त में बाधा डालती हैं. उनका का कहना है कि कम कीमत यानी कुछ एक लाख रुपये के ड्रोन लगाने से गश्त की लागत भी कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रोन कुछ मिनट में ही बहुत बड़े क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर सकेगा. उनका कहना है कि यह पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण साबित होता है. ऐसे में कार्बेट पार्क में यह लाभदायक साबित होगा. ड्रोन वन्यजीवों की गणना में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. डब्लूआईआई के बाघ विशेषज्ञ के रमेश का कहना है कि भारत में हालांकि वन्यजीवों की निगरानी के लिए ड्रोन पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं. आस्ट्रेलिया में इस तकनीक के जरिए वन्यजीव गणना तक की जा रही है. उनका कहना है कि बहुत से ऐसे वन्यजीवों की गणना बहुत कठिन कार्य है, जो विषम भौगिलक परिस्थितियों में रहते हैं और जहां इंसान का पहुंचना संभव नहीं हो पाता, ऐसे में यह काम ड्रोन के जरिए किया जा सकता है. उत्तराखंड इन दिनों पुरी तरह से वन्यजीवों के तस्करी के लिए जाना जाने वाला राज्य बन चुका है. सरकार के इस कदम से वन्यजीवों को सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे उनको बचाया जा सकता है. ■

अव्यवस्थाओं के बावजूद राजजात यात्रा सफलता पूर्वक संपन्न

राजकुमार शर्मा

हिमालयी शिखरों, बुग्यालों की देव यात्रा का महाकुंभ हिमालयी जनता के जिन्दादिली की मिसाल पेश कर सकुशल सम्पन्न हुआ. मंदाकिनी तथा रूपगंगा के किनारे बसे सुतोल गांव से गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र की देवडोलियों तथा छंतोलियों के साथ आए नंदा भक्त एक दूसरे से गले मिलकर अगले 12 सालों में फिर मिलने का वादा कर गए. सुतोल में देवडोलियों ने सभी नंदा भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य का शुभाशीष दिया. नंदा राजजात सुतोल गांव से विदा हुई, तो गढ़वाल तथा कुमाऊं से पहुंचे नंदा भक्तों की आंखें छलक उठीं. बीते 18 अगस्त से राजजात में शामिल लोग एक दूसरे से गले मिलकर राजजात के इस ऐतिहासिक क्षणों को याद कर खो से गए. इस मौके पर तमाम नंदा भक्त देवडोलियों से लिपट कर सुख-समृद्धि की मनौती भी मांगते रहे. देवडोलियां भी लोगों को आशीर्वाद देकर उनके सफल भविष्य को लेकर अपना शीश झुकाती रहीं. कुमाऊं के नैनीताल, रानीखेत, मरतोली, बदियाकोट, अल्मोड़ा, कोटभ्रामरी आदि क्षेत्रों से आए नंदा भक्तों की आंखें इस अवसर पर इस कदर छलक उठीं कि उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे. कई नंदा भक्त तो इस मौके पर इतने भावुक हुए कि वे अपने जज्बातों को नहीं रोक पाए. एक तरह से सुतोल गांव आस्था व अध्यात्म के साथ ही परस्पर मिलन की त्रिवेणी भी बन गया था. नंदा देवी का आशीर्वाद लेकर नंदा राजजात में शामिल नंदा भक्तों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की देवडोलियों और छंतोलियों के गण और पश्वा भी अपने-अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े.

इस मौके पर सुतोल तथा पेरी के ग्रामीण भी अपने जज्बातों को नहीं रोक पाए और कई बुजुर्ग महिलाएं तो इस मौके पर फफक-फफक कर रो पड़ीं. आस्था व विश्वास की इस रोमांचकारी यात्रा का सुखद सफर तय कर अब नंदा भक्त अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़े. इसी दौर में द्यो सिंह देवता भी अवतरित हुए और उन्होंने भी सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देकर परंपराओं के निर्वहन का वचन मांगा. पहाड़ की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों पर 20 दिन की नंदा राजजात कई तरह सवाल छोड़ गई है. चौदह साल बाद हुए इस आयोजन को लेकर लोगों की बेसब्री को यात्रा के हर पड़ाव में देखा गया. सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर किए गये इंतजाम भी दिखे, वे हर पड़ाव में उमड़े जनसैलाब के आगे नाकाफी साबित हुए. वेदिनी व इससे आगे के निर्जन पड़ावों में भी जिस तरह नंदा भक्त उमड़े, उसने पहले के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिये. इस महाआयोजन में सबसे बड़ी दिक्कत जो सभी ने महसूस की वह थी, संचार सुविधाओं का ध्वस्त होना. नौटी से निकलने के बाद 18 अगस्त को राजजात जैसे-जैसे आगे बढ़ी नंदाभक्तों की संख्या बढ़ती चली गई. भीड़ इतनी अधिक होती चली गई कि इस इलाके में मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया. मोबाइलों पर सिग्नल तो थे, लेकिन बात करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुलसारी के बाद तो यात्रियों का अनुमान लगा पाना भी कठिन था. इसके बाद थराली, देवाल, ग्वालदम, लोहाजंग व सवाड़ के मोबाइल टावरों की क्षमता चरमरा गई. माना जा रहा था कि यात्रा के आखिरी गांव वाण तक लोगों को घरों में रहने की जगह मिल जाएगी, व्यवस्था होने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका. आपस में सम्पर्क नहीं हो पाने से घरों में हजारों लोगों के लिए किए गये इंतजाम धरे के धरे रह गए. इसकी वजह से नंदा भक्तों को रिहायसी पड़ावों के आसपास भी जैसे-तैसे रातें गुजारनी पड़ी. सबसे बड़ी दिक्कत वाण में लोगों को झेलनी पड़ी. अनुमान था कि यहां करीब 70 हजार से एक लाख के बीच नंदाभक्त पहुंचे थे. इसमें से करीब 25 हजार के करीब लोगों को किसी तरह रात काटनी पड़ी. लोग इन घरों को ही नहीं खोज पाए जहां उन्होंने ठहरने के लिए पहले से व्यवसथा किया था. वेदिनी के बाद ही यात्रा के कठिन पड़ाव शुरू हुए. वहां सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से करीब 20 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वेदिनी पहुंचते ही शुरू हुई जोर की बारिश और तीन बार बज्रपात होने से लोग बुरी तरह घबरा गए और जिसे जो टैंट सामने दिखा उसी में घुसते चले गया. यहीं से अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया. इसके बाद के पड़ावों में प्रशासन को सबसे बड़ी दिक्कत शिलासमुद्र में हुई. यहां करीब चार हजार लोगों के ठहरने का इंतजाम था, नंदा राजजात का कार्यक्रम जारी होने के बाद से ही टूर आपरेटरों ने बड़ी संख्या में टूरिस्टों को इस ट्रैक पर बुला लिया था जो यात्रा से पहले ही शिलासमुद्र पहुंच कर प्रशासन की व्यवस्थाओं में जम गए. इसकी वजह से यात्रा के साथ गए करीब चार हजार लोगों को ठहराने में प्रशासन को पसीना बहाना पड़ा. यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों में हुई अफरा-तफरी का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि सरकार की ओर से छप रहे विज्ञापनों में यह कहा गया था कि सरकार की ओर पूरे इंतजाम हैं. इसका असर यह पड़ा कि हजारों लोग बिना इंतजामों के ही बुग्यालों की ओर चल पड़े. सरकार के मुखिया हरीश रावत ने हर स्थिति में यात्रा को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसे जन आस्था के सैलाब ने बौना सिद्ध कर दिया. करोड़ों की राशि खर्च करने बाद भी नंदा राजजात में अव्यवस्थाओं का आलम रहा है. पीडब्ल्यूडी को करीब 80 करोड़, पर्यटन विभाग को दिये गए 25 करोड़ के अलावा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 24 करोड़ की राशि कहां-कहां खर्च हुई राज्य सरकार को इसका जवाब ईमानदारी से देना चाहिए. हरिद्वार के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान यह बातें कहीं हैं. सरकार के मंत्री और इसके अपने विधायक ही सरकार को घेर रहे हैं. मुख्यमंत्री हरीश रावत रोजाना ही विवादों को सुलझाने में लगे हुए हैं,

राजजात के मार्गदर्शक चौसिंग्या खाडू को हेमकुंड से अनंत कैलाश की ओर रवाना कर दिया गया. मुख्य खाडू की विदाई से पहले इसे तिलक लगाया गया और मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक क्रियाएं पूरी की गई. इसके बाद खाडू की पीठ पर मां नंदा के श्रृंगार के आभूषण व अन्य सामान बांध कर अनंत कैलाश की ओर रवाना कर दिया गया. चौसिंग्या खाडू की विदाई के अवसर पर राजजात में शामिल हजारों आंखें छलक उठीं. रिमझिम बारिश और बर्फबारी भी खाडू की भावपूर्ण विदाई और राजजात के विसर्जन का गवाह बनी. पूरी यात्रा को सफल बनाने में सरकार के साथ ही बड़े सरकार भगवान की बराबर कृपा बनी रही बीते 18 अगस्त से साथ चल रहे राजजात यात्रा के पथ प्रदर्शक के रूप में लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक चौसिंग्या खाडू को फूल मालाओं के साथ श्रृंगार कर उसके पीठ पर फांचे को लाद दिया गया. इसमे नंदा भगवती के श्रृंगार, आभूषण, फल, फूल आदि डालकर चौसिंग्या खाडू को अनंत कैलाश के लिए विदा कर दिया गया. साथ में गए अन्य 5 खाडुओं की भी इसी तरह की पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच विदाई की गई. इसके साथ ही चौसिंग्या खाडू अनंत कैलाश की ओर निकल पड़ा. एक तरह से इस राजजात का विसर्जन हो गया. इस ऐतिहासिक क्षण के करीब 12 हजार लोग गवाह बने. मान्यता है कि यह चौसिंग्या खाडू कैलाश स्थित भगवान शंकर की कुटिया तक मां नंदा को भेजने कलेवा और मायके की अन्य सामग्री को साथ लेकर जाता है. इसके बाद देव डोलियां नंदा भक्तों के साथ वापसी के पड़ाव को रवाना हुईं. ■

feedback@chauthiduniya.com